LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, August 9, 2024 / Sravana 18, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, August 9, 2024 / Sravana 18, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBITUARY REFERENCES	**1**
REFERENCES RE: HOMAGE TO FREEDOM FIGHTERS & MARTYRS ON 82ND ANNIVERSARY OF 'QUIT INDIA MOVEMENT'	**2**
REFERENCE RE: FELICITATIONS TO INDIAN HOCKEY TEAM AND MR. NEERAJ CHOPRA ON WINNING MEDALS IN PARIS OLYMPICS	**2**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 261 – 271)	**2A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 272 – 280)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2991– 3220)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, August 9, 2024 / Sravana 18, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, August 9, 2024 / Sravana 18, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION		**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE		**281 - 88**
MESSAGES FROM RAJYA SABHA		**288**
BILLS INTRODUCED		**289 - 98**
(i)	**Banking Laws (Amendment) Bill**	**289 - 94**
(ii)	**Carriage of Goods by Sea Bill**	**295 - 96**
(iii)	**Bills of Lading Bill**	**296**
(iv)	**Railways (Amendment) Bill**	**297 - 98**
MOTION RE: THIRD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE		**299**
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE		**300 - 19 & 333 - 52**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID		**320 - 32**
	Shri Arun Kumar Sagar	**320**
	Shri Janardan Singh Sigriwal	**321**
	Dr. Rajesh Mishra	**321**
	Dr. Vinod Kumar Bind	**322**
	Shri Raju Bista	**322**
	Shri Rajkumar Chahar	**323**
	Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	**323**

Shri Ananta Nayak	**324**
Shri Vijay Baghel	**324**
Shri Ganesh Singh	**325**
Sushri Kangna Ranaut	**325**
Shri Jagdambika Pal	**326**
Shri Kanwar Singh Tanwar	**326**
Shri B. Manickam Tagore	**327**
Captain Viriato Fernandes	**327**
Shri Rajmohan Unnithan	**328**
Shri Varun Chaudhry	**328**
Shrimati Geniben Nagaji Thakor	**329**
Shri Babu Singh Kushwaha	**329**
Shri Neeraj Maurya	**330**
Shri T.M. Selvaganapathi	**330**
Shri Ravindra Dattaram Waikar	**331**
Shri Balashowry Vallabhaneni	**331**
Adv. Chandra Shekhar	**332**
Shri Rajesh Ranjan	**332**
MOTION RE: REFERENCE OF WAKF (AMENDMENT) BILL TO JOINT COMMITTEE	**353 - 55**
BHARATIYA VAYUYAN VIDHEYAK (Contd. -- Concluded)	**356 - 380**
Shri Kinjarapu Rammohan Naidu	**356 - 72**
Motion for consideration – Adopted	**373**
Consideration of clauses	**373 - 80**
Motion to Pass	**380**

BILLS INTRODUCED **381 - 95**

Intelligence Services (Powers and regulation) Bill **381**

Constitution (Amendment) Bill **381**
(Amendment of article 80, etc.)

Constitution (Amendment) Bill **382**
(Amendment of article 324, etc.)

Compulsory Military Training in Schools and **382**
Other Educational Institutions Bill

Visual Representation of Income Tax **382**
Collections Bill

Glucotest Strips (Regulation and Price Control) Bill **383**

Mahatma Gandhi National Rural Employment **383**
Guarantee (Amendment) Bill
(Amendment of section 3 and Schedule II).

ASHA Workers (Regularisation of Service and **384**
Other Benefits) Bill

Anganwadi Workers (Regularisation **384**
of Service and Welfare) Bill

Backward Areas Development Board Bill **385**

Ban on Entrance Examination in Professional **385**
Courses Bill

Overseas Workers (Welfare) Bill **385**

Quality Education (Enhancing Through Internship) Bill **386**

Solid Waste Management Bill 386

Special Financial Assistance to the State of Tamil Nadu Bill 387

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Seventh Schedule) 387

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 58) 388

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Seventh Schedule) 388

Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill (Insertion of new sections10A and 10B). 388

Food Safety and Standards (Amendment) Bill (Amendment of section 3, etc.) 389

Special Financial Assistance for Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains in the State of Tamil Nadu Bill 389

Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill (Insertion of new section 90A). 390

Compulsory Teaching of Sanskrit Language In Schools Bill 390

National Youth Commission Bill 391

Victims of Natural Lightning Disaster (Compensation) Bill 391

High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Palakkad) Bill 392

All India Institutes of Medical Sciences (Amendment) Bill (Insertion of new section 3A)	392
Promotion of Organic Farming Bill	393
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill (Insertion of new section 5A, etc.).	393
Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, (Amendment of section 2, etc.)	394
Airlines Passenger Services Authority Bill	394
Play Schools (Regulation) Bill	395
Orphans (Reservation of Posts in Government Establishments and Welfare) Bill	395
Rural Labour Welfare Fund Bill	395
COMMISION FOR REGULATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY (Inconclusive)	396 - 99
Motion for Consideration	396
Shri C.N. Annadurai	396 - 97
Dr. Nishikant Dubey (Speech not finished)	398 - 99
VALEDICTORY REFERENCE	400 - 401

(1100/CS/VR)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दु:ख के साथ सभा को हमारे तीन पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूँ।

श्री इकबाल अहमद सरदगी कर्नाटक के गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री सरदगी रेल संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति और गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य रहे हैं। वे कर्नाटक विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं।

श्री इकबाल अहमद सरदगी का निधन 79 वर्ष की आयु में 21 मई, 2024 को कर्नाटक के कलबुर्गी में हआ।

स्क्वाड्रन लीडर (सेवानिवृत्त) कमल चौधरी पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं लोक सभा के सदस्य रहे हैं।

श्री चौधरी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और रक्षा संबंधी समिति के सभापति रहे हैं। वे विभिन्न संसदीय समितियों के भी सदस्य रहे हैं।

स्क्वाड्रन लीडर (सेवानिवृत्त) कमल चौधरी का निधन 76 वर्ष की आयु में 25 जून, 2024 को दिल्ली में हुआ।

श्री रमेश राठौड़ तत्कालीन आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री राठौड़ सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति तथा कोयला और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे हैं। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा के भी सदस्य रहे हैं।

श्री रमेश राठौड़ का निधन 57 वर्ष की आयु में 29 जून, 2024 को आदिलाबाद में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

.....

भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि के विषय में उल्लेख

1103 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सम्पूर्ण देश 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 82वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिनांक 9 अगस्त, 1942 को आज के ही दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने के लिए पूरे देश को एकजुट होने का आह्वान किया था और देशवासियों को 'करो या मरो' का मंत्र दिया था।

'भारत छोड़ो आंदोलन' हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। इस आंदोलन में देश का प्रत्येक व्यक्ति, युवा, महिलाएं तथा हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर भागीदारी की और अन्याय तथा अत्याचार की शक्तियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति को रेखांकित किया।

इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिन आदर्शों और मूल्यों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन आदर्शों के प्रति स्वयं को पुन: समर्पित करने का संकल्प लेते हैं।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

.....

माननीय अध्यक्ष : ॐ शांतिः, ॐ शांतिः, ॐ शांतिः।

(1105/IND/SAN)

भारतीय हॉकी टीम और श्री नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलम्पिक्स में पदक जीतने पर बधाई

1105 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 8 अगस्त को पेरिस 2024 ओलम्पिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

कल ही भारत के श्री नीरज चोपड़ा जी ने पेरिस ओलम्पिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के पुरुष वर्ग में रजत पदक जीत कर भारतीय खेल जगत के लिए एक नया इतिहास रचा है। भारतीय हॉकी टीम और श्री नीरज चोपड़ा द्वारा लगातार दो ओलम्पिक खेलों में पदक जीतना बड़ी सफलता है जो निश्चित रूप से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से भारतीय हॉकी टीम और श्री नीरज चोपड़ा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने खिलाड़ियों को उनकी भावी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

प्रश्न 261, श्री गिरिधारी यादव

(प्रश्न 261)

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय की स्थापना का विषय केंद्रीय सूची में है। बिहार जैसे 13 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में मात्र एक हाई कोर्ट है और कोई बेंच भी नहीं है, जबकि इससे कम जनसंख्या वाले राज्यों में एक हाई कोर्ट और दो बेंच हैं। केंद्रीय सूची में पीठ की स्थापना करने का अधिकार यदि है तो क्या भारत सरकार बिहार के भागलपुर में या बिहार के किसी दूसरे इलाके में हाई कोर्ट या बेंच की स्थापना करने का विचार रखती है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना जसवंत सिंह कमीशन की रिक्मेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के तहत की जाती है। इसके अंतर्गत कंसर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व गवर्नर की सहमति से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कम्प्लीट प्रपोजल केंद्र सरकार को कंसिड्रेशन हेतु भिजवाया जाता है। जब कंसिड्रेशन हेतु प्रस्ताव आ जाता है तो बेंच हेतु आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह प्रक्रिया जसवंत सिंह कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा तय की गई है। माननीय सदस्य बिहार की बात कह रहे हैं, वर्तमान में भागलपुर या पूर्णिया पटना हाई कोर्ट की बेंच खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है।

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : अध्यक्ष जी, जब हाई कोर्ट और पीठ की स्थापना केंद्रीय सूची में है, न तो राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, तो क्यों कोई चीफ जस्टिस या गवर्नर करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में हाई कोर्ट की पीठ की स्थापना करे।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : प्रश्न यह है कि जब यह विषय केंद्रीय सूची में है तो गर्वनर या हाई कोर्ट को नहीं, बल्कि भारत सरकार को पीठ की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय सूची में 78 और 79 नम्बर पर भारत सरकार का अधिकार उल्लेखित है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी है कि देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है और जसवंत सिंह कमेटी की रिकमण्डेशन है। यह प्रक्रिया तय हुई है। जिस किसी भी हाई कोर्ट में, अगर इनके राज्य में हाई कोर्ट की कोई बेंच स्थापित की जानी है तो यह हाई कोर्ट का प्रस्ताव लाएं, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेकर आएं और गवर्नर की भी सहमति लाएं, उसके बाद विचार करने का विषय आएगा। एक प्रक्रिया तय है, लेकिन अभी विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदय, मैंने पहले भी रविशंकर जी को लंबी-चौड़ी चिट्ठी लिखी था। उसका आप अध्ययन कर लीजिए। आप लॉ कमिशन की 125वीं रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें स्पष्ट है। गांधी जी ने कहा है – Justice delayed is justice denied. इन दो इश्यू को आप देखिए। आप और राज्यपाल भी उसको मंगा सकते हैं। अन्य स्टेट में, आप ही की स्टेट में तीन, महाराष्ट्र में दो, मध्य प्रदेश में तीन, उत्तर प्रदेश में दो, जबकि यहां चार होनी चाहिए

(1110/RV/SNT)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदय, मेरा कहना है कि बिहार में एक पटना हाई कोर्ट है, जिसमें अभी तक लगभग 2,37,000 केसेज पेंडिंग हैं। अभी कुछ दिन पहले की स्थिति यह है कि पटना में वकीलों के रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहां वकील साहब नीचे बैठ रहे हैं।

महोदय, पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच का खुलना आज से लम्बित नहीं है। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, भागलपुर का जो इलाका है, वहां सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। वे पटना नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहां से पटना की बहुत दूरी है। इसके कारण उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता है। उसी तरह, बेतिया, छपरा, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर की स्थिति है। यहां भी एक बेंच की जरूरत है। इस तरह, बिहार में दो बेंच की जरूरत है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री जी ने बताया नहीं कि इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हाई कोर्ट प्रस्ताव भेजेगा?

माननीय मंत्री जी, आप यह बताइए और इसे पूरी तरह से क्लियर कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुन: माननीय सदस्य को यह चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशन्स, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ने कुछ प्रक्रियाएं तय कर दी हैं। उस प्रक्रिया के तहत नई बेंच स्थापित करने के विषय में संबंधित राज्य सरकार और हाई कोर्ट सभी पहलुओं पर विचार करके आपसी सहमति बनाएंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्य के मुख्य मंत्री और फिर गवर्नर, उनकी सहमति बनेगी और ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है, यही मैंने उनको कहा है।

महोदय, वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालयों की 25 प्रिंसिपल सीट्स कार्यरत हैं। इसके अलावा, कुल 15 बेंच, जिसमें 13 परमानेंट बेंच और 2 सर्किट बेंच कार्यरत हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीसा भारती जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती मीसा भारती (पाटलिपुत्र) : सर, क्या इसमें मेरा नाम है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार बैठे-बैठे बोलती हैं न, इसलिए आपका इसमें नाम लिखा गया है। बैठे-बैठे बोलने की जगह आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती मीसा भारती (पाटलिपुत्र) : अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि गिरिधारी जी ने और पप्पू यादव जी ने जो डिमांड की, वही डिमांड हम लोग भी कर रहे थे। हमारे दल के श्री अभय कुमार सिन्हा जी प्रश्न पूछना चाहते थे। माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं जे.डी.यू. के सांसद महोदय से कहूंगी कि वे अपने नेताओं से बात करें, माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी से बात करें और वहां से प्रपोजल भिजवाएं।

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछें। कृपया भाषण न दें।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती मीसा भारती (पाटलिपुत्र) : महोदय, अगर इस तरह का प्रपोजल वे नहीं करा सकते हैं तो सरकार से अपना समर्थन वापस लें और बिहार की जनता को धोखा देने का काम न करें।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, यह इनका प्रश्न नहीं है। इनका वही प्रश्न है, जो पहले दोनों माननीय सदस्यों ने पूछा और मैंने यह बताया कि अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा, हाई कोर्ट की सहमति आएगी, गवर्नर की सहमति आएगी, मुख्य मंत्री की सहमति आएगी, तो उसके बाद केन्द्र सरकार उस पर विचार करेगी।

(इति)

(प्रश्न 262)

माननीय अध्यक्ष : श्री तेजस्वी सूर्या।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रदीप पुरोहित।

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : स्पीकर सर, आपके जरिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दूसरी निचली कोर्ट्स में अपने राज्य की भाषा में बहस को शामिल करने की जो प्रक्रिया चल रही है तो क्या वह ओडिया भाषा में भी होगा?

महोदय, दूसरा, जो सर्किट बेंच की बात है, जसवंत सिंह कमीशन ने सिफारिश की थी कि ओडिशा के पश्चिमांचल में एक सर्किट बेंच की स्थापना की जाए। केन्द्र सरकार ने उसमें क्या निर्णय लिया है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में करने से संबंधित प्रावधान है। फिर भी, अनुच्छेद 348 में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्य के हाई कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। उसके तहत वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत राजस्थान हाई कोर्ट में वर्ष 1950 से, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में वर्ष 1969 से, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वर्ष 1971 से और बिहार हाई कोर्ट में वर्ष 1972 से हिन्दी का प्रयोग अधिकृत किया हुआ है।

SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): Hon Speaker Sir, Vanakkam. Tamil is the oldest language of the world. Tamil is also the oldest living Indian language. Tamil is a classical language. Our poet Puratchi Kavignar Bharathidasan says, "Tamil is like the elixir: and Tamil is equivalent to our life". I wish that Tamil language should be made the Court language of Madras High Court. This is a long pending demand. I want to know from Hon Minister that when will they make Tamil as the Court language of Madras High Court?

(1115/GG/AK)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि केंद्र के पास तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक राज्यों से क्रमश: मद्रास हाई कोर्ट में तमिल, गुजरात हाई कोर्ट में गुजराती,

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हिंदी, कोलकाता हाई कोर्ट में बंगाली और कर्नाटक हाई कोर्ट में कन्नड़ भाषा में हाई कोर्ट की कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों को कैबिनेट कमिटी, 1965 के निर्णय की अनुपालना में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझावों हेतु भेजा गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 16 अक्टूबर, 2012 के लैटर द्वारा सूचित किया कि 11 अक्टूबर, 2012 को फुल कोर्ट मीटिंग में इन प्रस्तावों को विचार-विमर्श के बाद स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी हम प्रयास में हैं कि भाषिणी के माध्यम से इसमें जितनी भी रीजनल लैंग्वेंज हैं, उनके निर्णयों का ट्रंसलेशन करवा सकें।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Thank you very much, Mr. Speaker Sir.

Article 348(1)(a) of the Constitution of India provides that the language of the Supreme Court and the High Courts will be in English. Article 348(2) proviso says that even though the language of some High Courts could be Hindi or some other regional language, the judgments, decrees, and orders will be in English. There is a logic to it, and the logic is that there should be a standardisation of authoritative text across the board.

1116 hours (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

Now, the Minister, in his answer, has referred to an initiative by the Supreme Court of India where the Supreme Court is using an Artificial Intelligence tool to translate judgments into various regional languages.

My question to the Minister is this. What is the integrity of that translation? Who will certify that the translation from the original judgement is correct? I am asking this primarily because the translation is not being done by the judge who has authored the judgement.

Even if you look at Section 7 of the Official Languages Act of India, which Mr. Minister you have referred to in your answer, it says that the only recognised authoritative text will be the text that has been translated into English and certified by the High Court.

So, my question is कि आपने अनुमति तो दे दी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें तर्जुमा होगा। तर्जुमा भी हो गया। अब अगर किसी वकील ने उसके बेसिस के ऊपर कोई दलील किसी अदालत में दी, यह कौन सर्टिफाई करेगा कि वह जो ट्रांस्लेटिड जजमेंट है, उसका जो न्यूएंस है, उसका जो टेनोर है, उसकी जो टांस्लेशन है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वह वही है, जो ऑरिजनल अंग्रेज़ी जजमेंट में जज के द्वारा लिखी गई थी, वह उसके बिल्कुल अनुरूप है? इसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा? इसकी इंटेग्रिटी के लिए कौन वॉच करेगा?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मनीष तिवारी जी ने महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ईज़ ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज़ ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा दे रही है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please listen to him.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : एक मिनट आप सुन तो लें। इसी न्यायिक सुगमता को ध्यान में रख कर टैक्नोलॉजी और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित टूल के द्वारा जूडिशल प्रोसिडिंग्स और जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांस्लेट किया जा रहा है। माननीय सदय ने पूछा है कि उसको कौन मॉनिट्रिंग कर रहा है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित भाषिणी एप तथा सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी सुवास के माध्यम से वर्तमान में अंग्रेजी जूडिशल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांस्लेट किया जा रहा है, जो इन्होंने भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट के मामले की स्थिति में डेली ऑर्डर, जजमेंट आदि की वास्तविक जानकारी को उच्चतम न्यायालय का मल्टीलिंग्वल एप छह भाषाओं, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलगु हैं, में उपलबध कराया जा रहा है। इसके आगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनरेबल जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता में एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंट असिस्टिड लीगल ट्रांस्लेशन एडवाइज़री कमिटी बनी हुई है। वह लगातार इसकी मॉनिट्रिंग कर रही है। उसके बाद ही आगे चीज़ों को बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद।

(इति)

(1120/UB/MY)

(Q. 263)

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, so many youths are recruited for the job by the false agencies. They are offering a high salary but, unfortunately, these youths are cheated. They are not getting the salary that was offered. Five youths from my constituency were recruited in Russian Army on the false promise of a job. The issue had been taken up with the External Affairs Ministry and all of them have been released and repatriated. It is concerning that the incident of fake recruitment in foreign countries on false promises are increasing. Many such incidents including recruitment of youths in Cambodia and Myanmar for cybercrime and slave jobs were reported recently. Such fake agencies are very active. The jobless youths are easily falling victim to such incidents. The Government has ordered an inquiry into such agencies targeting Indian youths.

I want to ask what are the findings of the inquiry and what action has been taken against the agencies. Has the same inquiry resulted in the arrest of any Indian citizens, recruitment agents or conspirators in false recruitments?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, we have total 91 cases so far of Indian nationals who were recruited into the Russian Army. Eight of them, unfortunately, have passed away. Fourteen of them have been discharged or in some manner have come back with our assistance. There are 69 Indian citizens who are awaiting release from the Russian Army.

1122 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, as my answer has also conveyed to the hon. Member, we take this issue very, very seriously. I have myself raised it numerous times with the Russian Foreign Minister, and when the Prime Minister was in Moscow last month, he raised it personally with President Putin, and he got President Putin's assurance that any Indian national who is in the service of the Russian Army will be discharged and released.

The problem is that the Russian authorities maintain that these Indian nationals entered into contracts for service with the Russian Army. We are not necessarily subscribing to that. I share the hon. Member's view. I think in many cases there are reasons to indicate that our nationals were misled, that they were being told that they were going for some other job, and that they were then deployed with the Russian Army.

Regarding the hon. Member's question, what action we have taken, because the main question pertains to people with the Russian Army, I would like to inform

the hon. Member through you that CBI has registered a criminal case against 19 individuals and entities. They have examined those 14 people who have returned from Russia. Sufficient evidence has surfaced against ten human traffickers whose identities we know.

(1125/SRG/CP)

During the investigation, two of the accused were arrested on 24th April and two more on 7th May. All the four accused are presently in judicial custody.

Sir, the hon. Member also referred to a different issue, which is the cyber trafficking of people who are being misled, taken to South East Asia and made to work on cyber scams, and related issues. Again, we take this very, very seriously. We have taken it up with all the Governments concerned at a political level. So far, 650 Indian nationals have been repatriated from Cambodia, 415 from Myanmar and 548 from Laos. So, as the hon. Member has noted, and the Government also appreciates the gravity of this issue, this is an issue for which we have to be very vigilant; we have to crack down very hard. So, I have also attached with the answer a list of cases State-wise for the last three years, what is the action taken report, what is the status of legal proceedings in those cases.

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, these youths are appointed without any training. How can these youths be recruited without any training? The respected Minister has given one answer. A total of 3,042 illegal agents have been notified on the portal till June 2024. I want to ask what action has been taken against these illegal agencies?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, there is a range of issues in this. The cases regarding Russia are in a different category. I would like the hon. Member to be aware, through you, that those cases are being probed by CBI. They are being investigated. The cases have been registered. As I said, people have been arrested and they will be prosecuted. We also have cases in respect of those who have been held for cyber crimes, who have been trafficked to Southeast Asia. They are a different category. In their cases too, we have asked the State Governments to initiate in many cases prosecution against agents where we have information about them.

There are a bulk of the cases, the number which the hon. Member referred to, where we have put on our portal recruiting agents who we have found to be in violation of the rules. What it does is that they will not be allowed to continue in this business, and wherever there is evidence of any criminality or any violation of the law, they will be prosecuted. In many cases, prosecution is underway.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Will the hon. Minister be kind enough to answer my specific question? He has accepted that there are 69 Indians who are stuck in Russia. Will the Indian Embassy in Russia ensure that these boys who are stuck at the Russia-Ukraine border are brought to Moscow? Eight have died, and there are two boys' dead bodies from Punjab and Haryana. The DNA tests have been done. These bodies have not been returned. No one knows about the whereabouts of one Kashmiri boy, Zahoor. As he knows, one Baba Vlogs in Dubai, Faisal Khan in Russia, Moin, Ramesh and Pushpri, are the main criminals sitting in Russia and one in Dubai, who are misguiding our youths. Will the government first cancel their passports, issue an LOC, and third, if the Russian Government is not taking us seriously, will this Government not purchase any Russian oil? Will they stop these Indian refiners from buying discounted oil from Russia?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I will give a set of very specific answers to the very specific questions of the hon. Member.

As I said, there are eight Indian nationals who unfortunately died while in service with the Russian Armed Forces.

(1130/RCP/KDS)

Sir, the mortal remains of four of them have been sent to India with the payment made by the Indian Community Welfare Fund. In one case from Haryana, the Russian Foreign Ministry has informed us about his death. They have sought a DNA test report to identify him. This has been sent to the Russian side. We are following it up. In one case relating to a person from Gujarat, the family wants cremation in Russia. The necessary authorisation from the family has been obtained. It has been sent to the Russian side. In a case from Punjab, the Russian side has requested for DNA sample. That DNA sample is being provided. Finally, in the case from Uttar Pradesh, the eighth case, the family has sent their wishes that the mortal remain should be brought back. We expect that it will be brought back.

Regarding the people who are involved in the trafficking, we will have to go by what the CBI inquiry has told us because that is evidence; that is what is legally permissible. We have 19 people, including some of the names that the hon. Member has referred to. In each case, the inquiries are going on. In many cases, the prosecution is going on. So, I can assure the hon. Member, through you, that we take this very, very seriously.

His last point is this. What is the status of discussions between us and the Russian Government? I think, it would be fair to say that the Prime Minister himself has taken up the matter with the Russian President and the Russian President has himself given an assurance. We should not jump the gun and say that the Russian are not serious on this matter. I think, it is important to hold the Russian Government to their word. It is most important for us. We are not here to score points or to enter into debates. We are here to get back those 69 people because the Indian citizens should not be serving in the Army of foreign countries.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने काफी डिटेल में जवाब दे दिया है।

… (व्यवधान)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Speaker Sir. Recently Telugu youth icon and our leader Shri Nara Lokesh Garu actively helped in the repatriation of Indians trapped abroad due to fraudulent job offers, including safely from the Middle East region with the assistance of our hon. Minister of External Affairs. We are all extremely thankful to you.

In the light of these incidents, what I would like to ask, through you, the hon. Minister is this. What specific measures is the Government taking to crack down on the immigration agents who actively participate in such fraudulent activities in India? Thank you very much.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, the bulk of the cyber-related trafficking cases or the highest number of cases are from Andhra Pradesh and to some extent from Telangana. So, I completely understand the hon. Member's concerns in this regard. If the hon. Members would look at the data we have provided, the majority of cases are from Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana. The bulk of the cases come from them. So, we have sought the cooperation of the State Government. It is an issue of national concern. This is not a political matter. This is a case where both the State Governments concerned and the Union Government, should work together. I can assure the hon. Member that wherever we find evidence of any infraction of the law, we will very vigorously prosecute the agents.

(ends)

(1135/MK/PS)

(प्रश्न 264)

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें बताया है कि संविधान के अनुच्छेद -171 के अनुसार राज्य सभा और विभिन्न राज्य के विधान परिषदों में … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि संविधान के हिसाब से विधान परिषद और राज्य सभा में आरक्षण लागू किया जाए। उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, यह बताया गया है। यह बात तो सही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आदरणीय सर संघ चालक मोहन जी भागवत ने कई बार कहा है … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से किसी का नाम नहीं लेते हैं।

माननीय सदस्य, आप नये आए हैं। जो इस सदन का सदस्य नहीं होता है, उसका नाम नहीं लेते हैं। आप इसको हटा दीजिएगा। आगे से आप समझ जाइए।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि आज भी देश में जाति और जनजाति के प्रति समाज में भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। इस समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करना उचित रहेगा। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन करके राज्य सभा और देश के विधान परिषदों में आरक्षण सुनिश्चित करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में एज-पर कांस्टिट्यूशन आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन, राज्य सभा में और जो विधान परिषद होती है, उसमें अभी संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं? जो बिना नाम बुलाये खड़े हो जाएंगे, उनको कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

… (व्यवधान)

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक पश्न है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो बिना नाम लिये खड़े हो जाएंगे, उनको मौका मिलेगा ही नहीं।

माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं?

… (व्यवधान)

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि अभी पिछले सप्ताह में माननीय उच्चतम न्यायालय में आरक्षण से संबंधित प्रकरण में कोटा के अंदर कोटा वर्गीकरण, क्रीमी लेयर का भी इसके संबंध में निर्णय दिया गया है, जिसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : अध्यक्ष महोदय, इससे इन जातियों में भारी रोष व्याप्त है। इसके बारे में इनकी सरकार में घटक दल का एक पक्ष भी अभी उच्चतम न्यायालय में गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न उसके संबंध में नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि sub-categorisation of castes के मामले में, जो पंजाब सरकार से चलते-चलते आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में आई है, उसमें ये जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, यह उनका ऑब्जर्वेशन है। वह डिसीजन का पार्ट नहीं है। ये समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश न करें।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, hon. Speaker, Sir.

Sir, reservation in the State Legislative Councils and Rajya Sabha is a very long-pending demand. The hon. Minister's reply was a technical one.

So, through you, I would like to know from the hon. Minister the approach of the Government for providing reservation in the Rajya Sabha as well as in the Legislative Councils.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि क्वैश्चन ऑवर ही टेक्निकल होता है। ये जो प्रश्न पूछते हैं, उसी का ही जवाब दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि आर्टिकल-80 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभा में प्रत्येक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में संसद सदस्यों को संबंधित राज्य की लेजिस्लेटिव असेम्बली के विधायकों द्वारा चुना जाता है और लोक सभा में डायरेक्ट चुनाव होता। डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट चुनाव में फर्क के कारण उस समय कांसिटट्यूएंट असेम्बली में भी चर्चा हुई थी। हम इसको इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी संविधान में इसका प्रावधान नहीं हैं। मैंने इनको यही कहा है।

(इति)

(Q.265)

SHRI K. GOPINATH (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker, Sir, what steps are proposed to be taken by the Government of India through the Ministry of Health and Family Welfare in association with such international regulatory bodies to address the regulatory issues pertaining to the veterinary medicines?

(1140/SMN/SJN)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, I have explained in my reply but I would like to explain again that worldwide there are three models of regulatory bodies that we follow for human as well as veterinary drugs and medicines. There are countries like USA, EU, Japan and New Zealand which follow a common regulatory body. Then, there are second categories of countries like the UK, like China, like Brazil, like Australia which have a separate regulatory body system, and there is this third category wherein the countries follow a model where they have a main national regulatory authority body and within which they have a dedicated veterinary division. So, India falls in that third model where we have one regulatory body and within which we have a separate dedicated division for veterinary drugs and medicines. That is how, we have the arrangement for regulation. In case of our country, that body is CDSCO which looks into the quality, safety and efficacy of the drugs, both human and veterinary, and it has a regulatory role in so far as the permission for the import, manufacture or clinical trials of any veterinary drug or human drug or vaccine is required.

HON. SPEAKER: Dr. M.K. Vishnu Prasad – not present.

Now, Dr. T. Sumathy.

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you very much hon. Speaker, Sir.

Last year, the NITI Aayog tabled its reports on telemedicine for livestock. It also has highlighted a shortage of approximately 41,000 veterinary institutions, veterinarians and thus, called for improving coverage *via* telemedicine which is the need of the hour. So, I would like to ask this to Madam, Minister, through you Sir. What measures has the Ministry or the Minister taken in this context for the regulation of telemedicine for livestock.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, this question pertains to separate regulatory authority for veterinary drugs and medicines. Telemedicine is not related to it.

(ends)

(Q.266)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, it is disappointing that this NDA Government has not made available the data. It does not have the data on the number of people who are disabled or who seek benefits from Ayushman Bharat Scheme. About 4-5 per cent of our country have some disabilities.

Through you, I would like to know whether the Government has got any special plans to make sure that everybody with disabilities is universally covered by this insurance scheme. Do they have any plans for giving any support for those caregivers? Will they pay for those caregivers?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: First of all, the Government has all the data in so far as our eligible beneficiary base is concerned. We are covering bottom 40 per cent population under this Scheme. This question pertains to disability. I would like to first apprise this House through you and the hon. Member. When we talk about the beneficiary base of PM-JAY, where do we derive the beneficiaries from? We derive it from the SECC data, we derive it from the RSBY; and we derive it from NFSA.

Sir, under SECC data, we have three criteria. One is the automatic allocation category; second is the deprivation criteria for the rural areas under which they fall under D-1, D-2, D-3 and D-4 categories. If you take D-4, that is specifically for the disabled. So, that criteria is for the disabled member and not for the able bodied adult member. So, the disabled members or the disabled persons under this SECC have been included in this PM-JAY scheme.

Also, Sir, under NFSA, we have a criterion under which the Antyodaya Anna Yojana households also specify that disability will be common inclusion criteria for the identification of priority households. The disabled persons, who are heading a household, which has no societal

support or an assured means of subsistence or the disabled person himself does not have a societal or assured means of subsistence, are also included under the PM-JAY. So, the disabled members are included in different ways under these schemes. But we do not maintain a central repository of only the disabled members but we have an overall figure which reflects how many people we are covering under the scheme.

Also, Sir, there are 13 States. I would like to apprise the hon. Member that there are 13 States which follow the universal health coverage. So, every member within that State, who is disabled also, is covered under the scheme, and I would like to add that we have a health benefit package under the PM-JAY. That package has been revised five times.

Sir, the new package of 2022 that we have includes 36 medical surgical packages across six medical specialities, which are aimed at helping the disabled persons, and as reported by the States, more than 95,000 admissions across 27 States have happened for the disabled persons. So, we very much take care of the disabled persons by way of the PM-JAY scheme but in a different way.

(1145/SMN/SPS)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): The question that I asked was, whether the support is given to the caregivers of disabled people. The Minister did not answer that.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): The question is about the caregivers. I would like to be very clear that the Ayushman Bharat Scheme takes care of the curative part, not the rehabilitatory part. So, as far as the caregivers are concerned or the NGOs are concerned, they are mostly in the area of rehabilitation. The Ayushman Bharat Scheme is for the curative part, and for the curative part, the Minister for State has given a very detailed answer

about the packages, about the issue and about the areas where we intervene and we give support to the people.

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab – not present.

Dr. Mallu Ravi.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, आप एक बार बैठिए। जब कभी नाम बोलते हैं, तभी प्रश्न पूछते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि आपका नाम नहीं होता है, तब भी खड़े हो जाते हैं। मल्लू रवि जी, मैं आपको कह रहा हूं।

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): Thank you very much for giving me time to ask this question.

I want to know from the hon. Minister whether there is any data available on the utilisation by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people under the Ayushman Bharat Scheme.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana, as I have already explained in my previous reply, we have different basis on which we select or identify the beneficiary. We do not maintain the separate data for SC/ST but if you go to the criteria that we have chosen under the PM-JAY in the rural areas as well as in the urban areas, in the rural areas, we have deprivation criteria and in the urban areas, we have occupation criteria, and also there are certain categories of automatic allocation.

Sir, I do not want to go into the details of every category. It will take time but mostly, it is the marginalised and vulnerable sections of the society who are also SC/STs who are benefited majorly under the scheme.

(ends)

(Q. 267)

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): May I say to the hon. Minister that there is a negative answer for all the first two queries about inclusion of the HPV vaccine in the immunisation programme. There is utter confusion between the federal States of the Union and the Central Government. You have innumerable number of letters being received from the Government of Rajasthan to you thanking you for including that. While I get an answer here saying that this is not a part of it.

(1150/SM/MM)

So, there has to be an explanation for it. Will you please kindly clear whether HPV vaccine is a part of it or not? Nearly Rs.400 core was given to Rajasthan. I am asking whether the logistic procurement programme will be initiated by the Government of India or the State should do it on its own.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: First of all, I would like to make the Member clear that as far as HPV Vaccination Programme is concerned, the status is like this. The National Immunization Technical Advisory Group of 2022 has recommended for HPV vaccination. The Government is actively considering it. There are logistic issues which have to be addressed.

The first issue is about the single and double dose vaccine. The indigenous vaccine, which we have prepared is a doble-dose vaccine and the vaccine, which is being supported by the external agencies is a single-dose vaccine.

Secondly, we have also to see the capacity to roll out the programme. As I said, the immunization programme itself is world's largest programme. For that, we have to see the capacity of the logistic part which the Government is actively considering.

There are States, which have taken initiatives on their own, which we accept and welcome. But as far as the Government of India is concerned, it is under our active consideration. Yes, this needs to be rolled out and we are actively considering it.

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): May I ask the hon. Minister one thing? Will you permit the States to do it on their own or are the States under any restriction not to do it till it is decided at the Government of India level?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: No Sir, we have not restricted any State. Sikkim is doing this vaccination programme. Punjab did it for a year and a half when they got the external support and then they stopped it. So, the States can do it on their own initiative. We have not stopped them. Yes, we have to roll out the programme because it is a national programme. It is a free of cost programme for every child. But for that, a cohort logistic system has to be developed and we are doing it.

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you, Sir, for the opportunity. I am really happy to know about the inclusion of HPV vaccine in immunization programme. I would like to ask the hon. Minister one thing through you.

There is a test called VILI test to identify cervical and breast cancer at the initial stages. It has been done free of cost in all the previous years. Earlier, there used to be an awareness programme about it through advertisement on radio etc. Now, it has been stopped over the years. Has the Government any plan to create awareness through advertisement etc. about VILI test?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: No, we have not stopped any programme of awareness. In fact, I would like to share with you that we are actively working on it. As far as the screening part is concerned, it has been rolled out. Here, I would like to share with you the figures of screening which we have done.

First of all, I would like to tell you that sexual transmission infection, development of abnormal cells, early marriage, child birth, multiple pregnancies, using oral contraceptives, tobacco smoking, immune cells separation etc. are the reasons for this.

If you see the NCD portal, you will find that 6,17,74,353 women have been screened; 76,652 women have been diagnosed with cervical cancer and 67,424 are being treated in the Government facilities.

I would like to also share with you that we have 1,73,000 Ayushman Arogya Mandirs where we have the screening facilities for diabetics, cervical cancer, HIV etc. All the necessary screenings are being done there. So, we have not stooped this. In fact, we have increased the screening. That is why, these figures have come up.

(ends)

(1155/YSH/RP)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 268.

श्री ए. राजा – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, the answer is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 269.

श्री वी सेल्वाराज – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज पूरे 20 क्वेश्चन्स होने दीजिए। मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। पूरे 20 क्वेश्चन्स होने वाले हैं।

श्री के सुब्बारायण – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 270.

आज पूरे 20 प्रश्न हो गए हैं।

(प्रश्न 270)

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज बजट भी इनहेंस हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ट्राइबल एरियाज़ में जहां सिकल सेल, एनीमिया और थैलासीमिया का ज्यादा प्रभाव है, उस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इनीशिएटिव लिया है, इसलिए भी मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बजट में ज्यादा राशि की जरूरत है? इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, तो जीडीपी 1.13 परसेंट इंक्रीज हुई है और उसको हम 1.35 परसेंट तक ले गए है। दूसरी बात यह है कि हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडीचर भी कम हुआ है। अगर उसे हम देखें तो वह वर्ष 2014-15 में 62 परसेंट था, वह आज 47.01 प्रतिशत हो गया है। अगर हम पर कैपिटा टोटल हेल्थ एक्सपेंडीचर देखें तो वर्ष 2014-15 में यह 3,826 था और वर्ष 2019-20 में वह 4,863 हो गया। इस तरह से यह 27 परसेंट इंक्रीज हुआ।

इस तरह से हम हेल्थ के बजट को इंक्रीज कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने सिकल सेल की बात की है तो सिकल सेल के एलिमिनेशन का प्रोग्राम प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2023 में शुरू किया था। हम बहुत तीव्र गति से उसकी एक्टिव स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ट्राइबल एरियाज़ में उसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और उसके इलाज के लिए सभी व्यवस्थाओं को माकूल किया गया है।

(इति)

(pp. 22-30)

Q. 271

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, will the hon. Minister provide details on the emergence and characteristics of KP.1 and KP.2 strains of the SARS-Co V-2 virus? How does this strain differ from previous variants and what measures are being taken to address its spread?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, there is a continuous surveillance programme which is going on. In that surveillance programme, if there is any change in the virus or if it is mutated, we see that. All this is being done by our agencies as far as the disease control programme is concerned. We are vigilant and regularly monitoring it. If there is any change because of that, we accordingly change our strategy.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, what steps are being taken by the Government to promote community awareness regarding this new COVID-19 strain and the importance of adherence to the respiratory hygiene? How is this awareness being spread among the general public?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: There is a regular programme – Information, Education, Communication Programme. This question is very relevant because one has to be very much aware of the changes which are taking place and for that our IEC programme is there. In that programme, community participation and community involvement are done at the grassroot level. Even in the Arogya Mandir, we communicate to the patients and to the vulnerable patients who are there. That is all we are doing.

(1200/RAJ/NKL)

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Hon. Speaker Sir, I would like to ask the hon. Minister what are the key research initiatives currently underway to understand the behavioural impact of the KP.1 and KP.2 strains. How is the Government supporting the research institutions in this regard?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, there is a regular process going on project-wise. There are many agencies where the research is going on. If I talk about the ICMR-NIV, this also takes care of it. We have the projects for taking care of these upcoming problems in the field of medical sector. So, this is also being taken care of accordingly.

(ends)

(प्रश्न काल समाप्त)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं करता हूं।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 3, श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी।

… (व्यवधान)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 119(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अंतरर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19 के अंतर्गत अंतरर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.10आर(3)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.395(2)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 06 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.5(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3058(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.456(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत तदर्थ छूट आदेश 2024 का संख्यांक 5 दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसके द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा लाइबहेर हैवी लिफ्ट क्रॉलर क्रेन (मॉडल:एलआर 1350/1, क्रम सं. 074113) की एक इकाई के पुन: आयात हेतु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के निबंधनों के अंतर्गत सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences & Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences & Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2022-2023.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2022-2023.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, for the year 2022-2023.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2022-2023 together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2022-2023.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English Version) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi for the year 2022-2023.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(12) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited, Goa, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited, Goa, for the year 2022-2023 and alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of HLL Infratech Limited (HITES), Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the HLL Infratech Limited (HITES), Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023, and alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the HLL Biotech Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023

(ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Madras Fertilizers Limited, Chennai for the years 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Madras Fertilizers Limited, Chennai, for the years 2021-2022 and 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai for the years 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the years 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, New Delhi, for the years 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi, for the years 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi, for the year 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh, for the year 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh, for the years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Project and Development India Limited, Noida, for the years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Project and Development India Limited, for the years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi, for the years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(13) Thirteen statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Hon. Speaker Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Board of Major Port Authority for Deendayal Port (Meetings and Transactions of Business) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. LW/GN/2790/2024/001 in Gazette of India dated 8th April, 2024 under section 73(A) of the Major Port Authorities Act, 2021.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation (No.3) Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th July, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.2) Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance (No.2) Bill, 2024, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7h August, 2024 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक

1204 बजे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Speaker Sir, in accordance with Rule 72 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I rise to *pro forma* oppose the introduction of the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 as there is no provision in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha to get a clarification with respect to the source of legislative power of the Union Government under the Seventh Schedule of the Constitution of India to introduce the proposed Bill even though it may be an amendment to the principal Act.

Mr. Speaker Sir, I am aware that the Banking Regulation Act was amended in 1965 to make it applicable to the cooperative societies. I am also aware that it was amended in 2020 to bring cooperative banks under the purview of the Reserve Bank of India. The Entry 45 pertains to banking. However, it is important to note that the Entry 43 of the Union List expressly excludes the cooperative societies from the legislative remit of the Central Government and by implication, the cooperative banks.

(1205/VR/KN)

Entry 44 of the Union List does not specifically refer to cooperative societies. On the other hand, Entry 32 of the State List gives specific powers to State Governments to legislate on cooperative societies and by derivation on cooperative banks. *....(Interruptions)* Mr. Speaker, Sir, this is an important issue of legislative power, if you could indulge me for a second. *....(Interruptions)*

Mr. Speaker, Sir, this matter had also come up when the Joint Parliamentary Committee had deliberated on the Multi-State Cooperative Bill. There are a catena of judgments by various courts in this country including the Supreme Court that the power to legislate with regard to cooperative societies and by implication cooperative banks vests with the State Governments. The Government's answer will be that the earlier two Banking Regulation (Amendment) Acts have not been challenged. But that does not mean that we can have an ambiguous source of legislative power.

My submission, through you, Mr. Speaker, Sir, to the Government is that where there is ambiguity with regard to legislative power, why they would amend the Seventh Schedule. List-I, List-II and List-III are updated so that there is absolute clarity with regard to where the Government is drawing legislative power in order to enact a particular legislation.

Thank you, Mr. Speaker, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी तो सेंटर के अंदर आएगी न?

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, जब इसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, तो यह विषय उसमें भी उठा था। क्योंकि एंट्री 43, 44 यूनियन लिस्ट और एंट्री 32 में विरोधाभास है। हम लोगों ने उस टाइम पर भी डिसेंट नोट नहीं दिया था। लेकिन हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस इस चीज के ऊपर दी थीं कि कोऑपरेटिव सोसायटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि नहीं? इसके ऊपर विरोधाभास है। मेरा लिमिटेड पॉइंट यह है।

माननीय अध्यक्ष : ओ.के.। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन तो सेंट्रल, रजिस्ट्रार में होता है न? मैं यह पूछना चाहता हूं।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सर, उसके ऊपर … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपका भी नंबर आएगा। आप हैड फोन लगा लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my objection is not to the legislative competence of the Bill. My objection is regarding the established rules, practices and procedures in the House. By this Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 the Government is intending to amend four laws - the Reserve Bank of India Act, 1934; the Banking Regulation Act, 1949; the State Bank of India Act, 1935; and the Banking Companies Act, 1970 as well as 1980.

Sir, I am not questioning the legislative competence of the Government with regard to these Acts. But the problem is with regard to compiling or consolidating of four laws into one law, that is, banking laws. Yes, there are a lot of precedents. It can be done. But it is for the common purpose that the provisions of all these Bills should be interconnected.

I will just cite one example. Here, in this case the Cooperative Societies Act, in which the tenure of the Directors of the offices is extended from eight years to ten years. It has nothing to do with the original common purpose of the Bill.

My point is that this is against the precedence and conventions of the House and the practice which is being followed. Only those provisions which are interconnected, interrelated and have a common purpose to achieve, then only you can consolidate all these legislations together. That is the objection which I would like to raise.

Thank you very much, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of the Bill further to amend several laws. As has been pointed out, this Bill is entirely superfluous. It deals with amendments of the Banking Regulations Act to redefine substantial interests.

Then again, it changes the Rules with regard to directors of cooperative banks.

(1210/SAN/VB)

Then again, it goes to the State Bank of India Act and says that the unclaimed dividends would go to the Investor Education and Protection Act. Again, it goes to the State Bank of India Act to provide discretion to the public sector banks in the matter of remuneration of auditors.

Now, this Bill is superfluous in the sense that all that this Bill is seeking to achieve can be achieved through administrative steps. If the banks are not reporting to the Reserve Bank of India, then steps can be taken against the banks under the present law. If the cooperatives, in which there is a lot of corruption throughout the country, are not functioning properly, the Banking Department can take steps against them. I totally object to the fact that they are saying that any unclaimed dividend would go to the Investor Education and Protection Fund, as a result of which we may complicate the resolution.

Sir, Mr. Premachandran has pointed out that through one Bill, four different laws are sought to be amended. Is this the way legislation should happen in this country? Four Acts are sought to be amended through one Bill, which his unnecessary, superfluous and against the interest of the people. Hence, I oppose the introduction of the Bill.

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, the hon. Member was pointing out the ambiguity which prevails and also quoting from the slight dichotomy which prevails in the VII Schedule-listed items. I just want to highlight, which I think hon. Member Manish Tiwari also conceded, that there have been several amendments earlier and probably, he felt that it was not sufficient to say that it has been done earlier, courts have not struck it down, so why not now, if I have understood him right.

Sir, I would think it is important for us to recognise the ambiguity, which he rightly points out, between Entry Numbers 43, 44 and 45 where one excludes the ‘cooperative’ and Entry 45 brings in the ‘banking’ and therefore, with that done and remaining in front of us, the various amendments which have been done to the Banking Regulation Act with respect to the cooperative banks are not just one or two; they are several. It happened in 1981, 1984, 1987, 1989, 1991, 2004, 2013 and 2020, just to cite a few. There are several instances, but I do not want to take the hon. House’s valuable time.

But the simple understanding is that we are not touching any aspect of the cooperative other than that which came under the name of banking. I would not so directly relate it, but I would certainly bring to the notice of this hon. House, if I remember correct, that in 2019 when there was near collapse or complete collapse of a multistate cooperative bank, which hon. Speaker remotely mentioned, not the multistate cooperative dealing with primary agricultural society - it was through the Banking Regulation Act and through the body which governs insurance to be paid to the bank account holders - we had approached this hon. House and raised the insurance cover from Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 and from Rs. 1,00,000 to Rs. 5,00,000. As a result, we were able to give a lot of small account holders in these cooperative banks some relief. So, the inter-linkage between the banking regulation and that which is cooperative but banks, not the primary agricultural society, is completely getting repeated in history and every time the Banking Regulation Act has to, with due consideration, come with a delayed step. This is one of the reasons why we are doing not just the Banking Regulation Act but all those related to this, at one go. We can always come four times to this august House for the same cause, but when it is related to the same function of banks, either under the cooperative society or regularly under the banks, we need to take this route.

(1215/SNT/PC)

That is what is being done here. Just to give an example, I will cite the 2004 Amendment where Section 22A was introduced as a part of the Banking Regulation (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act of 2004. It addresses the validity of banking licences granted by the Reserve Bank of India to multi-State cooperative societies. Section 22A was enacted to protect licensing status of multi-State cooperative societies, ensuring that licences granted before the 2004 Amendment remain valid, and providing a clear process for those whose applications were still pending at that time. So, the Sections which have been brought in as amendments and also the Court's verdicts have repeatedly reinforced the point that the Banking Regulation Act and the cooperative banks do have this relationship, and therefore, it has to be taken through this route. Otherwise, there is no attempt to undermine the cooperatives, particularly, the cooperatives which do not deal with banking.

The banks and the cooperatives with licence for banking will have to have a route, and therefore, we have shown this.

I partly answered Prof. Sougata Ray's question regarding why so many Acts will have to be dealt with. The amendment that we are now aiming at is shifting of submission of statutory reports by banks – which he mentioned distinctly – to RBI from the reporting Friday to the fortnight of last month or quarter. What is the rationale behind it? The current reporting Friday system has several limitations that impact the accuracy and effectiveness of reporting of the data. I will name a few of these limitations. These limitations are: incomplete coverage of monthly data; seasonal fluctuations in banking activities, which lead to inconsistent reporting; and the need for adjustment every 11th year which introduces complications and inconsistencies. That is why, in order to address this issue, it is proposed to amend this legislation to transition to reporting on 15th and on the last working day of each month, thereby, accuracy can be brought in. Reports for the 15th would be submitted on the 20th of the same month, while reports for the last day would be submitted by the 5th of the following month.

So, these are largely aimed at the common cause, a point which Shri N. K. Premachandran would say, a point which Shri Manish Tewari would say that the larger cause is what you should deal with through the Acts but not the minor ones or not the specific ones which benefit one section. This is actually going to impact the banking, both of cooperatives and otherwise as well. These are data today which are being used legitimately with approval by very many different sources and if inaccuracies are going to guide our policy-making, it may not be effective, and therefore, we had to come up with this.

Sir, I would seek your indulgence in clearing this.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

CARRIAGE OF GOODS BY SEA BILL

1219 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Respected, Speaker Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the responsibilities, liabilities, rights and immunities attached to carriers with respect to the carriage of goods by sea and for matters connected therewith or related thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि समुद्र द्वारा माल वहन की बाबत वाहक से संलग्न उत्तरदायित्व, दायित्व, अधिकार और उन्मुक्तियों के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

(1220/AK/CS)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have opposed the introduction of this Bill, which is called the Carriage of Goods by Sea Bill, 2024.

The Indian Carriage of Goods by Sea Act, 1925 was enacted to amend the law with respect to carriage of goods by sea. It has stood us in good stead for 100 years. Suddenly, in the 100th year the Minister thinks of coming up with a fresh Bill. The mention of Hague rules, Brussels rules, Visby rules, all these were always there.

So, I would like to know this from the hon. Minister. Is it just to find some work for his Department that does not have enough work that you are bringing in a new Bill? A Bill which has served its purpose for 100 years, suddenly you jump and say that : "… with rules that are applicable …", they are all minor amendments. This superfluous legislation should be done away with. It only makes your bureaucrats happy. It does not make the country happy, and it does not help anything. Thank you, Sir.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Speaker Sir, the hon. Member is a very senior and very respected Member in the House. I believe that, after going through the Act, you have also come to realise it.

I do agree with you that the spirit and the substance of the Act are unchanged. We are bringing this because it is already 100 years old. Now, to comply with the international conventions; to deal with the changing situation of the global scenario; and also with the modern legislations, simplification and ease of understanding is very necessary. Here, we have made some proposals, which need to be incorporated to empower the Government to issue directions so that the spirit and also the provision is strictly carried out by the concerned.

1223 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

So, I believe that this particular Bill is very much necessary, and it is imperative to bring certain changes., We are trying to make it simplified for better understanding of the Act by incorporating some definitions. Thank you.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि समुद्र द्वारा माल वहन की बाबत वाहक से संलग्न उत्तरदायित्व, दायित्व, अधिकार और उन्मुक्तियों के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, I introduce the Bill.

BILLS OF LADING BILL

1224 hours

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to make provisions for the transfer of rights of suit and all liabilities to the consignee named in a bill of lading and every endorsee of a bill of lading, to whom the property in the goods mentioned in the bill of lading shall pass, upon or by reason of a consignment or an endorsement, and for matters connected therewith or related thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि किसी वहन-पत्र में नामित पारेषिती तथा किसी वहन-पत्र के पृष्ठांकिती के वाद में अधिकारों और सभी दायित्वों के अंतरण, जिन्हें वहन-पत्र में वर्णित माल की संपति पारेषिती या पृष्ठांकिती होने के कारण संक्रान्त करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, I introduce the Bill.

(1225/IND/UB)

रेल (संशोधन) विधेयक

1225 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आइटम नम्बर-13, श्री अश्विनी वैष्णव जी।

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सभापति महोदया, मैं रेल संशोधन विधेयक, 2024 का विरोध करता हूं। मंत्री जी ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में बताया है कि the functioning and independence of the Railway Board will be enhanced with this Bill. All the provisions of the Indian Railway Board Act, 1905 are proposed to be incorporated in the Bill. अभी तक 1989 का एक बिल है। It is not a very old Bill. Originally, as you have mentioned, Railways was separated from PWD. Then the Railway Board was set up. May I represent to you, hon. Chairman, that the Railway Board was bureaucracy? That can happen. It is inflexible. It is unable to take timely decision. It is unable to give relief to the people of this country. The Railway Minister, instead of bringing unnecessary bills which have functioned for a long time, should give attention to the railway accidents. He himself was present when the railway accident took place in Balasore. He was present again when the Kanchanjunga Express rammed into a station. The whole question is, what is the railway doing about safety of railway passengers? The Railway Minister has introduced Vande Bharat Train. It is good. They take you fast. When I oppose something, I can bring all the points. … (*Interruptions*) Your Railway Board has failed to control accidents. इसे ज्यादा पावर देने से क्या होगा?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय रेल मंत्री जी।

श्री अश्विनी वैष्णव : सभापति जी, मुझे लगता है कि प्रो. सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसलिए कोई भी सुपरफ्लूअस ऑब्जेक्शन लाना इनकी मजबूरी है। इनके पास कोई काम नहीं होगा। आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें कि ज्यादा काम लाएं।

अब मैं विषय पर आता हूं कि इस संशोधन विधेयक लाने की जरूरत क्यों है। जैसा आप सभी जानते हैं कि रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूज हुई, तब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी। रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। जब रेलवे का विस्तार बढ़ा, तो जरूरत महसूस हुई कि इसमें अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। इसलिए वर्ष 1905 में जब बहुत सारे प्रिंस्ली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तब एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई। रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टेच्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आकर एक एग्जिक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आयी। इसकी जरूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कम्पैरिजन में रेलवे अलग तरह का डिपार्टमेंट है। यह एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। दूसरा, इसमें नेटवर्क इफेक्ट होता है। तीन अलग-अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, आज भी यह प्रश्न आता है और माननीय सांसद कई बार यह प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए एक जगह से रेल में सामान चढ़ा और दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना है तो जो भी सामान चढ़ा रहा है, वह सारे का सारा ओरिजनेटिंग स्टेशन पर देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए, उन रेलवे सिस्टम की भी जरूरत होती है, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिर सेम डायमेंशन्स होने चाहिए। सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था। जब इंडियन रेलेवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके वर्ष 1989 में नया कानून आया, उसमें एक कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टेट्यूटरी पावर देने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पाए थे। उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए एग्जिक्यूटिव आर्डर के साथ लिंक रखा था, लेकिन यह एक कमी थी, जिसे इस बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड की कम्प्लीट पावर्स एनहांस होंगी और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि रेल अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री अश्विनी वैष्णव : सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(1230/RV/SRG)

कार्य मंत्रणा समिति
तीसरे प्रतिवेदन के विषय में प्रस्ताव

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आइटम नम्बर - 9; माननीय सदस्य बैजयंत पांडा जी।

श्री बैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 8 अगस्त, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 8 अगस्त, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

---

*लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1231 बजे

श्री वरुण चौधरी (अम्बाला) : सभापति जी, हाल ही में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज दविन्दर सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, इसके कारण पूरे देश में अनुसूचित जाति के जो हमारे साथी हैं, उनके अन्दर अशान्ति का भाव है और एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। इसी फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को 'भारत बंद' का भी आह्वान किया गया है।

सभापति महोदया, इसके अन्दर क्रीमी लेयर की भी बात कही जा रही है, सब-क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है और सब-क्लासिफिकेशन का जो अधिकार है, वह राज्य सरकारों को दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण मिला था, वह आर्थिक आधार पर कभी नहीं मिला था। जब वह मिला था, तो वह छुआछूत के खिलाफ, जातिगत श्रेष्ठता और हीनता के खिलाफ मिला था। समाज के अन्दर यह जातिगत श्रेष्ठता और हीनता आज भी मौजूद हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो सोच थी, उनकी जो परिकल्पना थी, यह उसके खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर एक बयान दे और उपरोक्त वर्णित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एक समीक्षा पिटीशन भी दायर करे, क्योंकि यह प्रतीत होता है कि इससे अनुसूचित जातियों के आरक्षण को खत्म करने का एक रास्ता बनाया जा रहा है।

महोदया, आज भी आप देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट के कितने मामले रजिस्टर होते हैं और उत्पीड़न के कितने मामले आज भी दिखाई देते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाले और इसके ऊपर अपना वक्तव्य भी दे।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : महोदया, क्या सरकार इसको नोटिस में लेगी? सरकार को इस पर बयान देना चाहिए।... (व्यवधान)

SHRIMATI KRITI DEVI DEBBARMAN (TRIPURA EAST): Madam, I would like to inform the House that my State of Tripura has a very famous and divine Siddha Peeth, the Mata Tripura Sundari Temple, which is also a Shakti Peeth. The temple is situated at Matabari, and is the most sacred pilgrimage for the people of Tripura, both for the indigenous tribal people and for the non-tribal people.

Devotees from different parts of the State, especially the indigenous tribal people who belong to the lower income groups find it difficult to find any affordable accommodation to stay for a night or even to make a short transit.

---

* Please see pp. 351-352 for List of Members who have associated

(1235/SMN/GG)

I would request the Tourism Minister to kindly ensure that the ongoing Temple Corridor project, which is currently under the Tripura State Government, must have provisions for free or affordable accommodation for the devotees, primarily the indigenous people.

This will create employment opportunity for the local youth as well. Also, additional steps to put the temple on the National and International Tourism Map must be taken as it will boost the overall economy of the region.

Today being world indigenous day, I wish everyone and the people in the House who belong to the indigenous tribe, a very, very happy indigenous day.

Thank you, Madam. Thank you for giving me an opportunity to speak

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you Madam Chairperson for giving me an opportunity to raise one of the most important issues relating to the fishermen of Kerala. Everybody knows that the plight of fishermen nowadays is very miserable. Due to various reasons, particularly due to weather, they are not in a position to catch fish and they are facing very many different problems everyday. The kerosene supply is not at all there. Therefore, fishing has become a difficult thing.

Now, the fishermen of Kerala are totally depending upon the debt from the cooperative society. The apex body of the cooperative society is NCDC. Earlier, there was a central subsidy for the fishermen for taking this loan. Earlier, when the UPA was in power, 25 per cent of subsidy was there from NCDC and NABARD like organisations. When the NDA came to power, gradually this subsidy on loan for the fishermen has been reduced and now, it is totally stopped. What is happening in the coastal areas? The suicide thing will happen because the fishermen's condition is like that only. They are in a position to commit suicide. It is because every fisherman is in debt. There is no subsidy at all. The Government of India is talking about the poor people. But the entire action is against the poor. How will the poor fishermen live? Therefore, my request to the hon. Government is to introduce the subsidy for the fishermen. Why are you penalizing the fishermen? They are the poor people of this country. Like tribals, our fishermen are residing near the seashore. Both the tribals and the fishermen are in the same condition. We

need to treat them in a very good manner. On the other side, the Government of India is penalizing the fishermen to the maximum extent.

My request to the Government is that they need to immediately look into this matter and reintroduce the subsidy for the poor fishermen.

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : महोदया, बंग्लादेश में हिंदु मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ। जो चित्र प्रदर्शित हुआ है, उसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा पर आक्रमण अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, अधार्मिक और दर्दनाक है। बंग्लादेश में इस प्रकार की घटना घटी है। राजनीति मतभेद के कारण वहां आंदोलन हो कर सरकार का तख्तापलट कर दिया गया है। लेकिन हिंदु मंदिर तोड़े जाने के कारण और मंशा क्या हैं? इस परिप्रेक्ष में जो समाचार प्रदर्शित या प्रसारित हुए हैं, इसमें जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और सुभ्रदा देवी की मूर्तियों को तोड़े जाने का चित्र प्रदर्शित और प्रकाशित हुआ है। यह केवल ओडिशा के लोगों को ही नहीं, बल्कि समग्र जगत की जनता को दुखी किया है।

(1240/MY/SM)

संसद, सरकार, समग्र मानव समाज और देश इस गंभीर विषय पर विचार करें। दोषी को पकड़ कर उचित दण्ड दिए जाने हेतु सरकार बांग्लादेश के साथ वार्ता करें। हालांकि विदेश मंत्री जी ने कहा है कि हिंदू मंदिरों के ऊपर आक्रमण परेशानी की बात है। मैं समझता हूं कि जगन्नाथ महाप्रभु सारे जगत के हैं।... (व्यवधान) जय जगन्नाथ। आप भी दबाव डालिए।

महोदया, कोलकाता व हावड़ा से जगन्नाथ पुरी तक लंबी कतार लगती है।... (व्यवधान)

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Thank you, Madam, for giving me the time. I want to bring up the issue of Eastern Nagaland People's Organisation.

In Nagaland, we have 16 districts. Out of 16 districts, six districts are asking for a separate State. This was started from 25th November, 2010. The people of ENPU have been deprived of employment. Adequate fund allocation was also not done and the Act East Policy was not implemented properly for Eastern Nagaland people. Nothing was done for them in respect of natural wealth, native skill talent, infrastructure, roads and highways, transport, education and health.

We have three international trade centres, that is, DAN (Pangsha), Lungwa and Mimi. But they were also not taken care of well by the Government. They have been asking for the upgradation of village roads. The State Government formed a committee on 23rd May, 2011 and all the replies have been given regarding their demand for a separate State.

The State Government had proposed for an autonomous State. But the ENPU rejected it. They want a separate State. The BJP Government has agreed to give the Frontier Nagaland Territory. The ENPU has accepted that.

Now, due to the delay in fulfilling that promise, they have abstained from voting in the last parliamentary election. They have also abstained from voting in the regional council elections. It is deteriorating the situation. We need to bring social harmony among our Naga people.

So, I would like to know about the tripartite talk among the Government of India, the State Government of Nagaland and the ENPU about the Memorandum of Settlement of 6th December, 2022. So, I would like to appeal to the Home Ministry, through you, to kindly take up the matter urgently and solve the problem. Thank you.

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : सभापति महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, साक्षर भारत मिशन के तहत एक नारा था- 'शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन', लेकिन आज क्या हो रहा है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2009 के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 'साक्षर भारत मिशन' का आगाज किया गया था।

(1245/CP/RP)

यह पूर्णतया केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केन्द्र सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 5 लाख शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति हुई और हर ग्राम सभा में दो शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति हुई। इन्होंने इस मिशन के तहत घर-घर जाकर निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य किया तथा समय-समय पर बीएलओ का कार्य भी किया। इस कार्य में सबसे ज्यादा महिलाओं ने अपना योगदान दिया।

महोदया, अकेले हमारे उत्तर प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरकों ने कार्य किया। 8 साल बाद वर्ष 2017 में पत्रांक संख्या 17,036 और 17,536 दिनांक 27 दिसम्बर को जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं शिक्षा प्रेरकों के नवीनीकरण को प्रदेश सरकार द्वारा यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि जब तक केन्द्र सरकार आदेश नहीं आ जाता, तब तक इनकी बहाली या नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इनका लगभग 40 माह का मानदेय भी रोक कर रखा गया, तब से आज तक शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हैं। इस वजह से उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो गए हैं।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सादर अनुरोध है कि उन लाखों शिक्षा प्रेरकों और उनके परिवार की भुखमरी को देखते हुए उक्त योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्रदेश सरकार को उनके नवीनीकरण के लिए दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि उन लाखों बेरोजगारों एवं उनके परिवार का जीवन खुशहाल बन सके। इसके साथ ही, उनका रुका हुआ मानदेय भी दिलाया जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : महोदया, मैं राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, वर्तमान में 21 जिलों में पीने तथा सिंचाई के जल की समस्या के निराकरण के संबंध में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में देश का 10.41 प्रतिशत भू-भाग आता है। कृषि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देश का 13.88 प्रतिशत कृषि क्षेत्र राजस्थान के पास है। देश का 11 प्रतिशत पशु धन राजस्थान में है और आबादी के 5.67 प्रतिशत लोग राजस्थान में निवास करते हैं। जल संसाधनों के दृष्टिकोण से देश में राजस्थान की स्थिति अत्यन्त विषम एवं चिन्ताजनक है। राजस्थान के हिस्से में देश में उपलब्ध भूजल का मात्र 1.6 प्रतिशत एवं सतही जल का 1.16 प्रतिशत आता है। वर्ष 2022 में किए गए एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में कुल 302 ब्लॉक्स में से 264 ब्लॉक्स की स्थिति पानी के अति दोहन के चलते अत्यन्त गम्भीर हो गई है। बचे हुए 38 ब्लॉक्स भी तेजी से डार्क जोन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। महोदया, इन परिस्थितियों को देखते हुए पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, वर्तमान में 21 जिलों के लिए ईआरसीपी योजना के लिए वर्ष 2016-17 की डीपीआर तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 50 प्रतिशत जल निर्भरता पर बनाई थी। इससे इन 13 जिलों को 3,921 एमसीएम पानी मिलना था। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर, अपने नये एमओयू में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान व केन्द्र सरकार के मध्य पीकेसी रिवर लिंक के नाम से एक नया एमओयू कर लिया गया। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि यह एमओयू 75 प्रतिशत जल निर्भरता पर किया गया है। इससे राजस्थान को मात्र 1,775 एमसीएम पानी ही मिलेगा, जो बहुत कम है। राजस्थान की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित पीकेसी एमओयू की समीक्षा करते हुए 50 प्रतिशत जल निर्भरता पर ही योजना लागू की जाए। मैं आपसे यह मांग करता हूं।

सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन और है। आज ट्राइबल डे है। सबको ट्राइबल डे मुबारक हो। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में इस आदिवासी दिवस की छुट्टी सरकार द्वारा घोषित है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ट्राइबल डे की छुट्टी पूरे देश में भी घोषित की जाए।... (व्यवधान)

[*]SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon Chairperson, Vanakkam. I wish to raise an important issue pertaining to Vellore Parliamentary Constituency. All the trains and railway track between Chennai and Bengaluru go *via* Vellore Constituency. This Union Government has introduced superfast Vande Bharat trains. Those trains are the need of the hour. I do not deny. But in our area, they say a proverb. It goes like this, "Although the building is strong, the basement is so weak". This Government, which has introduced superfast trains, has forgotten to expand these railways tracks. All those trains from Chennai to Arakkonam *via* Vellore and Jolarpet should use this Vellore route besides all the trains going to Bengaluru and north India. Almost 200 trains pass through the Vaniyambadi, Ambur, Gudiyatham, Pernambut railway stations. If the people want to cross the railway track to go on both sides, they have to wait for at least one hour at the Level Crossings. When the people cross through the railway tracks due to the closure of Level Crossings for long time, accidents take place and every day at least one precious life is lost. I urge that in order to rectify this, at LC- 81 at Vaniyambadi New Town, an over-bridge should be constructed. We need an over-bridge at Latteri, at LC-57 besides another over- bridge at LC-58 at Rangampettai Railway Gate. We also need over-bridges at Katpadi VIT Gate at LC-53 and Katpadi Vanjur Gate, at LC-129 respectively. In all these places, these Level Crossings should be removed and overrides or underpass should be provided to ease the movement of people on both sides of the railway route. When I was MP of 17th Lok Sabha, I raised this issue several times in the Lok Sabha but nothing has happened. When I took this issue to the Divisional Railway Officer at Chennai, they said since elections were around the corner and he promised to complete this after the elections are over. Even elections are over now and we have won in our constituencies and we are now in Parliament, but over-bridges are not constructed in these places. I urge, through you, in order to stop people dying in accidents every day, all these LCs should be either converted as over-bridges or underpasses. Thank you for this opportunity.

---

[*] Original in Tamil

(1250/NKL/SJN)

SHRI RICHARD VANLALHMANGAIHA (MIZORAM): Respected Madam Chairperson, first of all, being a first-time MP, I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to all the people of my State for placing their confidence in me and giving me the opportunity to represent them in this august house.

Secondly, I would also like to extend my invitation to all my esteemed colleagues and request them to take time out from their busy schedules during this tenure to visit my beautiful State.

Mizoram is also known as the most peaceful State in India despite being surrounded on two sides by the neighbouring countries, Myanmar on the East and Bangladesh on the West.

Hon. Madam Chairperson, through you, I want to draw the kind attention of the Central Government to a burning issue currently affecting my State, that is, African Swine Fever (ASF), which has affected the livestock and livelihoods of thousands of people. As per the latest reports, the pig farmers of our State have suffered financial losses of over Rs 200 crore due to the recent outbreak of ASF.

Since February 2024, the ASF has caused deaths of over 8,251 pigs and culling of over 15,000 pigs, as per the official records. This number is bound to be much more as there are a number of unreported cases. I would specifically like to highlight the hardship being faced by some of our pig farmers who have taken loans worth several crores but have lost everything due to this outbreak.

(1255/VR/SPS)

Madam, even before this recent outbreak, the State has been plagued by African Swine Fever (ASF) for many decades. Such is the magnitude of this problem. Even I myself have been affected personally by this outbreak. After the results of the Lok Sabha elections were announced, I could not even celebrate my victory properly as my own locality was declared as an infected area.

I, therefore, request the hon. Union Minister of Animal Husbandry to help us containing the spread of ASF immediately, and to help in finding out measures to contain it permanently.

Keeping in view the hardship faced by our pig farmers, a project proposal for revival of the piggery sector amounting to Rs 26,725 crore had already been submitted to the Central Government. I must mention that no financial aid has been received yet to compensate for the livestock which have been lost due to the disease but not due to culling. I, therefore, urge the hon. Union Minister of Animal Husbandry to kindly look into this personally and give favourable consideration to the proposal at the earliest.

Madam, from 2021 to June, 2024, in about three and a half years, about 55,602 pigs have died from ASF, and about 40,540 pigs have been culled. So, the total loss of pigs in terms of number has been 96,142. A total of 22,718 families and 652 villages have also been affected due to the deadly disease.

Thank you, Madam.

श्री राहुल सिंह लोधी (दमोह) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। वहां एक जागेश्वर नाथ धाम है, जहां पर निरंतर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। मैं इसके विषय में माननीय रेल मंत्री जी से भी मिला हूं और उनसे विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज के विषय में चर्चा की है। इसकी आवश्यकता पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही एक और स्थान है, जो हमारे जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं उसके विषय में भी जानकारी देना चाहता हूं। इससे पहले वर्ष 2004 और वर्ष 2011 में जबलपुर से दमोह और दमोह से वाया कुंडलपुर पन्ना के लिए रेल मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका सर्वे भी हुआ था। यदि यह लाइन पड़ती है तो इससे हम लोगों को दो फायदे होंगे। वर्तमान में जब हम दिल्ली की ओर आते हैं तो हमें पहले जबलपुर से कटनी, कटनी से दमोह और दमोह से सागर होते हुए दिल्ली आना पड़ता है, जिसमें लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। यदि यह लाइन जबलपुर से दमोह वाया कुंडलपुर बढ़ती है तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा। इसके अलावा यदि यह लाइन दमोह से वाया कुंडलपुर पन्ना जाएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर तीर्थ क्षेत्र है, जहां कुंडलपुर के बड़े बाबा है। इनकी पूरे विश्व में ख्याति है। वहां पर लोगों का आवागमन होता है। यदि यह लाइन डालते हैं तो विश्वास मानिए यह सरकार का और माननीय रेल मंत्री जी का जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे बड़े बाबा के चरणों में होगी।

महोदया मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि यह रेल मार्ग शीघ्रातिशीघ्र बनना चाहिए, जिससे दमोह से कुंडलपुर और कुंडलपुर से पन्ना के लिए लोगों का आवागमन हो सके। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(1300/MM/SAN)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदया, मैं बिहार के सीमांचल किशनगंज से आता हूं। वहां हर तरह की सब्जी और फल होते हैं, लेकिन बाजार नहीं होने के कारण किसानों को बहुत ही सस्ते दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ती हैं। फल और सब्जी ही नहीं, वहां जूट और चाय की भी खेती होती है, वहां के हिसान इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकारी मदद नहीं होने के कारण वहां से लोगों को पलायन करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पॉप्युलेशन के ज़रिए यह बताया गया है कि बिहार में 50 परसेंट से ज्यादा हाउसहोल्ड अपने स्टेट से बाहर काम करने जाते हैं। हमारे यहां लगभग 80 परसेंट लोग, हर परिवार से एक या दो लोग, बाहर जाते हैं। मेरी गुज़ारिश है और वैसे भी वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के अंडर किशनगंज के पाइनेप्प्ल को दिया गया है। वहां पाइनेप्पल की बहुत खेती होती है। पूरे हिन्दुस्तान में पाइनेप्पल वहां से जाता है, लेकिन हमें सही प्राइस नहीं मिल पाती है। मेरी गुज़ारिश है कि इन हालातों को देखते हुए और सरकार कहती भी है – वोकल फोर लोकल। अगर सरकार की यह बात सही है तो मेरी गुज़ारिश होगी कि इस सरकार के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट फण्डेड मेगा फूड पार्क वहां बनाया जाए ताकि हमारी क्रॉप की मुनासिब कीमतें मिल पाएं। इसके अलावा, स्टेट से जो माइग्रेशन हो रहा है, वह रुक पाए और लोगों को जॉब्स मिल पाए। यह हमारी गुज़ारिश है, बहुत-बहुत शुक्रिया।

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Thank you Madam Chairperson. Please give me three minutes to speak.

सर्वप्रथम, सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे विश्व आदिवासी दिवस के पुनीत अवसर पर अपनी बात रखने की अनुमति दी।

विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष ९ अगस्त को विश्व के आदिवासी जनों के अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए मनाया जाता है। आज का दिन आदिवासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देने का अवसर है जो एक बेहतर संसार बनाने में सहायक है। यह अवसर हमें आदिवासी जनों द्वारा दुनिया में जो सामाजिक धरोहर, परंपराएँ, भाषाएँ और अनुभव जोड़े गए हैं, उन्हें मनाने और संजोने का अवसर देता है। यह शुभ दिन आदिवासी समुदाय के बीच एकता विकसित करने और व्यापक लोगों में जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद करता है।

परंतु, दुर्भाग्य से, आज वास्तविकता अलग है। भारत में आदिवासी जनों की समस्याएँ बहुत हैं, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आदिवासी छात्रों की ड्रॉपआउट दर अत्यधिक ऊँची है, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर। आदिवासी क्षेत्रों में बाल विवाह एक जटिल सामाजिक समस्या है। स्वास्थ्य के संदर्भ में आदिवासी आबादी की बड़ी समस्याएँ हैं। ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी है जो अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित और तैयार हों। यह मुद्दा आदिवासियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। अधिकांश आदिवासी गरीब हैं। अधिकांश आदिवासियों का प्राथमिक व्यवसाय शिकार, संग्रहण, और कृषि है, जिससे न के बराबर मुनाफा मिलता है।

सभापति महोदया, आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में पर्यावरण संरक्षण का पालन करते हैं। उनके लिए प्रकृति की रक्षा सबसे पहले आती है। प्रकृति उन्हें आहार उपलब्ध कराती है और प्रकृति उनकी रक्षा भी करती है। आदिवासी नृत्य, त्योहार और भोजन भी बहुत अनोखे और असामान्य होते हैं। ऐसे कई आदिवासी गीत, नृत्य, कहानियाँ, लोककथाएँ हैं जिनका दस्तावेजीकरण किया गया है और अन्य का दस्तावेजीकरण किया जाना बाकी है।

आदिवासी लोग अभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी लोग भूमि की हानि, जंगलों की समस्याएँ, सड़कों की कमी, नेटवर्क एक्सेस और मुख्यधारा के विकास के कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं। सरकार इन समस्याओं को पूरी तरह से समझने में सफल नहीं हो पा रही है।

समय आ गया है कि हम आदिवासी मुद्दों को समझने, संवेदनशील और दृढ़ निश्चयी बनने की शपथ लें। केवल तभी विश्व आदिवासी दिवस मनाने का कोई अर्थ होगा। मैं एक बार फिर भारत और विश्व के सभी आदिवासी भाई-बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि 9 अगस्त को नेशनल हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर किया जाए।

(1305/YSH/SNT)

DR. RABINDRA NARAYAN BEHERA (JAJPUR): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to raise my topic in Zero Hour.

It was decided to develop waterway connectivity in the River Brahmani in Odisha and its branches Kharasrota and Kelua and other rivers of Odisha under the development of National Waterways (NW-5) by Inland Waterways Authority of India (IWAI) and other stakeholders, like Dhamra Port Company, and Paradip Port Trust for mineral and cargo transportation.

In the early days, the Sadhabas of Kalinga used to travel Java, Sumatra, Borneo, and other Asian countries for trading on the country boats through these rivers. This is an alternate to reduce road congestion and traffic control for mineral and cargo transportation, and simultaneously, to bring back the maritime heritage of Kalinga. In 2010, a tender was floated in this regard.

I request the hon. Minister of Ports, Shipping and Waterways to kindly look into this matter and revive the past glory of Kalinga by bringing back this project. A time frame in this regard may be communicated.

Thank you.

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : माननीय सभापति महोदया, मेरे पिताजी सन् 1946 में पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश से जान बचाकर पश्चिम बंगाल में भागकर आए थे। उसके बाद मैं किसी कारण से अंडमान निकोबार चला गया था। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, यहां पर ये सभी पश्चिम बंगाल के लोग बैठे हैं। ये चुपचाप बैठे हैं। ये कुछ नहीं बोलते हैं। वहां के लोग रिफ्यूजी बनकर यहां आते रहे। उन्हें भारत के अंदर गांव-गांव में भेज दिया गया।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, शून्य काल का विषय रखिए।

… (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : ये बांग्लादेशी लोग माँ की चीख पुकार नहीं सुनते हैं। रोना, पीटना, मृत्यु, काटना, चारों तरफ लूट मची है। बच्चों की मृत्यु और उनका अपहरण किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, तृणमूल पार्टी सब मिलकर बांग्लादेश का विरोध नहीं कर रही हैं। ये बांग्लादेश की आलोचना करे, चर्चा करे। … (व्यवधान) ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। पाकिस्तानी आओ, बांग्लादेशी आओ, इनकी तरफ से सिर्फ यही चलता रहा है। … (व्यवधान) मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि तृणमूल पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस नहीं बोलेगी। राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेंगे। … (व्यवधान) इनके लिए ये सिर्फ वोट बैंक है। बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ। मैं इसका विरोध करूंगा। पूरा सदन इसका विरोध करे तथा एक पत्र भारत द्वारा बांग्लादेश को भेजना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। … (व्यवधान)

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Madam, I would like to draw the attention of the House towards the inordinate delay in the construction of sanctioned Railway Over Bridges in my parliamentary constituency of Attingal, Kerala.

Chirayainkeezhu Railway Over Bridge (LC-566) was sanctioned in the year 2013. The construction works were started only two years back and the inordinate delay in works is causing great difficulties to the public. Similarly, the Railway Over Bridge at Kaniyapuram level crossing (LC-573) was also sanctioned in the year 2013. The works of this ROB is not started yet and the public are facing extreme difficulties due to closure of railway gate at Kaniyapuram.

Apart from these two, works of following ROBs are also long pending: LC-567 – Sarkara, the year of sanction is 2013; LC-569 – Manjadimoodu, the year of sanction is 2013; LC-555 – Edava, the year of sanction is 2012; LC-557 – Venkulam, the year of sanction is 2012; LC-558 – Punnamoodu, the year of sanction is 2016; and LC-570 – Azhoor Gate, the year of sanction is 2018.

It is necessary to take immediate measures for the execution of these projects without further delay. I request the Government to complete the sanctioned Railway Over Bridges in Attingal constituency under Thiruvananthapuram Railway Division at the earliest.

Thank you, Sir.

(1310/RAJ/AK)

*SHRI ABU TAHER KHAN (MURSHIDABAD):Honourable Chairperson, My Constituency Murshidabad is a place of historical importance. It was once the capital of Bengal, Bihar, and Odisha. Nashipur Bridge has been constructed which is adjacent to the Murshidabad station. This Rail Bridge will reduce the distance of travel between Sealdah and North Bengal by 100 kms. Railway Services are yet to be started on the Rail bridge. Due to the Honourable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay's initiatives, the construction of the Rail bridge has been completed after 10 long years. It has been 6 months since this bridge was inaugurated. New trains are yet to commence journey through the bridge. Through you I am requesting the authorities to resume rail services through this bridge. Since the construction of the rail bridge has already been completed, since it will reduce 100 km of distance between Sealdah and North Bengal, which will be eventually beneficial for the Railways; train services should readily kick off on the bridge to benefit the people of North Bengal. Murshidabad is a historical station, this place was once the capital of Bengal, Bihar, and Orissa, thus this station deserves to be modernized. There are many problems regarding the underpasses at Bhogobangola, Jiaganj, Lalgola- steps should be taken accordingly to amend those. Karimpur is a famous place in my constituency. A rail line needs to be constructed from Krishnanagar to Karimpur. If the new rail line gets constructed, people from two sub-divisions- Domkal and Tehatta will be benefitted. Honourable Chief Minister Mamata Bandopadhyay sanctioned this rail line during her tenure as the Railway Minister. There has been no progress since. I demand the rail line to be constructed. Around my constituency, there's Domkal on one side, there's Jolongi, there's Islampur on the other side- people of this large area will get benefitted, people hailing from North Bengal will also get benefitted, people living in the frontier areas which falls in the radius of 100 kms. from my constituency, they will all find this beneficial if they get to avail the Railway services. Thus, I am requesting through you, to escalate the work.

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर की एक अत्यंत, महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। शिवहर बिहार का एक सीमावर्ती जिला है, जो उत्तर में नेपाल और अन्य तीन दिशाओं में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, और मोतीहारी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, जिसके कारण यहां से मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है। इसका प्रमुख कारण जिले में उद्योग-धंधों का अभाव है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। दूसरा कारण यह है कि वहां का एक मात्र रीगा चिनी मिल वर्षों से बंद पड़ी हुई है।

माननीय सभापति महोदया, रीगा चीनी मिल को अति शीघ्र चालू कराया जाए और साथ ही शिवहर जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। यदि यहां एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, तो न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि मजदूरों का पलायन भी काफी हद तक रुक जाएगा और राज्य को राजस्व में वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। अतः, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता देते हुए शिवहर जिले में नए उद्योगों की स्थापना हेतु शीघ्र कार्रवाई की कृपा की जाए। इसके साथ ही, मैं फिर से आग्रह करूंगी कि रीगा चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ी हुई है, वहां किसानों का काम रुक गया है। किसानों को उससे काफी राहत मिलेगी, मजदूरों को राहत मिलेगी, उसे शीघ्र चालू कराया जाए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

---

*Original in Bengali

(1315/KN/UB)

श्री करण भूषण सिंह (कैसरगंज) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे पहली बार आज जीरो ऑवर में कैसरगंज लोक सभा क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाने का मौका दिया।

महोदया, मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं और उनकी खेल तैयारियों में होने वाली समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, मैं खुद शूटिंग का नेशनल खिलाड़ी हूं और कुश्ती जैसे खेल से बड़े लम्बे समय से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की दैनिक परेशानियों से भली-भांति परिचित हूं। इसलिए खिलाड़ियों की मांग को माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है।

महोदया, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में छात्र-छात्राएं खिलाड़ी बनने के साथ-साथ पुलिस और फौज में भर्ती होने के लिए प्रयास करते हैं। युवा और विद्यार्थी अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटती हैं और युवाओं की असमय मृत्यु होती है।

आज हमारे देश के गौरवशाली लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से मैं मांग उठाता हूं कि मेरे कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में खेल की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उत्कृष्ट स्टेडियम उपलब्ध कराया जाये। धन्यवाद।

श्री देवेश शाक्य (एटा) : सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज में एटा से मंडल आगरा और कासगंज से मंडल अलीगढ़ के लिए जो मुख्य मार्ग है, इस आशय के साथ फोर लेन बनवाने का अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में इन दोनों मार्गों पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण हर वर्ष इन मार्गों पर दुर्घटनाओं में कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है।

मेरा आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से आग्रह है कि इस जनहित के कार्य को इसलिए पूर्ण कराएं, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, वे जिले से मंडल मुख्यालयों तक जुड़े हुए हैं। मैं इसे फोर लेन बनवाने का प्रस्ताव इसी बजट में करने का अनुरोध करता हूं।

इसके साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र कासगंज एटा के साथ फरुर्खाबाद, बदायूं, आंवला में बड़े पैमाने पर किसान चकोरी की खेती करते हैं। चकोरी से कॉफी का पाउडर बनाया जाता है। किसानों द्वारा इसकी पैदावार बहुत मेहनत एवं पैसा लगा कर की जाती है। लेकिन ठेकेदार इनकी फसल ओने-पौने दाम पर खरीदते हैं और किसानों का आर्थिक शोषण करते हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि कासगंज में इसका एक बड़ा सरकारी प्लांट लगाने की कृपा करें, जिससे किसानों पर हो रहे अत्याचार पर विराम लगाया जा सके और किसानों को चकोरी का सही मूल्य दिलाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Madam, I would like to draw the attention of the House on the stalled Nashik-Pune High Speed Rail Project in my Nashik constituency. The project has immense potential to transform the economy of the surrounding areas as the project will pass through Nashik, Sinnar, Sangamner, Narayangaon, Rajgurunagar, and Chakan and will greatly benefit agriculture tourism and the industries of the region. The Nagpur-Mumbai Samruddhi Highway and the proposed Surat-Chennai Highway intersect on this route. Another aspect of this project is that it will create new avenues of economic development as it will connect the western and northern regions with the southern region.

Madam, through you, I would like to request the Ministry concerned to take immediate steps for the completion of the project at the earliest.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं शून्य काल को और आगे बढ़ा रही हूं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि सभी एक-एक मिनट में अपने विषय को रखें। मेरे पास बहुत सारे सदस्यों के नाम हैं। आप अपनी बात को एक मिनट में ही पूरी करें।

डॉ. संबित पात्रा जी।

(1320/VB/SRG)

डॉ. संबित पात्रा (पुरी) : माननीय सभापति जी, आपने शून्यकाल में मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदया, आज 9 अगस्त का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित उन सभी महान देशभक्तों और अमर बलिदानियों, क्रांतिकारियों को इस महान सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज से सौ वर्ष पहले, ठीक सौ वर्ष पहले, 9 अगस्त, 1925 को काकोरी में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति योजना को मूर्त रूप प्रदान किया था।

महोदया, परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि इस ऐतिहासिक घटना को हमारी पाठ्य-पुस्तकों में, हमारे इतिहास लेखन परम्परा में और डिजिटल फुट-प्रिंट में वह स्थान नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, बल्कि काकोरी प्रतिरोध की इस घटना को काकोरी कांड, काकोरी षडयंत्र अथवा काकोरी डकैती के नाम से इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया है। अगर आप अभी गूगल में सर्च करेंगे तो काकोरी कांस्पिरेसी, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी षडयंत्र, काकोरी लूट जैसे नाम दिये गए हैं।

महोदया, कांड, डकैती अथवा षडयंत्र असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले कुकृत्य होते हैं। यह उन शहीदों का अपमान है, जो इस देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार एक एडवाइज़री जारी कर यह सुनिश्चित करे कि पाठ्य-पुस्तकों से 'काकोरी षडयंत्र' और 'काकोरी कांस्पिरेसी' हटा दिया जाए तथा इसके स्थान पर काकोरी की घटना को 'काकोरी प्रतिरोध' या 'काकोरी रेल ऐक्शन' के नाम से सम्मिलित किया जाए।

इसी प्रकार से, मैं संस्कृति मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि शताब्दी वर्ष के अवसर पर व्यापक प्रचार हेतु संस्कृति मंत्रालय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए और इस शताब्दी वर्ष में 'काकोरी प्रतिरोध' शताब्दी वर्ष का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग कीजिए।

श्री लुम्बा राम जी।

श्री लुम्बा राम (जालौर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, सिरोही जालोर में पिछले कई सालों से भू-जल स्तर में भारी गिरावट के कारण दोनों जिले डार्क जोन घोषित हो चुके है। इस क्षेत्र के किसानों को डार्क जोन से मुक्ति दिलाने हेतु माही बांध का पानी सिरोही जालोर जिले के लिए उपलब्ध कराएं। यह योजना 60 वर्षों से बनी हुई है, जिसे कांग्रेस सरकार ने कागजों में दफन कर रखी थी। ऐसे में किसानों की उम्मीदें भी टूट गई थी। मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को पेयजल और सिंचाई के पानी को लेकर फिर उम्मीद जगी हैं।

आपसे निवेदन है कि वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार माही बांध परियोजना का कार्य शुरू हुआ था। उस समय खोंसला कमेटी की रिपोर्ट1 सितम्बर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान के बीच बोर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित था। उस समय 01 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता में कडाणा बांध का निमार्ण हुआ था। उस समझौते के अनुसार, खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आने के बाद कडाणा और माही बांध के पानी का 2/3 हिस्सा राजस्थान को और गुजरात के खेड़ा जिले को 1/3 पानी मिलना तय हुआ था।

चूंकि वर्ष 2005 में नर्मदा का पानी गुजरात के खेडा जिले को मिल रहा है, तो अब समझौते के अनुसार जालोर सिरोही को अपने हक का पानी मिलना चाहिए। मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के हक का पानी कडाणा बांध से पिछले 37 वर्षों में 27 बार ओवरफलो होकर 1.30 लाख एम सी एम पानी समुद्र में बह गया।

अतः पूरे पश्चिमी राजस्थान के किसानों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुसार किसानों के हित में कडाणा व माही बांध के पानी के लिए हाई लेवल नहर के माध्यम से, जालोर सिरोही व बाडमेर के गावों में पेयजल हेतु माही व कडाणा का पानी उपलब्ध कराएं।

मेरा पुन: निवेदन है कि यह योजना समय पर लागू करें। इसके लिए पश्चिमी राजस्थान का किसान वर्ग और जालोर सिरोही के किसान आपके आभारी रहेंगे।

(1325/SMN/PC)

*SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank Hon Chief Minister of Tamil Nadu Hon. *Thalapathiyar* who has given an opportunity to this ardent follower like me belonging to an ordinary family of farmers to serve as a Member of Lok Sabha. I thank the Secretary of DMK Youth Wing who is the heartbeat of lakhs of youth of Tamil Nadu. I also thank the voters of Kallakurichi constituency who voted for me, besides the party cadre of DMK and cadre of alliance parties for their valuable support. More than 2 lakh people live in the mountains of Servarayan hills, Yercaud - the poor man's Ooty, Kalvarayan hills, Pachaimalai hills and Arunootru Malai of the areas in Kallakurichi and Salem Districts under the Kallakurichi parliamentary constituency. Farming is their primary profession. These people who are dependent on agriculture are not provided Patta or ownership right for their farm lands. People of this area and the Officials have informed me that the Department of Forests under the Union Government is causing delay in providing a No Objection Certificate. Therefore I urge upon the Union Government and the Department of Forests under them to immediately provide this NOC so as to protect the livelihood of the people of these areas. These people in mountainous areas should also be provided with road facilities. These tribal people are being affected due to these issues. I as a Member of Parliament representing these tribal people want them to get these facilities. Thank you.

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, हमारे क्षेत्र में बासमती चावल की फसल बहुत होती है। बासमती चावल के एक्सपोर्ट का जो काम है, उस पर सरकार ने पिछली बार 1,200 डॉलर्स प्रति टन की कैप लगा दी थी। उसके विरोध के बाद उस कैप को 950 डॉलर्स प्रति टन कर दिया गया।

हमारे क्षेत्र में बासमती चावल की किस्में 1509, 1121, 1718 उगाई जाती हैं। जो बासमती चावल है, वह पूरे वर्ल्ड में इंडिया या पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन इसके रेट ज्यादा होने की वजह से अब 1509 बासमती चावल का ऑर्डर हमारे एक्सपोर्टर को नहीं मिल रहा है। यह मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट होता है। सारा ऑर्डर पाकिस्तान को मिल गया है।

मेरी सरकार से इसके लिए दरख्वास्त है। सरकार कहती है कि हमें किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। किसान की फसल अब पककर तैयार है, लेकिन 1509 बासमती चावल का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। सरकार उसका कैप कम करे। पाकिस्तान में 700 डॉलर्स की कैप है, उससे कम होना चाहिए, ताकि हमारा किसान भी बच सके और हमारा व्यापारी भी बच सके।

मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं।

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Madam, a new Bus Stand near Tiruvannamalai Railway Station in Tamil Nadu has been constructed. There is an urgent need to allocate funds for construction of a new railway over bridge connecting the railway station and the new bus stand. This will enable the passengers to make easy access/movement from bus stand to railway station and vice-versa. Besides, the proposed railway over bridge will also be connected with old bus stand. Therefore, I request the hon. Minister for Railways to allocate adequate funds for the project in the interest of the general public.

---

*Original in Tamil

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you Chairperson Madam for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance matter. Cashew industry is facing an unprecedented crisis and the situation is ignored by inaction of the Central Government and Ministry of Commerce and Industry.

It is shocking that around two lakh cashew workers are rendered jobless in the last four years in the Kollam, Alleppey, Pathanamthitta and Trivandrum districts and also in neighbouring States. This industry is facing a serious crisis. More than 10 people from the cashew industry committed suicide.

We have submitted so many memoranda to the Government of India for a special package for the cashew industry. But, unfortunately, the Government of India has not taken any step to revive the cashew industry in Kerala.
(1330/SM/CS)

So, I would like to request the Government, through you, that a special package should immediately be announced for the revival of cashew industries. At least Rs.1,000 crore should be given as revival package to the cashew industries in Kerala. Thank you.

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : महोदया, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदया, इस सदन के पक्ष, विपक्ष के हर व्यक्ति, सदन के हर चुने हुए माननीय सदस्य के क्षेत्र की यह समस्या है। मैं आपके माध्यम से इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदया, आबादी क्षेत्र के ऊपर से जा रही एचटी और एलटी लाइंस के कारण, अगर मैं कहूँ तो यह गलत नहीं होगा कि किसी भी आपदा, जंग या महामारी से भी अधिक मौतें डेली होती हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पिछले 10 वर्षों में वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2020 तक लगभग एक लाख लोगों की मौत हुई है। 12,500 से अधिक मौत वर्ष 2022 में हुई हैं। मेरे क्षेत्र बिजनौर लोक सभा के कुलचाना गाँव में और बरसात के सीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से मौतों का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

मेरा इतना ही कहना है कि जागरूकता और प्रीकॉशन, चाहे लाइंस को इंसुलेटिंग करना, रबड़िंग करना, उनकी हाइट एक्सटेंड करना आदि हैं। राज्य सरकारों के पास भी उनको चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस विषय पर सदन का संरक्षण मिलेगा और उसके लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : महोदया, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है। आजकल वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसे वाला को मारा है। यह कहता है कि मैं सलमान खान को मारूँगा। पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है। वह व्यापारियों से फिरौती लेता है और जो व्यापारी फिरौती नहीं देता है, उसे मार दिया जाता है। कल क्या हुआ, जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है। पिछले 6 महीने पहले हमने शोर मचाया, हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने सीआईए में, जहाँ इंटैरोगेशन होता है, वहाँ पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। एक पंजाब में हुआ और एक राजस्थान में हुआ। जब वह कोर्ट में जाता है तो ऐसे चलता है, जैसे देश का... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जाता हो। वह व्यक्तियों का कत्ल करता है। क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी या नहीं करेगी? वह रोजाना लोगों को मारने का काम करता है। ये बाहर की बातें करते हैं, लेकिन देश में जिस बंदे ने आतंक फैला रखा है, इन्हें उसके बारे में कुछ करना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : महोदया, देश का... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) वाला शब्द विलोपित करवा दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं देख लूँगी। जो भी शब्द वैसा होगा, हम उसे देख लेंगे।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Madam, I would like to draw the attention of the Government to the price hike of medicines. The people of our country cannot bear the excessive pressure of price rise anymore. The price of daily commodities is increasing day by day. The price of medicines is increasing at an alarming rate and it is exploiting the people.

The medicine manufacturing companies get a huge amount of money by electoral bonds. They do not care anybody. They are free to increase the cost of medicines. Has this Government any responsibility in this matter?

We have drawn the attention of the Government inside the Parliament to remove the GST on medicines. I would like to draw the attention of the hon. Prime Minister to this matter. Thank you for giving me the opportunity.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Madam. This is my first 'Zero Hour' submission in the Budget Session. It is relating to the Employees' Provident Fund pension.

In the Sixteenth Lok Sabha, I moved a Private Members Resolution and the Government appreciated it. A Committee was then appointed. It went into the matter of EPS,1995. It recommended to increase the minimum pension to a higher level. The Ministry of Labour and Employment also accepted it.

(1335/RP/IND)

It is pending before the Finance Ministry. So, my first submission is that the minimum pension should be enhanced as per the recommendations of the High Level Empowered Committee.

My second submission is regarding the inordinate delay in the disbursal of lawful pensionary benefits to the contributors for the pension on higher wages. The higher pension on the basis of actual wages should be provided as per the direction of the hon. Supreme Court's verdict dated 4th November 2022. It is clear on the part of the hon. Supreme Court that higher pension should be given on the basis of actual wages. But, it is quite unfortunate to note that there is a delay in that till now. Most of the PF offices are not disbursing the amount on time.

My third submission is regarding the unlawful introduction of *pro rata* calculation method for higher pension which is overpowering the Parliamentary provisions and disregarding the apex court judgement dated 4th November, 2022. The pensionable service and the wages are divided into two parts. After 1st September 2014, 30-35 per cent pension will be reduced. It is a gross violation of the hon. Supreme Court's judgement as well as the Act passed by the Parliament.

There is one more point that I wish to make. There is a non-compliance of the judgement dated 4th November 2002 of the hon. Supreme Court as well as the judgment dated 30th May 2004 of the High Court of Kerala with respect to the petitions of pensioners of CPSUs in Kerala. In Kerala, para 11 of the pension scheme has not been opted. They are now being denied this higher pension.

All these issues go to show that the Employees Provident Fund Organisation is always acting against the interests of the poor labourers in the country. Therefore, an urgent meeting may be conducted by the Government of India to address this serious issue.

With these words, I thank you very much for permitting me to speak.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति महोदया, मेरा नाम भी लिस्ट में है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि आप सभी के नाम मेरे पास हैं। आप धैर्य रखें, आप सबका नम्बर आएगा। आप सभी सहयोग कीजिए।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : आपकी वजह से ही हमें उम्मीद है कि हमें बोलने का अवसर जरूर मिलेगा।

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : सभापति जी, पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई थी, जिसके माध्यम से एक गांव दूसरे गांव से जोड़ा गया। मेरे संसदीय क्षेत्र रतलाम झबुआ अलीराजपुर में लोग फलिया में रहते हैं, जहां रोड नहीं है। जहां सड़कें नहीं होती हैं, वहां किसी प्रकार की व्यवस्था पहुंचाना आसान नहीं होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि जिस तरह से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई गई थी, उसी प्रकार प्रधान मंत्री फलिया सड़क योजना बनाई जाए। धन्यवाद।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के प्रतापगंज रेलवे स्टेशन जो पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत है। उक्त स्टेशन में मात्र 1 पैसेंजर ट्रेन तथा 2 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है। दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर नहीं है। अतः जनहित में ट्रेन सं० 13211/ 13212-जोगबनी-दानापुर एक्सप्रेस तथा 13213/13214- जोगबनी- सहरसा एक्सप्रेस का ठहराव 2 मिनट प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर किया जाय। साथ ही वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या-12553/12554 तथा राज्यरानी एक्सप्रेस-ट्रेन संख्या-12567/12568 का विस्तार सहरसा से सरायगढ़ या सुपौल तक जनहित में किया जाए।

(1340/RV/NKL)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : माननीय सभापति महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है और बांग्लादेश के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध अच्छे भी रहे हैं। हम चाहते हैं और पूरा भारत चाहता है कि वहां पर फिर से एक बार शांति वापस आए।

महोदया, बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, वह करीब 4,096 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय जैसे प्रदेश बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत का वेस्टर्न बॉर्डर जितना सख्त बनाया गया है, वैसे ही ईस्ट और नॉर्थ-ईस्टर्न बॉर्डर, इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर भी बहुत ही मजबूत बनाया जाए। वहां पर रिवराइन एरियाज़ भी हैं। वहां हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को मजबूत सुरक्षा मिले।

महोदया, जब वर्ष 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब वहां करीब 24 प्रतिशत हिन्दू थे, पर आज वहां पर मात्र 6 प्रतिशत हिन्दू ही रह गए हैं और उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि वहां हिन्दुओं को सुरक्षा मिले। मैं फिर से एक बार इस संसद के माध्यम से, सभी सांसदों के माध्यम से, बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश प्रशासन से यह अपील करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में रहने वाले हर हिन्दू, हर माइनॉरिटी को पूरी सुरक्षा मिले। उन्हें किसी दूसरे देश न जाना पड़े, ऐसी मैं भारत सरकार से विनती करता हूं।

डॉ. शिव पाल सिंह पटेल (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं, डॉ. एस.पी. सिंह पटेल आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

महोदया, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में डॉ. सोने लाल पटेल मेडिकल कालेज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहाँ पर मेडिकल सुविधा नगण्य है। वहां के लोग कहते हैं कि जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्ज़ा दे दिया गया है, लेकिन वहाँ की सुविधाएं आज भी जिला अस्पताल स्तर की ही है जबकि दूसरे जिलों के मेडिकल कालेजों में काफी सुविधाएं हैं। इस मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट और ट्रामा सेन्टर नहीं हैं। वहां पर न्यूरो सर्जन, मनोचिकित्सक और हार्ट की बीमारी के डाक्टर भी नहीं हैं, तो वहां इलाज क्या होगा? एम.आर.आई. मशीन तो वहां लगी है, लेकिन इसके लिए वहां कोई ऑपरेटर नहीं है। लोगों को हर जाँच के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में या दूसरे जनपद में जाना पड़ता है। यहां सिर्फ नाम के लिए मेडिकल कॉलेज खोला गया है, पर उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है, जिस कारण से वहां आये दिन बहुत से मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां के डायलिसिस सेन्टर में कम बेड होने के कारण जाँच के लिए मरीजों को लम्बे समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। वहां सिर्फ नाम के लिए मेडिकल कॉलेज है। वहां पूरे टीचर्स भी नहीं हैं, तो आगे पढ़ने वाले डॉक्टर क्या सीखेंगे?

महोदया, अतः आपसे अनुरोध है कि सदन के माध्यम से लोक महत्व के इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उपरोक्त सभी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर) : माननीय सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए, ताकि मरीज जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंच सके, इसके लिए पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना को प्रारम्भ किया था। मोदी जी के काल में बीते दस सालों में मेरे यहां 4,528 किलोमीटर की रोड्स बनी हैं, लेकिन अभी जो नियम बना है कि तीन किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर रहने वाले गांवों को ही प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाएगा, तो उसके चलते मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में करीब 400 गांव ऐसे हैं, जो प्रधान मंत्री सड़क योजना या पक्के रोड्स से जुड़े नहीं हैं। वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं और आये दिन वहां मरीजों और गर्भवती माताओं को खटिया में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तीन किलोमीटर वाले नियम को रिलैक्स किया जाए। सभी गांव पक्के रोड्स से जुड़ने चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

नियम-377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1344 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्यगण, नियम-377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन माननीय सदस्यों को नियम-377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गयी है, वे मामलों को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Implementation of 'Har Ghar Jal' Scheme under Jal Jeevan Mission in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में जल जीवन मिशन योजना "हर घर जल" के अन्तर्गत करवाए जा रहे कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मुझे क्षेत्र में दौरे के दौरान निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो निर्माण कार्य कार्यदायी एजेंसी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, वे गुणवत्ताविहीन और मानक के अनुरूप नहीं है। निर्माण कार्य में अत्यधिक घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तथा कार्यदायी एजेंसी द्वारा कार्य को जिन छोटे-छोटे ठेकेदारों में बांटा गया है. उनको उक्त कार्य का अनुभव ही नहीं है।

कार्यदायी एजेंसी द्वारा जो पाइप लाइन डाली जा रही है. उसकी गुणवत्ता मी अत्यधिक घटिया है। पाइपलाइन बहुत हल्की है एवं साइट पर डालते समय टूट-फूट हो रही है। इसके अलावा पाइप लाइन डालने के उपरांत रोड को कहीं भी ठीक / रिस्टोर नहीं किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर की सभी ग्राम पंचायतों में यह स्थिति है । जनपद के विकास खंड सिधौली के ग्राम मुर्छा में जल जीवन मिशन के तहत घटिया निर्माण सामग्री से बन रही पानी की टंकी की सीढ़ी गिरने से मजदूर भी घायल हुए हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित करके उपरोक्त पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करवाने तथा कार्यदायी एजेंसी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करते हुए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने और कार्यों को कुशल कार्यदायी एजेंसी को आवंटित किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

(इति)

Re: Need to establish Horticulture and Forestry college in Maharajganj parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सारण (छपरा) जिला के मांझी एवं सिवान जिला के भगवानपुर हाट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा स्थापित एक-एक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते यहाँ के किसान एवं जनता की इच्छा होती है कि आज के आधुनिक युग में अपने बच्चों को कृषि से सम्बन्धित उच्च एवं आधुनिक शिक्षा दिलवाई जाये जिससे कि उनके बच्चे कृषि के क्षेत्र में ही अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हुए। किसानों को उन्नत्त तरीके से खेती करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें । इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि उपर्युक्त दोनों कृषि विज्ञान केन्द्रों में से किसी एक में वागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय खोलवाया जाये। इन केन्द्रों के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है।

अत : महोदय के माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मांझी और भगवानपुर हाट में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों में से किसी एक में वागवानी एवं वानिकी कृषि महाविद्यालय खुलवाया जाए। (इति)

Re: Displacement of people in Jayant in Singrauli district, Madhya Pradesh

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : सिंगरौली जिले के जयंत क्षेत्र में विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्थापन होगा इससे पहले इस क्षेत्र में जो भी विस्थापन हुये थे लगभग ग्रामीण थें। किन्तु इस विस्थापन में बाजार, शो-रूम, प्रतिष्ठान, बस स्टैण्ड, हास्पिटल, पूजा घर, स्कूल, स्पोर्ट्स के मैदान के साथ-साथ इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक सभी प्रभावित हो रहें है। 75 हजार से अधिक आवादी, 30 हजार से अधिक परिवार, 927 हेक्टेयर जमीन व 22 हजार से अधिक घर प्रभावित हो रहें है, जिसमें फारेस्ट लैण्ड भी है। कोल वियरिंग एक्ट के तहत धारा 4, 7, 8 व 9 का प्रकाशन हो चुका है। विस्थापन होना तय है। वहां की जनता भी राष्ट्रहित में, राष्ट्र की प्रगति, समद्धि हेतु अपना घर-वार छोड़ने को तैयार है किन्तु कुछ शंकाएं वहां के विस्थापितों को है। मै सदन के माध्यम से उन्हे उल्लिखित करना चाहता हूं- पूर्व में उस क्षेत्र में हुये सभी विस्थापन नियम सापेक्ष नही हुये है। अतः इस बार सब ठीक-ठाक होगा यह संशय है। जमीन किस दर से ली जायेगी यह स्पष्ट हो वर्ग मीटर या वर्ग फिट में। LARR प्राबधानों के अनुरूप हों। (इति)

Re: Need to construct a bridge over Ganga river in Bhadohi Parliamentary Constituency

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : मेरे संसदीय क्षेत्र भदोही के अंतर्गत कोनिया क्षेत्र में धन तुलसी से डेंगूरपुर तक गंगा नदी पर पक्के पुल की आवश्यकता है, जिसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर है। आपको अवगत कराना है कि यह वह क्षेत्र है जो धार्मिक स्थल सीता समाहित स्थल, लव कुश जन्मस्थली और बाल्मीकि आश्रम के नजदीक है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में देश विदेश से दर्शनार्थियों का आवागमन होता है। अगर यहां गंगा पर पक्के पुल का निर्माण होता है तो 50 से ज्यादा गांव के ग्रामीण जिनकी संख्या लाखों में है, जो रोजी रोजगार के लिए आते जाते हैं और दर्शनार्थियों का आना-जाना रहता है और कोनिया क्षेत्र में प्रयागराज मिर्जापुर सहित मध्य प्रदेश और आसपास के कई क्षेत्रों में आने-जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह क्षेत्र भदोही जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कोनिया क्षेत्र में गंगा पर पक्के पुल बनने से लाखों के आबादी को लाभ होगा। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल इस कार्य को करने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to formulate a national policy to grant land rights to ancestral land of the people

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The Forest Department in India was set up in 1864, whereas Tea Gardens in Darjeeling was set up in 1850s and Cinchona gardens in 1861 which means the Tea gardens and Cinchona gardens are older than the Forest Department. But today, the West Bengal Forest Department claims that even Tea Garden and Cinchona Garden land belongs to the Forest Department of State. But the State Government has not yet implemented the Forest Rights Act, 2006 passed by the Parliament. When the Tea Gardens and Cinchona Gardens where developed the British appropriated our ancestral lands and they refused to give land documents to our ancestors. Even though 77 years have been elapsed since independence, the Government of West Bengal is yet to grant Parja Patta land rights to the workers of Tea garden and Cinchona Garden. The people from Darjeeling region have done four Andolans for “LAND” and in recent days, the ownership of people’s ancestral land is claimed by the State Forest Department. Hence, I request the Central Government to form a National Policy to grant land rights to ancestral land of the people.

(ends)

Re: Need to complete construction of remaining portion of Agra – Tantpur court Road in Uttar Pradesh declared as National Highway

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) :आपको अवगत कराना है कि चंदौसी-आगरा-तांतपुर-कोर्ट मार्ग आगरा जनपद की जनता के लिये महत्वपूर्ण मार्ग है जो कि सी०ए०टी० मार्ग कहलाता है। जिसे चंदौसी से आगरा तक पूर्व में ही एन०एच० घोषित किया जा चुका है। मार्ग भी बन गया है परन्तु आगरा से तांतपुर-कोर्ट मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। अत: आपसे विशेष अनुरोध है कि आगरा-तांतपुर-कोर्ट मार्ग के शेष भाग का निर्माण कराने की कृपा करें जिससे यातायात में जनता को बड़ी राहत मिल सके।

(इति)

Re: Need to include tribal people of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu in the Fifth and Sixth Schedules to the Constitution

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : मै दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव जैसे आदिवासी बाहुल्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने से वहां के आदिवासी समुदाय के कई परिवारों को मूलभूत सुविधाए नहीं मिल रही है। जब मेरा प्रदेश आजाद हुआ था तब यह कहा गया था कि आदिवासी समुदाय को पांचवी और छठी अनुसूची में शामिल किया जायेगा। मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद प्रदेश के 80% प्रतिशत आदिवासी समुदाय को आजादी के बाद पांचवी और छठी अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। पूर्व में मेरे पति श्री मोहन डेलकर जी नें इस विषय को कई बार सदन में उठाया था। मै संबधित मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोगों को पांचवी-छठी अनुसूची मे शामिल कर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए जिससे उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेगी। यदि रास्ता, पानी, लाइट, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रिजर्वेशन जैसी हर सुविधा मिलेगी तो ही आदिवासी समाज आगे बढ़ सकेगा।

(इति)

Re: Need for establishment of a Trauma centre in Keonjhar district, Odisha

SHRI ANANTA NAYAK (KEONJHAR): NH-20 and NH-49 are two most important National Highways which pass through heart of my constituency Keonjhar and are lifeline of this area. As these two NHs are connected to the major ports and mining areas, almost more than 10,000 trucks in addition to other vehicles ply daily through these two highways carrying mineral ores from mines to major ports. Due to heavy traffic on these two major highways lots of accidents occur on these highways and many precious lives are lost over the period due to unavailability of immediate medical facilities/trauma Centre in Keonjhar to treat the patients met with accidents. The nearest city/town with trauma Centre/medical facility to treat accident victims is quite far from my constituency and often it becomes too late to get urgent necessary medical treatment. Considering the increasing number of accidents and the consequent need for specialized medical intervention, I request the Government to initiate the process for the establishment/construction of a dedicated trauma centre in my constituency, Keonjhar district so that the time and risk associated with transporting patients to distant hospitals may be reduced, thereby minimizing complications and fatalities and precious lives of the people can be saved. (ends)

Re: Need to grant Divyanga status to ostomy patients

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : ओष्टमी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मलमूत्र मार्ग में कैंसर हो जाने के कारण उन्हें ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा एक कृत्रिम मार्ग निकालकर पेट पर एक बैग लगा दिया जाता है और मूल मार्ग से मलमूत्र का रिसाव न होकर कृतिम बैग में मलमूत्र का रिसाव होता है, इस बैग को हर 2 से 3 दिन में बदलना होता है, उन मरीजों में यह भी महसूस नहीं होता कि उनका रिसाव कब कहाँ और कैसे होगा | जब थैली भर जाए तो खाली करो और उस भयावह स्थिति की कल्पना कीजिये जब कहीं काम के दौरान रिसाव हो जाए तो सबके सामने मलमूत्र से सना हुआ बदबू भरा उनका कपड़ा, कैसी स्थिति में जी रहे हैं सोचा जाए तो नरक से कम नहीं है इनका जीवन। वर्तमान में देश भर में अनुमानतः ऐसे लगभग 10 लाख के आसपास मरीज हैं अतः मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूँ कि चूँकि उनके शरीर का महत्वपूर्ण अंग काम नहीं कर रहा है इस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिव्यांग का दर्जा देने की दिशा में सकारात्मक पहल जल्द से जल्द करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to construct Road over Bridge in Satna City Madhya Pradesh and also provide additional funds for construction of Satna and Tamas Rivers

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना शहर की ओर दिलाना चाहता हूँ, देश के अन्दर 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की जिस महत्वपूर्ण योजना को मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, उसमें सतना शहर भी शामिल है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि शहर में दिन-प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है इसलिये सेमरिया चौक से पुरानी गल्ला मंडी होकर टिकुरिया टोला तक तथा सर्किट हाउस से रेलवे स्टेशन रोड होकर नजीराबाद कालोनी तक फ्लाई ओव्हर सड़क बनाने की हमारी मांग को स्वीकृति दी जाय, तथा स्मार्ट सिटी के तहत सतना एवं टमस नदी जिनके संगम से शहर को पीने का पानी दिया जा रहा है इन दोनों नदियों के संरक्षण हेतु अतिरिक्त धनराशि दी जाय। (इति)

Re: Need to promote spiritual tourism in Himachal Pradesh and also set up a Yoga Vidyalaya in Mandi area of the State

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : हिमाचल प्राचीन काल से ही भारत का गौरवमयी भूभाग रहा है| ऋषियों, देवताओ, स्वयं शिव- पार्वती, ऋषि वेद व्यास, मार्कण्डेय ऋषि , एवं पांडवो की तपो स्थली रही है । हिमाचल प्रदेश का कई ग्रंथों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। हम अपनी संस्कृति , अपनी सभ्यता और प्राचीन पुण्य स्थलों को भूलते जा रहे है| आज दुर्दशा यह है कि लोग हिमाचल को भांग पीने, सस्ती शराब और रेव पार्टीज़ का पर्यटक स्थान मानने लगे हैं। इससे हमारी देव भूमि के देव समाज एवं सनातन संस्कृति को ठेस पहुँचती है। महाभारत काल में पांडव, ऋषि मुनि, तपस्या, ध्यान के लिए, और अध्यात्म की दृष्टि से लाभ के लिये हिमाचल प्रदेश आया करते थे| हिमाचल के प्राचीन गौरवमयी आध्यात्मिक इतिहास को देखते हुए मेरी आयुष मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से यह मांग है की वहाँ आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, मैं आयुष मंत्रालय से आग्रह करती हूँ कि बिहार की तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में एक वैश्विक सतर का योग विद्यालय खोला जाए, जहां देश विदेश से लोग आएँ और अध्यात्म एवं आयुर्वेद का लाभ उठाए। जिससे हिमाचल के बैभव और संस्कृति को वापस स्थापित किया जा सके।

(इति)

Re: Need to establish a 'Bharatiya Rashtriya Gramin Bank'

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : देश मे RRBs Act,1976 के तहत स्थापित RRB की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।तब से लेकर आज तक ग्रामीण बैंक देश के 26 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी 22,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से लगभग 40 करोड़ आम जनता की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों का वर्तमान में आरक्षित लाभ लगभग 40,000/- करोड़ रुपए है तथा 50,000 करोड़ रूपये net worth हैं। ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का विभाजन इस प्रकार है- भारत सरकार- 50%, संबन्धित राज्य सरकार- 15%, sponsor bank- 35%। आज देश मे 12 स्पान्सर बैंक हैं जो कि देश के 43 ग्रामीण बैंक को प्रायोजन करने का काम करते हैं। जो राज्यों मे अलग-अलग संख्या मे हैं-UP- 3, Gujrat- 2, Mizoram- 1 ,Kerala- 1। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 40 करोड़ लोगों की सुविधा के लिय केन्द्रीय स्तर पर 'भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जो कि इन सभी बैंक को एक मुख्य अथॉरिटी के रूप मे संचालित करे। जिससे यह अलग-अलग स्पान्सर बैंक के संचालन से बाहर आ सके। इन बैंक मे व्यवसाय वृद्धि के अनुसार भर्ती हेतु निर्धारित नियमों के तहत अविलंब नई भर्ती, प्रमोशन की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिये। अस्थायी रूप से सेवा मे 20,000 से अधिक स्टाफ को स्थायी किया जाना चाहिये। (इति)

Re: Need to set up a Trauma Centre at Gajraula on National Highway 9

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 की ओर आकर्षित करता हूं। यह राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र, अमरोहा से गुजरता है इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों के घायल और हताहत होने की सूचना मिलती रहती है। इस एनएच के गजरौला क्षेत्र में चिकित्सा सहायता के अभाव में घायलो को उपचार के लिए आसपास के शहरों के अन्य हिस्सों में लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है। दिल्ली और हरियाणा सहित सभी पड़ोसी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हिंदू लोग विभिन्न त्योहारों पर गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए आध्यात्मिक स्थल गढ़मुकेश्वर आते हैं। इन त्योहारों पर हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं । इसके अलावा, सप्ताह अंत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल जाने वाले पर्यटकों की आवाजाही से भी इस राजमार्ग में वाहनों की भारी वृद्धि होती है। महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 - गजरौला में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया प्राथमिकता के आधार पर गजरौला में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए ताकि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार मिल सके।

(इति)

Re: Revised schedule to conduct Census of the Country

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I wish to raise an urgent matter regarding the delay of the 2021 census, which has traditionally been conducted every decade for the past 100 years. The COVID-19 pandemic has disrupted this schedule, and it is imperative for the Government to declare about the revised schedule to prepare and plan effectively to conduct the census along with estimation of the budget for the purpose. Transparency in this regard is crucial for public trust. In light of the Supreme Court's directions on Dalit reservations and the Rohini Committee's recommendations for OBCs, it is vital to collect caste-based data to ensure fair implementation of reservation policies. We seek not just explanations but concrete assurances from the Government. Timely action and clarity on these issues are essential for upholding democratic principles and ensuring equitable policy implementation.

(ends)

Re: Poor condition of the National Highway stretching from Canacona to Pernem in Goa

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): There have been massive landslides across the national highway stretching from Canacona to Pernem in Goa. The highways have also developed cracks, thus endangering the lives of motorists and people travelling on the route. There is a need for a thorough investigation to find out the cause and ensure that the huge amount of money spent on the construction of these highways does not go waste and accountability is fixed.

(ends)

Re: Need to set up an institute like AIIMS at Kasargod in Kerala

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): For the last 10 years people of Kasargod raising their voice in all platforms demanding that All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) should come up in Kasaragod, as the proposal for School of Medicine under Central University Kerala (CUK) was shelved. AIIMS is the only health institution capable of conducting research and studies beyond the health backwardness of Kasaragod to find the root causes of endosulfan poisoning. The Government has an obligation to put an end to endosulfan misery, which can affect generations at least. It is the responsibility of the State and Central Governments to fulfill it. AIIMS is needed for this backward district where 14 lakh people reside and 86 lakh people live around the so-called backward district. AIIMS is an essential for Kasaragod district more than any other district, considering the state of healthcare facilities available. There is huge barren and unutilised land in Kasargod and the place currently identified by Government of Kerala in Kozhikode seems to be sufficient to build up a biggest medical organisation like AIIMS. Considering these factors, it's the need of the hour to establish a health institute like AIIMS in Kasaragod, Kerala.

(ends)

Re: Need to increase the limit of MPLADS fund from five crore rupees to fifteen crore rupees

SHRI VARUN CHAUDHRY (AMBALA): The MPLADS Fund limit of Rs. Five crore was last revised in the year 2011-2012. It is a high time to revise the MPLADS fund limit as the construction costs have increased. A reference may be taken from the CPWD Rates of 2011 & 2024. Goods and Services tax is also levied on the materials for construction works. The present amount is too meager to fulfill the expectations of the people. Therefore, I request to the Minister for Statistics & Programme Implementation through your good self to increase the limit of Rs. Five crore to Rs. Fifteen crore.

(ends)

Re: Need to release funds under Border Area Development Programme in Banaskantha Parliamentary constituency

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : अवगत कराना है सरकार द्वारा Border Area Development Program (BADP) के अंतर्गत ग्रांट आवंटित किया जाता था परंतु अंतिम बार वर्ष 2019 – 2020 के लिए ग्रांट आवंटित हुआ था। उसके बाद ग्रांट को रोक दिया गया। जबकि 19 –20 की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सभी जिलों द्वारा भेज दिए गए। उसके बाद वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना भी मंगवा ली गई परंतु उसके बावजूद भी ग्रांट आवंटन नहीं किया गया। जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास रुक गया है। यदि यह ग्रांट आवंटित किया जाता है तो इससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास दुबारा से शुरू हो सकेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा सहित पाटन और कच्छ जिले पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, जिसमे से मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के दो तालुका के 17 गाँव सम्मिलित है।

आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि BADP के अंतर्गत रुके हुए ग्रांट को दुबारा शुरू कराने एवं कुछ और गावों को इस प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित कराने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to provide stoppage of various trains at Kheta Sarai Railway Station in Jaunpur Parliamentary Constituency

श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र जौनपुर है] यह विकास की बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है। लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए दिल्ली-मुम्बई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। गाड़ियों के ठहराव के अभाव में कई किमी0 दूर दूसरे स्टेशनों पर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। जनता वर्षों से खेतासराय रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव की माँग करती चली आ रही है। किन्तु सरकार का इस विषय पर कोई ध्यान नहीं है। जनता की परेशानियों को देखते हुए सरकार से माँग है कि जौनपुर के अन्तर्गत खेतासराय रेलवे स्टेशन पर दून एक्सप्रेस 13009 फरक्का एक्सप्रेस 13483-84 मेमो एक्सप्रेस 04217-18 गोदान एक्सप्रेस 11055-56 छपरा एक्सप्रेस 11059-60 आदि गाड़ियों का ठहराव किया जाय। और मुगलसराय से फैजाबाद 54109-10 वाराणसी से बालामऊ 54333-34 पैसेन्जर ट्रेन जो लगभग 8-10 वर्षों से बन्द पड़ी हुई है, इसका भी संचालन किया जाय, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम हो। (इति)

Re: Need to construct an over bridge/ under pass at level crossing No. 6A and 6B in Bisharatganj in Aonla Parliamentary Constituency

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : आपको अवगत कराना है कि आंवला लोकसभा की बिथरी विधानसभा क्षेत्र जनपद बरेली उत्तर प्रदेश अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत बिशारत गंज की आबादी 25000 होगी। यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन की क्रॉसिंग नंबर 6A एवं 6B अत्यंत व्यस्त मार्ग होने के कारण इस जगह ओवर ब्रिज/अंडर पास बनवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। बिशारत गंज, बरेली रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाया जाए जिससे यात्रीगण रेलवे लाइन कूद कर प्लेटफार्म पर ना जाए तथा बरेली से अलीगढ़-टूंडला-आगरा होकर बांदीकुई तक जाने वाली एकमात्र पैसेंजर को पुन: संचालित किया जाए।

(इति)

Re: Need to construct a road overbridge at level crossing No. 128 between Attur and Thalaivasal Railway Stations in Tamil Nadu

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): People of 13 villages viz. Kattukottai, Deviyakurichi, Kamakkapalayam, Arathi Agragaram, Navalur, Punalvasal, Sathapadi, Sathasivapuram, Sarvoy, Vadakumarai, Thenkumarai, Manivizhunthan South and Manivizhundan North in Salem District were against construction of Limited Use Subway (LUS) at Kattukottai- Sadhasivapuram- Thedavur Road in lieu of LC.No.128 between Attur and Thalaivasal Railway Stations as it is not in their interest. Eight panchayats have passed resolutions against it. Considering prevailing of current law and order problem, District Administration has temporarily withdrawn permission given for LUS. Kattukottai industrial cluster has more than 20 sago factories and to these factors approximately 300 loaded tapioca Lorries and tractors reach every day as well as sugarcane to various sugar mills and all these go through this level crossing gate. Many educational institutions and Government offices and hospital exist just near to this gate. Famous SHRI VADACHENNIMALAI BALASUBRAMANIAR Temple which attracts over 3.00 lakh devotees during Panguni Uthiram festival is also near to this level crossing. As per Traffic census of Highways Department and Number of gate closures at this Level Crossing & Train Vehicle Unit in 2024 will be more than 1.00 lakh which qualifies elimination of level crossing. Therefore, it is urged that instead of Limited Use Subway, Road Over Bridge be constructed at LC.No.128. (ends)

Re: Need to accord the status of classical language to Marathi

SHRI RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Hon. Speaker Sir, we have been demanding to accord the status of classical language to our Marathi language for the last many years. We do not only speak Marathi but also read, write and research in Marathi. It has got a glorious and historical heritage. The best quality literature is also available in abundance in Marathi language since ancient times. In the year 1278, Mhaïbhatt had written 'Leelacharitra' and Sant Dhyaneshwar composed 'Dyaneshwari' in 1290. Sant Eknath had written 'Bharud and added one more classic Epic named 'Eknathi Bhagmat Bhavarth Ramayan". The most adorable deity of Maharashtra Chhatrapati Shivaji Maharaj founded Maratha Empire. The archeological Department has the old and ancient records of Marathi scripts and texts as old as 1012 AD. We celebrate Marathi Language Day every year on 27th February. The Union Government has given the status of classical language to six different languages. When I was serving as a Minister in Maharashtra Government, I had sent a written request to Hon. Prime Minister in this regard on 19.2.2019. Marathi language fulfills the criteria to be accorded as a classical language. This is a matter of pride and honour for all the people of Maharashtra. Hence through you, I would like to request the Culture Minister to look into it personally and accord the classical language status to Marathi language.

(ends)

Re: Need to address the bottleneck in implementation of Jal Jeewan Mission Scheme in Krishna district in Andhra Pradesh

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Jal Jeevan Mission is not just one of the Flagship Schemes of the Ministry, but is one of the priority projects of the hon. Prime Minister and hence we have to work collectively to reach the goals. The Machilipatnam Parliamentary Constituency falls under Krishna district of Andhra Pradesh and if it is looked at the progress of Jal Jeevan Mission – 'Har Ghar Jal' which aims to provide every household with safe and adequate drinking water through individual tap connections is yet to be realized fully in Krishna district. Out of 3,75,600 households in Krishna district, only 2.2 lakh households – which constitute just 59%, much below the national average of 78 – have been provided with individual tap connections. Jal Jeevan Mission was started in 2019 and 100% progress is to be achieved by 2024. But the pace with which the Government is providing tap water connections in Krishna district, I feel, it takes 4-5 more years to achieve 100%. There is a need to push things faster. I once again request you to kindly look into bottlenecks and hurdles in implementing JJM in Krishna district and see that they are removed and 100% households are provided with individual tap connections. (ends)

Re: Collegium system for appointment of judges in higher Judiciary

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : कॉलेजियम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिससे अनियंत्रित शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग होता है। कॉलेजियम भारतीय समाज की विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिससे सामाजिक वास्तविकताओं के दृष्टिकोण और समझ की कमी होती है। कॉलेजियम योग्यता पर वरिष्ठता को प्राथमिकता देता है। कॉलेजियम लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करते हुए सत्ता को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर देता है। इन सबके परिणामस्वरूप एक ऐसी न्यायपालिका का निर्माण हुआ है जो एससी और एसटी के अनुभवों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इससे न्याय तक पहुंच में कमी आई है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव का चक्र कायम है। दशकों से, एससी और एसटी को प्रणालीगत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। उन्हें हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का शिकार होना पड़ा है। और फिर भी, कॉलेजियम प्रणाली इन मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है और इसके परिणामस्वरूप न्याय तक पहुंच में कमी आई है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव का चक्र कायम है। (इति)

Re: Need to take measures to promote production of foxnut seeds (Makhana) and also set up industry for makhana production in Purnia, Bihar

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मखाना का बोटेनिकल नाम यूरेल फेरोक्स सलीब (कमल का बीज) कहा जाता है। मखाना एक ऐसा खाध पदार्थ है जिसके उत्पादन में न तो खाध और न ही कीटनाशक का इस्तमाल होता है। खर्च के नाम पर काफी कम पैसे लगते है। इसकी मांग पूरी दुनियां में है। क्योंकि यह रासायनिक प्रभावों से मुक्त ऐसा फल है जो पौष्टिकता से भरपूर है।

हमारे देश में लगभग 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती होती है। जिसमे 80 से 90 फीसदी उत्पादन अकेले बिहार राज्य में होता है। इसके उत्पादन में 70 फीसदी हिस्सा मिथलांचल (मधुबनी, दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णिया) का है। लगभग 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) टन मखाने का बीज उत्पादन होता है। जिससे लगभग 40,000 (चालीस हजार) टन मखाने का लावा प्राप्त होता है। पारम्परिक रूप से अभी मखाने का उत्पादन किया जाता है। मखाना का फल कांटेदार एवं छिलकों से घिरा होता है, जिससे कि इसको निकालने एवं उत्पादन में बहुत कठिनाई होती है।

मखाना निकालने में लगभग 20 से 25 प्रतिशत मखाना बीज तालाब के सतह में ही छूट जाता है और वही 30 से 35 प्रतिशत मखाना छिलका उतारते समय खराब हो जाता है यानी बिहार में कुल मखाना बीज उत्पादन का 40 प्रतिशत ही मखाना तैयार हो पता है।

मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। किसानों से 200 से 300 रूपए प्रति किलो मखाना की खरीद होती है जबकि यह बाजार में 1200 से 2000 रूपए प्रति किलो बेचा जा रहा है।

अतः भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मखाना बीज उत्पादन हेतु उन्नत टेक्नोलॉजी कृषि यंत्र किसानो को उपलब्ध हो। वंही मखाना बीज से मखाना उत्पादन हेतु आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग की स्थापना बिहार राज्य के कोशी सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया में हो एवं सरकार मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें ताकि बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिल सके। (इति)

(1345/VR/GG)

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE – contd.

1345 hours

DR. SHARMILA SARKAR (BARDHAMAN PURBA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity. I would like to speak about an important issue which has a huge impact on doctor-patient relationship, and the critical decision making by a doctor while performing medical procedures.

Madam, being a medical practitioner and educator, I am acutely aware of the dedication the medical students and the doctors bring to the patient care. But it is essential to remember that doctors are humans too. A doctor never intentionally harms his patient. When a doctor unintentionally makes a mistake, it can cause a huge trauma to the mind of the concerned doctor and it takes several days to overcome. When a patient dies, the family believes that the doctor was negligent. Even if the negligence was minor, the magistrate has no option other than to give him 'imprisonment and fine' both as a punishment under Section 106 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

Therefore, I respectfully urge the hon. Health Minister and the hon. Law and Justice Minister to consider including 'or' between 'imprisonment and fine' so that either imprisonment or fine or both can be given as punishment depending upon the severity of the negligence. This would provide a stringent punishment for a clear medical negligence while it will award less punishment for minor mistake.

Madam, in addition to this, I would like to say that a clarification is also needed on what basis the negligence will be determined and who will determine the negligence. We are looking forward to the hon. Minister of Health and the hon. Minister of Law and Justice to kindly consider the above requests for the betterment of the society. Thank you, Madam, for giving me the opportunity.

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : सभापति महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र का एक बहुत ही मत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।, जिससे लाखों लोगों का जीवन कष्टदायी बना हुआ है। एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट टांडा में है, जो 1320 मेगावाट का यूनिट है, उसके एशडैम से लगातार जिस तरह से राख उड़ती है, जिससे लगभग पचासों गांवों में दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। जिसके कारण उनके खाने में, अगर वे बाहर बैठ कर खाना चाहें तो खाने में भी वह राख पड़ती है, रात में बाहर सोना चाहें, तब भी राख उनके बिस्तर पर पड़ती है। इस तरह से प्रदूषण के कारण वहां की हालत बहुत खराब है। वहां का जो एनटीपीसी प्रोजेक्ट है, वे सीएसआर के अंतर्गत, आरएण्डआर के अंतर्गत दूसरे जिलों में तो काम कराते हैं, लेकिन वहां पर इस समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अत: आपके माध्यम से विद्युत मंत्री और पर्यावरण मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का, जो सभी लोगों के जीवन के लिए खतरा बनी हुई है, उसका समाधान करने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अधिष्ठाता महोदया, मैं एक अत्यंत लोक महत्वप के विषय को, जो सभी माननीय सदस्य के क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जैसा महत्व लोक सभा और राज्य सभा का है, प्रदेशों में विधान सभा और विधान परिषद का है, उसी तरह से जिला स्तर पर ग्राम सभाओं का और क्षेत्रीय पंचायत का है, जिसे बीडीसी भी कहते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उसी ब्लॉक डेवल्मेंट काउंसिल से होता है, जिसमें क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य प्रधान से भी बड़े क्षेत्रफल से जीत कर आता है, लेकिन विडंबना यह है कि विकास में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। वह किसी प्रस्ताव को नहीं दे सकता है। सारे प्रस्ताव उस ब्लॉक डेवल्पमेंट काउंसिल के माध्यम से आते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होता है और सभी राज्यों के, सभी लोक सभा में उन ब्लॉकों के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य निर्वाचित हो कर आते हैं, तो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे प्रधान, विधायक और सांसद की भागीदारी विकास के मामलों में सुनिश्चित होती है। उन्हें मानदेय भी नहीं मिलता है। जैसे प्रधान को मानदेय मिलता है या अन्य जनप्रतिनिधियों को मानदेय मिलता है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी उन्हें मानदेय नहीं मिलता है। मैं पूरे सदन की तरफ से मांग करता हूँ कि अपने देश के, अपने उत्तर प्रदेश के, सिद्धार्थ नगर के क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मनरेगा से ले कर या वित्त आयोग के प्रस्ताव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और उनको मानदेय दिया जाए।

(1350/SAN/MY)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Madam, I would like to bring to the attention of this House a policy of this Government, which is completely motivated by rank and blatant crony capitalism.

The polyester staple fibre is a necessary raw material for our textile industry. The international price is Rs. 80 a unit whereas the domestic price is Rs. 110 a unit. This Government has come up with a quality control order, which is a non-tariff barrier, which prohibits imports into the country to protect certain manufacturers who are profiteering from the high price in India. Due to this high price, our textile units are becoming unviable. In fact, there are very few manufacturers in India, who make polyester staple fibre, but there are many textile units which need to use it as a raw material. This Government is interested in protecting the interest of only a few. In fact, the biggest beneficiary of this non-tariff barrier is an A-lister company. Everybody knows who I mean when I say 'one of the A-lister companies'.

This blatant crony capitalism must be scrapped; this quality control order must be withdrawn; and the Indian textile units must be able to import polyester staple fibre at international prices so that the products manufactured by them are competitive. This crony capitalism must end right now.

Thank you, Madam.

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र पनवेल नवी मुम्बई में नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। वर्ष 2025 में यहां से उड़ान शुरू होगी। जिस जमीन पर यह एयरपोर्ट बन रहा है, उस जमीन को अधिग्रहण करते समय बड़ा आंदोलन हुआ था। वह आंदोलन जिसके नेतृत्व में हुआ था, वह लोकनेते सांसद डी.बी. पाटिल जी के नेतृत्व में हुआ था। आंदोलन के समय तीन किसानों की जान भी चली गई थी। वहां के स्थानीय किसानों की मांग है कि इस एयरपोर्ट का नाम लोकनेते डी.बी. पाटिल के नाम पर दिया जाए। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के पास भी लिख कर भेजा है।

महोदया, इस एयरपोर्ट के पूरा होने के बाद, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पनवेल, नवी मुम्बई में बन रहे नए एयरपोर्ट का नाम लोकनेते डी.बी. पाटिल का नाम दिया जाए। धन्यवाद।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सभापति महोदया, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक बहुत बड़े पेंडिंग इश्यू के बारे में बोलना चाहता हूं। वर्ष 2021 के खरीफ फसल का क्लेम राजस्थान के चुरू लोक सभा क्षेत्र में जितनी राशि आई, उसमें से मात्र ढाई सौ करोड़ रुपये क्लेम का डिस्बर्समेंट हुआ। वहां काफी शिकायतें हुई, काफी किसानों ने आंदोलन किए। हम स्टैक्स ऐट लेवल असेसमेंट टेक्निकल कमेटी के पास गए।

महोदया, पिछले आठ महीने से स्टैक की किसी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कंपनियों ने गलत प्रीमियम लेते हुए क्लेम डिस्बर्समेंट भी गलत किया। वहां किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज 450-500 करोड़ रुपये का क्लेम पेंडिंग पड़ा हुआ है। यह पिछले 2-3 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्टैक की मीटिंग को जल्द से जल्द बुलाया जाए और किसानों के खरीफ वर्ष 2021 का क्लेम जो 550 करोड़ रुपये पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे डिस्बर्स किया जाए।

महोदया, साथ ही साथ हम वर्ष 2024 खरीफ का प्रीमियम 31 जुलाई को पे कर चुके हैं। आज तक वर्ष 2023 खरीफ डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो मैन एसेंस थी, उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसान एक-साल तक वेट करते हैं, लेकिन प्रीमियम नहीं मिलता है। मंत्री महोदय ने बात कही थी कि अगर किसान के क्लेम डिस्बर्समेंट लेट होता है तो 12 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2021 का क्लेम विद ब्याज किसानों को जल्द से जल्द से आवंटित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1355/SNT/CP)

*SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, thank you for this opportunity. In order to benefit the coastal areas of my Ramanathapuram Constituency, Karaikkal- Thoothukudi rail route was already planned. This rail route connects Karaikkal and Thoothukudi via Thondi, Ramanathapuram, Keelakkarai, Ervadi and Sayalgudi. This Scheme which was already in planning stage, should be implemented soon. The people living along the coastal areas will be benefitted by this rail route. This will also benefit them commercially. A new rail route from Manamadurai to Thoothukkudi via Parthibanur, Kamuthi, should be implemented in order to benefit the people of southern Districts of Tamil Nadu. Thangachimadam railway station was successfully operational 20 years ago. This station needs to be started again. Many trains pass through this rail route but do not have a stoppage Thangachimadam railway station. I urge that trains should have stoppage in Thangachimadam. Since this railway station was not functional, there was 30 acres of land available around this station. We can set up a Railway Yard in Thangachimadam. I once again urge that railway station at Thangachimadam should start functioning as before. People as a Group are staging agitations in this regard. I urge that this Thangachimadam railway station should be made operational very soon. Thank you.

*Original in Tamil

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): Respected Madam, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today.

On this occasion, I also thank Shri Narendra Modi ji who is an able, dynamic, and a visionary leader who aims to make India Viksit Bharat by 2047. With his blessings, I have won the Lok Sabha election. I also thank my constituency people for electing me to the Parliament representing from Mahbubnagar Parliamentary Constituency.

I would like to bring to your kind notice the need to set up a new Sainik School in Narayanpet district headquarters which falls in my Mahbubnagar Parliamentary Constituency in the State of Telangana. In this regard, I would say that, at present, there is no Sainik School in my entire constituency. My constituency people have urged me at various platforms whenever I go in my constituency.

Earlier, a survey was done and an extent of 50 acres of land was identified at Eklaspur village in Narayanpet district headquarters and Assembly Constituency for establishment of a Sainik School. But the then BRS Government has not allocated the land to establish the school. Therefore, I request the hon. Minister of Defence, through the Chair, to kindly intervene in the matter to expedite this project.

Thank you.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much, Chairperson Madam, for giving me this opportunity. I would like to bring forward an urgent matter for immediate action. An amount of around Rs. 23 crore is to be distributed in the Kasargod Constituency area under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), which includes the wages of skilled, unskilled labour and the cost of materials. This is for both the current financial year 2024-25 and the previous year 2022-23. This amount of wages is arrears despite the rule that wages must be paid within 15 days of employment. The workers are entitled to compensation for delay in payment of wages if the wages are not paid within 15 days from the date of completion of muster roll. The workers are also entitled to compensation at the rate of 0.05 per cent of the wages payable for each day of delay beyond the 16th day after completion of the muster roll. For example, the Development Block wise details of the dues for the financial year 2024-25 are as follows: in Kanhangad, it is Rs. 75 lakh; in Karadka, it is Rs. 1.5 crore; in Kasaragod, it is Rs. 35 lakh; in Manjeswaram, it is Rs. 69 lakh; in Nileswaram, it is Rs. 75 lakh; in Parappa, it is Rs. 1.55 crore; in Payyannur, it is Rs. 55 lakh; and in Kalliasseri, it is Rs. 1.5 crore. The highest is Rs. 1.54 crore due in the Parappa block and the lowest is Rs. 34 lakh in Kasaragod block. Madam, I urge upon the Government to intervene in the matter immediately. Thank you very much, Madam.

(1400/SJN/AK)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : सभापति महोदया, आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर समस्या भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत, विशेषकर जंगली रमी जैसे खेलों के संदर्भ में रखना चाहूंगा। इस डेंजरस ट्रेन्ड का एनॉलिसिस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खेल न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी गहरी छाप छोड़ रहा है।

1400 बजे (श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार वर्ष 2025 में 30 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा जंगली रमी का भी है, जिसमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं और इसकी लत ने कई लोगों को जिंदगियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जंगली रमी खेल की लत की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि नेशनल काउंसिल के अनुसार वर्ष 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के कारण 30 प्रतिशत युवा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

Nearly 3.5 per cent of the Indian adolescents suffer from gaming disorder. इसमें 40 प्रतिशत लोग अत्यधिक पैसे की लत का शिकार हो चुके हैं। कई केसेज़ में तो ये गेम्स व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्तीय संकटों का कारण बन गए हैं। उधार के कारण लोग आत्महत्या करते हैं।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : महोदय, जंगली रमी की विशेषता है कि यह एक बहुत ही आकर्षक और जल्दी जीत की उम्मीद देता है, लेकिन जब खिलाड़ी हार जाता है, तो अधिक खेलने की कोशिश करता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है।

हमें इस मुद्दे के प्रति जागरुकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि हम स्कूलों, कॉलेजों और समाज के अन्य हिस्सों में गेमिंग की लत से जुड़े खतरों के बारे में जानकारी फैलाएं। इसके साथ ही साथ कड़े नियम और उचित कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में अनुशासन और नियंत्रण स्थापित किया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वह सुरक्षित रहे और वह इस लत से बच सके।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, लिस्ट में 54 मेंबर्स का नाम है। मैं चाहता हूं कि सभी 54 मेंबर्स बोल सकें। इसलिए आप लोग संक्षिप्त में अपना विषय रखें, ताकि वह भी कार्यवाही का हिस्सा बन सके। सभी मेंबर्स 30 सेकेंड्स में अपनी बात रखें।

श्री खगेन मुर्मु – उपस्थित नहीं।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल जी।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं। हमारे देश में पानी की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। खासकर जलस्तर में निरंतर गिरावट के कारण पूरे देश में जल संकट गहराता जा रहा है।

यह समस्या मेरे लोक सभा क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में भी है, जो कि अधिक गंभीर विषय है। 'हर घर नल योजना' को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंच सके। इसके लिए पाइपलाइनों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और नियमित रख-रखाव की व्यवस्था की जाए। सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए तत्काल योजना बनाई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

माननीय सभापति : आपका विषय आ गया है। मैंने सबसे अनुरोध किया है कि 30 सेकेंड्स में अपनी बात कहिए।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : महोदय, वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज और विकास पर ध्यान दिया जाए। जैसे नहरों की मरम्मत और तालाबों का पुनर्निर्माण तथा नदियों का जल भी उपयोग में लाया जा सके।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You should have patience. Everybody will get an opportunity. सबको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री खगेन मुर्मु जी, आप 30 सेकेंड्स में अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : सभापति महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ यह तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं कि भारी बारिश और नदी की गहराई में कमी के कारण गंगा, फुलहर और कोशी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इससे अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

मेरा संसदीय क्षेत्र माल्दहा उत्तर और रतुआ-वन जैसे ब्लॉक के अंतर्गत खासमोहोल, नसीरुद्दीन टोला, भाषा राम टोला, कानतु टोला, महानंदा टोला और भिलाई मारी पंचायतों जैसे नदी किनारे के गांवों के आवासों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।

(1405/SPS/UB)

इसमें 300 से अधिक परिवार गंगा, फुलहर और कोसी कटाव से प्रभावित हुए हैं।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप मांग रख दीजिए। आप अपना विषय उठाइए। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना विषय उठाएं, जिसमें यह बताएं कि आपकी मांग क्या है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : सभापति महोदय, इससे हरिश्चंद्रपुर-II ब्लॉक के उत्तर और दक्षिण भकुरिया, रशीदपुर जैसे गांवों में लगभग 135 से अधिक परिवार फुलहर से प्रभावित हुए हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : महोदय, उपरोक्त सभी ग्रामीण दुर्भाग्यवश तीनों नदियों के कहर के कारण अपने घरों से विस्थापित होकर सड़कों पर आ गए हैं। … (व्यवधान) इन सभी लोगों को यथाशीघ्र उचित राहत एवं मुआवजा देकर पुनर्वासित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति : आप अपनी लास्ट लाइन कह दीजिए। More than 50 hon. Members have to speak. आपको यह समय बैलेट से अलग दिया गया है, इसलिए आपको तीन मिनट नहीं मिल सकते हैं।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : महोदय, मैं ऐसी परिस्थितियों में आपसे निवेदन करता हूं कि गंगा, फुलहर एवं कोसी के तटवर्ती बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से माननीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल जी एवं पश्चिम बंगाल सरकार बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था तुरंत करे। धन्यवाद।

DR. RICKY A. J. SYNGKON (SHILLONG): Sir, I want to draw your attention to the NGT ban on mining and transportation of coal in the State of Meghalaya which are the major activities of the people of our State. However, the sad part is that, in spite of the ban, there is a High Level Group which is indulging in mining and transportation of coal. This is very serious. The Government of the day in Meghalaya is turning a blind eye to this activity. Therefore, I urge upon the Government to take up this issue seriously either to ensure that the blanket ban is enforced or open it so that the people are allowed who have been dependent on this important industry for their livelihood.

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का मौका दिया।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बुन्देलखण्ड में आता है, जो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां के लोग ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में छुट्टा आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है। ये आवारा पशु किसानों की फसल को तैयार होने से पहले ही खा जाते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं।

माननीय सभापति : आपकी मांग क्या है?

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन) : सभापति जी, किसान अपने खेतों में बांस, बल्ली, तार की घेराबन्दी करने के बावजूद भी अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। किसानों के द्वारा मेहनत से तैयार की गई फसलों को आवारा पशुओं के नुकसान से किसान तबाही के कगार पर आ गये है, लेकिन इन छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या का निस्तारण सही तरीके से आज तक नहीं हो पाया है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को रहने के लिए बड़ी-बड़ी गौशाला बनाकर उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर दी जाए तथा उनकी देख-रेख के लिए वेतन पर लोगों की नियुक्ति की जाए, जिससे वे सही तरीके से उन पशुओं की देखभाल कर सकें। इससे आवारा पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ दूध और घी का उत्पादन भी होगा और साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। धन्यवाद।

(1410/MM/SRG)

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की मंशा सबका विकास, सबका विश्वास और इसी तारतम्य में उन्होंने सामान्य रेल डिब्बे बढ़ाने का काम किया है।

2500 रेल डिब्बे बढ़ाए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उज्जैन-झालावाड़ रेल लाइन के लिए उन्होंने पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, उसका डीपीआर जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद सभापति महोदय। राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव के लिए समर्पित गुजर समुदाय ने देश की हर लड़ाई में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए असंख्य वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। इसका उदाहरण सन् 1857 की क्रांति कोतवाल धन सिंह गुजर और बुलंदशहर के कालाआम में 140 गुजर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। 27 नवंबर, 1940 की उनकी यह मांग है कि गुजर रेजिमेंट बनायी जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि गुजर रेजिमेंट बनायी जाए।

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Sir, thank you for giving me this opportunity. We know about the devastating experience of landslides in Wayanad. On the same day, on the same night, Vilangad town of my constituency also experienced a massive landslide. Sir, 150 houses were destroyed. They lost everything but life. Mathew Kulathinkal, affectionately known as Mathew master of that area, drowned away in the landslide. So many farmers have lost everything. We request a special package for Vilangad. It is a necessity. I urge the Government to declare a special package for Vilangad.

*SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me this maiden opportunity to speak in Zero Hour. Today is World Tribal Day and would like to wish you all on this day. Onion is a main crop in my constituency. Onion producing farmers are facing serious problems today. The ban on onion export has been revoked but the export duty is very high which is around 40% and export value imposed is around 550 US dollars. So, our onion costs around Rs. 56 per kg. in international market whereas the onions from Pakistan are available as cheap as Rs. 28 per kg.

So, if the Government really want to ensure the financial benefit of these farmers, the export duty on onions should be removed immediately and NAFED should start procuring onions from the market committees and farmers directly.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के विषय को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करता हूं।

मान्यवर, सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना पर बहुत शोर मचाया और इस योजना के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इकाइयां लगी हैं, जिन्हें लोन भी मिला, परंतु आज तक

* Original in Marathi

उनको सब्सिडी नहीं मिल पायी है। जिला उद्योगों के द्वारा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी सब्सिडी का समायोजन और स्वीकृति पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं। जिला उद्योग केन्द्रों में पूछने पर बताया जाता है कि इसका सत्यापन सरकार द्वारा किसी प्राइवेट संस्था, जो किसी एक विशेष संगठन से जुड़ी हुई है, के माध्यम से कराया जाता है और अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही सब्सिडी को ऋण में सम्मिलित किया जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो छोटी-छोटी यूनिट लगी थीं, उन सभी को सब्सिडी दे दी जाए। जिनकी सब्सिडी स्वीकृत है, उनकी सब्सिडी उनको दी जाए।

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। मैं अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में पूनिया क्षेत्र है, वहां बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं। वहां कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे- सीता समाहित, लव-कुश जन्मस्थली, वाल्मीकि जन्मस्थली। वहां आने वाले लोगों को इलाहाबाद जाना होता है, प्रयागराज संगम जाना होता है, मध्य प्रदेश मैहर देवी के दर्शन के लिए जाना होता है और इसके लिए उन्हें काफी दूरी तय करनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि धनतुलसी से देंडूपुर का एक किलोमीटर का पुल है, उस पुल का निर्माण होना चाहिए।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, मैं इंदौर से आता हूं और इंदौर क्लीनीस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। लगातार स्वच्छता में नंबर वन है, स्मार्ट सिटी में नंबर वन है और इसके साथ-साथ 'एक पेड़ माँ के नाम से' के तहत एक दिन में 12 लाख पेड़ हमने लगाए हैं। देश में तेजी बढ़ता हुआ हमारा शहर इंदौर है। मैं सरकार से दो मांग करना चाहता हूं कि हमारे इंदौर में मेडिकल और फार्मा की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। सरकार इंदौर में फार्मा-ड्रग पार्क बनाए। मेरी दूसरी मांग है कि इंदौर में अच्छा गेहूं, चना और दुनिया का सबसे अच्छा सोयाबीन है और आलू है, जिसकी चिप्स बनती है। इंदौर में मेगा फूड पार्क बनाया जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

(1415/YSH/SMN)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर – उपस्थित नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह जी।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं देश के अति महत्वपूर्ण संस्थान, बनारस यूनिवर्सिटी के अति संवेदनशील विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति: आप 30 सैंकेड में अपनी बात पूरी करें और अपनी मांग रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदय, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। वहां पर अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हो पाया है। केवल एक व्यक्ति उस पूरी यूनिवर्सिटी का संचालन कर रहा है, जिससे पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। तीन साल से एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनी है, जो वहां पर सारे संचालन का काम करती है।

मैं मांग करता हूँ कि तत्काल संचालन के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी का गठन किया जाए।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter regarding the State of Kerala. The 128-year old Mullaperiyar dam poses serious threat to the lives and livelihoods of five million people spread over four districts. This is a major concern of the people of Kerala. There is a Government Report which says this. Ageing water storage infrastructure and emerging global risk published in the 11th series of United Nation University Institute for Water, Environment and Health.

Sir, our major slogan is water for Tamil Nadu and safety for Kerala. I urge the Government of India to decommission Mullaperiyar dam and build a new dam which ensures water for Tamil Nadu and safety for Kerala.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मैं सबको आदिवासी विश्व दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया का जो इलाका है, वह बहुत ही गरीब और अत्यन्त पिछड़ा इलाका है। यहां स्मार्ट मीटर का आतंक है। मीटर को रिचार्ज नहीं किया जाता है। मिडिल क्लास, गरीब और अत्यन्त पिछड़े लोगों पर मीटर के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है। यह स्मार्ट मीटर बहुत गलत है। इसकी रीडिंग की जांच बहुत ही आवश्यक है। मेरा आग्रह है कि कटिहार जिले में आज से तीन साल पहले विद्युत ग्रिड के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उसके लिए अभी तक सरकार ने जमीन नहीं दी है। विद्युत ग्रिड की जमीन आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। सबसे अधिक कटिहार और पूर्णिया में बिजली की कटौती हो रही है।

माननीय सभापति : आप सीनियर सदस्य हैं। शून्य काल में आप एक ही विषय को उठा सकते हैं।

श्रीमती संध्या राय (भिण्ड) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह और निवेदन करती हूँ कि जिस तरह नगरपालिकाओं का मास्टर प्लान बनाया जाता है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी पंचायतें हैं, उन पंचायतों का भी एक मास्टर प्लान बने, जिससे गांव की प्रत्येक गली, सीसी रोड तथा नाली सहित बनाई जाए। गांव में विद्युतीकरण हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि गांव में नल से जल योजना का काम अभी ठीक से नहीं चल रहा है। इसलिए व्यवस्थित योजना बने और इसके लिए शासन की तरफ से पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार हो।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा-मोहम्मदी के अटवा, पिपरिया इलाके में, कस्ता के पाल्हापुर इलाके में, महोली के अमिरता इलाके में, नन्ही कटघरा और धौरहरा के कैरातीपुरवा इलाके में बाघ तथा तेंदुए का इतना आतंक है कि पिछले दो महीनों में जब से हम लोग सांसद बने हैं, तब से तीन कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किसान अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इसकी रोकथाम की जाए। आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में बाघ आ जाए, तेंदुआ आ जाए, कहीं संसद में आ जाए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई है।

श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के संदर्भ में कहना चाहती हूँ कि दिनांक 1 अगस्त, 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश में इन वर्गों के लोगों को उपवर्गीकरण करके आरक्षण व्यवस्था दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में राज्यों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है।

(1420/RAJ/SM)

जिसमें वास्तव में लोगों का उपयोग राजनैतिक दल एवं सत्ता वोट बैंक के रूप में करने के आदेश हुए हैं। साथ इस आदेश द्वारा संविधान...(व्यवधान)

सुश्री बाँसुरी स्वराज (नई दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में सीवेज की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और दिल्ली सरकार पूरी तरह संवेदनहीन है। मेरे अपनी लोक सभा क्षेत्र, जैसे किदवई नगर, कोटला, मुनिरका, कीर्ति नगर, राजेन्द्र नगर और कई अन्य पॉश इलाके भी पूरी तरह डूब रहे हैं। यहां पर नालों की डिसिल्टिंग नहीं कराई गई है और सुपर सकर भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है।

मेरा यह केन्द्र सरकार से निवेदन है कि हाई लेवल कमेटी का गठन हो, ताकि दिल्ली सरकार की निष्कर्मता की जांच हो सके और इस स्थिति से... (व्यवधान)

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदय, केन्द्र शासन की स्मार्ट सिटी योजना है। मैं यह कहना चाहती हूं कि it is a money making racket. महाराष्ट्र में जितनी भी सिटीज हैं, जहां पर यह स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, वहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने पिछले तीन सालों से इलेक्शंस नहीं कराए हैं। इसीलिए जहां पर स्मार्ट सिटीज हैं, वहां पर अधिकारी और स्मार्ट सिटी के कॉंट्रैक्टर्स के बीच में नेक्सस है। शोलापुर में न रास्ता हैं, न एयरपोर्ट है और न ही पानी है।... (व्यवधान)

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से प्रयागराज में मेट्रो रेल के संबंध में, इस महती सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर पावन शहर प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना में हो रही विलंब की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इसका अखिलेश यादव जी की सरकार ने डीपीआर स्वीकृत कर दिया था, इसको लाइट मेट्रो रेल में वर्तमान सरकार ने परिवर्तित कर दिया है।...(व्यवधान)

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : सभापति महोदय, किसानों की उत्पाद को दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है। मेरे क्षेत्र के कई किसानों को अभी भी वर्ष 2022-23 सीजन की फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है। यह गंभीर मुद्दा है, जो किसानों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। तत्कालीन कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक शिकायत निवारक समिति का गठन किया था। समिति ने लगभग 12 हजार किसानों से दावा-पत्र दाखिल कराया था, उसके बाद समिति ने इसमें जांच-पड़ताल कर लगभग 6,690 किसानों के दावे का सत्यापन किया, लेकिन उन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है। मैं सरकार

से अनुरोध करती हूं कि तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर इस प्रक्रिया में तेजी लाएं।...(व्यवधान)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You have only 30 seconds. There are so many hon. Members who want to speak.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): But Sir, I have to breathe also. It is an important issue. Please give me some time.

It is an important issue concerning violation of rights, harassment and mental torture to lady officers in UCO Bank in Odisha. Several lady officers have been transferred to far off places like Gujarat, Kerala and Karnataka in clear violation of Clause 14 of the Transfer Policy of the Bank. It clearly states that women officers shall be transferred within the presently posted States or any other adjoining States.

These ladies, as disciplined officers, went and joined and worked there for two years. They suffered great hardships and personal inconvenience, innumerable difficulties, leaving their husbands, children and parents. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Prabha Mallikarjun.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, please give me two seconds. It is a very important issue.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude now. We have time constraint. I think you are well aware of it. There are so many Members who want to speak. I have given you an opportunity.

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Thank you, Sir, for permitting me to raise a matter of urgent public importance regarding upgradation of Mariyammanahalli SH25 road as National Highway.

Sir, this SH25 is an important major inter-State highway road which connects NH50, NH48 and NH69. It passes through three major districts of Central Karnataka, that is, Vijayanagar, Davangere and Shivamogga. I request the Minister of Road Transport and Highways to upgrade SH25 as National Highway from Mariyammanahalli to Shivamogga in the State of Karnataka. It is a long-pending demand of the people of central Karnataka. This upgradation will improve the socio-economic condition of this region.

(1425/KN/RP)

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, मैं किसानों के बहुत ही गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कर्नाटक में पिछले एक वर्ष में 1200 किसानों ने कर्नाटक सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आत्महत्याएं कर लीं। वहीं उनके एक मंत्री ने किसानों के लिए कहा कि किसान आत्महत्याएं इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि 5 लाख रुपये किसानों को मिलते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। हमारी भाजपा की सरकार ने 4 हजार रुपये उस समय दिए थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' में ऐड किए थे, उसको भी बंद कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कर्नाटक के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। केन्द्र के सांसदों की एक सर्वदलीय कमेटी बना कर भेजने की कृपा करें।

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) *There is a road in my Lok Sabha Constituency Birbhum which connects Lohapur Station to Morgram Station, this road is beside the rail line and is currently at a distressing state. Even after repeated requests, the Railway Department has taken no measures for this. The people who elect us as their representatives, the people who come to us with their requests and complaints, the Railway Ministry and the Railway Minster should be answerable to their questions instead of us. They should answer why even after repeated requests, this work has not been done. Construction of overbridges and underpasses are immediately required in Srikrishnapur and Pakuria.

सर, आप इतना भी टाइम नहीं देंगे और आप खुद तीन मिनट बोल कर गए। हम 30 सैकेंड में क्या बोल सकते हैं? हम तीन घंटे से बैठे हैं और फिर बोलने नहीं देंगे।

*The Railway Authorities have closed six roads in Birbhum Railway Colony and Shantipara. People won't be able to commute through these roads, 3000 tribal people will not be able to go out of their homes. The situation is the same in Harijanpally, Kasaipur, Dakbanglapara. 4000 people are inhabitants of these colonies. They are not being able to get out, they are unable to go to school. People take them immediate actions. Even after repeated complaints to their Railway Ministry why they aren't not responding and taking any necessary step, I demand an answer for that.

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि – उपस्थित नहीं।

सुश्री इकरा चौधरी जी।

---

*Original in Bengali

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूं।

अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम, 2013 को पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्कल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरीडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु वर्ष 2013 से अभी तक सर्कल रेट में उन्हें मुआवजे में फायदा नहीं मिल पा रहा है।

सहारनपुर व बागपत के सर्कल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं। इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है, वह बहुत कम है। जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अंबाला ग्रीन हाईवे में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। सर, मुझे दो मिनट दीजिए।

माननीय सभापति : दो मिनट कहां है?

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : सर, एक मिनट दे दीजिए। यहां किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें उपजाऊ जमीन का... (व्यवधान)

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की एक बड़ी संख्या जो वृद्ध और दिव्यांगों की है, उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

माननीय सभापति : आप लोग कृपया बोल कर मत जाइये। आनंद जी, आप लोग बोल कर मत जाइये।

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : महोदय, राष्ट्र सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार के द्वारा 200 से 500 रुपये तक पेंशन वृद्ध को और दिव्यांगों को दी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र खगड़िया और बिहार में केवल 400 रुपये मात्र वृद्ध लोगों को दिए जाते हैं। वहां जो वृद्ध हैं, वे दवाइयों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मेरी बस यही मांग है कि वृद्ध पेंशन को बढ़ा कर कम से कम 1000 रुपये किया जाये। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री हनुमान बेनीवाल जी, आप अपनी बात 30 सैकेंड में रखिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पंजाब राज्य से राजस्थान की नहरों में हरिके बैराज पर प्रवाहित किये जाने वाले दूषित जल और अपशिष्ट से उत्पन्न स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा।

राजस्थान रावी, व्यास और सतलुज का जल हरिके बैराज के डाउन स्ट्रीम से प्राप्त करता है। पंजाब राज्य में सतलुज नदी के आस-पास बसे शहरों व कस्बों का नगरीय अपशिष्ट व औद्योगिक अपशिष्ट नालों से होते हुए सतलुज नदी में मिलते हुए हरिके बैराज में आता है।

हरिके बैराज में आया हुआ जल राजस्थान के इंदिरा गांधी फीडर और फिरोजपुर फीडर में छोड़ा जाता है, इंदिरा गांधी फीडर का पानी राजस्थान को मिलता है और फिरोजपुर फीडर पंजाब व राजस्थान की संयुक्त नहर है।

माननीय सभापति : हनुमान जी, आप अपनी मांग रखिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सर, एक मिनट दीजिए। इन नहरों में अपशिष्ट से मानव जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मैंने पूर्व में कई बार इस विषय को उठाया और प्राप्त जानकारी के अनुसार अपशिष्टों के शोधन हेतु पंजाब में STP's & CETP's निर्माणाधीन हैं, लेकिन यहाँ और बेहतर उपाय करने की जरुरत है। एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश दिए, मगर कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ है। मैं अपनी मांग कर रहा हूं। मेरी मांग है कि भारत सरकार का केन्द्रीय प्रदूषण… (व्यवधान)

(1430/VB/NKL)

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बीकानेर से डबवाली नेशनल हाइवे, जो पहले से ही बना हुआ है और इससे आगे डबवाली से पानीपत तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। मेरा विनम्र सुझाव है कि इस प्रस्तावित हाइवे को पानीपत से आगे छपरौली, बड़ोत, बरनावा से होते हुए मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाए। ऐसा करने से यह हाइवे बीकानेर से इलाहाबाद तक जुड़ जाएगा, जिससे राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य आपस में जुड़ जाएंगे। इस मार्ग के निर्माण से तीन प्रदेशों के बीच यातायात सुगमता में वृद्धि होगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को एक नई दिशा मिलेगी।… (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : सर, मैं आपकी विसातत से जम्मू-कश्मीर के हवाले से बात करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन में यह बात लाना चाहता हूँ और इनसे इस बारे में जवाब भी चाहता हूँ।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): There is a time constraint. Please conclude within thirty seconds.

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : वर्ष 2019 में जब हमसे सब कुछ छीना गया। हमारे यहाँ रोज़गार का जो एक मीडियम था, वह छीना गया। वर्ष 2019 के बाद माइनिंग के हवाले से डिसीजंस लिये गये, चाहे जम्मू में तवी रिवर हो, झेलम रिवर हो, सिंधु रिवर हो, ये हमारे यहाँ रोज़गार का जरिया थे।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please put your demand.

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी (श्रीनगर) : वहाँ से स्मॉल स्केल्स माइनिंग होती थी। उनमें से रेत और बजरी वगैरह निकाली जाती थी। उस पर बैन लगाई गई है। बड़ी-बड़ी कम्पनीज को आउटसोर्स किया गया है।… (व्यवधान)

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

Sir, there are cases of elephant menace and intrusion of elephants in the farm lands across Kanakapura, Sathanur and Bannerghatta regions of my

Constituency. … (*Interruptions*) There is a need to build barricades along a stretch of 31 kilometres to prevent elephant intrusion. … (*Interruptions*) If the farmers die, they get only Rs. 15 lakh as compensation, and if the employees die, they get Rs. 20 lakh as compensation. … (*Interruptions*) The amount should be equal. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपकी बात रेकॉर्ड में आ गई है।

… (व्यवधान)

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आदिवासी दिवस, क्रांति दिवस, नागपंचमी, पतैया और पुतरी के त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए, अपनी बात रखना चाहता हूँ।

घाघरा नदी के कटान से पूरा भोजपुरवा गांव नदी में विलीन हो गया है। घाघरा नदी से खरीदनिपनिया, पुरुषोत्तमपट्टी, बिजलीपुर, सुल्तानपुर, ताहिरपुर, खादीपुर, किशुनपुर, कोटवा, तुर्तीपार, महुआपार, खैरा, दुहा, बिहरा… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : बलुआ, अफगान, लक्ष्मीपुर, बांसघाट, घाटी, सरैया खरात आदि गांवों गंडक नदी, खनुआ नदी और घाघरा नदी से लोग प्रताड़ित हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी मांग क्या है?

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : मेरी मांग है कि जिनके घर नदी में विलीन हो गए हैं, सरकार कम से कम उनके कर्ज माफ करे और उनको पुन: बसाया जाए। उनकी बिजली बिल भी माफ की जाए।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर **(**दादरा और नागर हवेली**) :** महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, मेरे प्रदेशवाससियों की जनता को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनता आदिवासी समाज से है। यहाँ प्रतिवर्ष आदिवासी जातियों में जागरुकता फैलाने एवं उनके अधिकारों के समर्थन और संरक्षण के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व के आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना है। आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा दिसम्बर, 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस दिन आदिवासी समाज के लोग अपने देवी-देवताओं की पूजा करते हैं।

(1435/VR/PC)

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय उड्डयन मंत्री जी, जो यहां बैठे हुए हैं, उनसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं।

महोदय, मैं बुंदेलखंड, वीरों की भूमि से आता हूं। … (व्यवधान) हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने हमें हाल ही में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दिए हैं – डिफेंस कॉरिडोर,

बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और बल्क-ड्रग-पार्क। मेरा माननीय एविएशन जी से आग्रह है कि झांसी बुंदेलखंड का गेटवे है। वहां अगर माननीय मंत्री जी एक एयरपोर्ट स्थापित कर देंगे, तो पूरे बुंदेलखंड का बहुत आर्थिक विकास होगा और हमारे पूरे क्षेत्र को, विशेष रूप से … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : श्री उम्मेदा राम बेनीवाल जी।

… (व्यवधान)

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के मारवाड़ के अति-महत्वपूर्ण मुद्दे मरु गंगा लूणी नदी के संरक्षण के संबंध में बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बालोतरा, जोधपुर, पाली टैक्सटाइल उद्योगों से खतरनाक रसायन युक्त और गंदे नालों का पानी नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। इसके कारण मरूगंगा के नाम से प्रसिद्ध लूणी नदी पूरे तरीके से दूषित हो चुकी है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि टैक्सटाइल फैक्ट्रियों को ऐसा न करने के लिए पाबंद करें। जोधपुर हाई-कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद भी प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और फैक्ट्री मालिक मनमर्जी से गंदा पानी नदी के अंदर छोड़ रहे हैं। इससे किसानों के खेत दूषित हो चुके हैं। पीने का पानी और तालाब भी दूषित हो चुके हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री सालेंग ए. संगमा जी।

… (व्यवधान)

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Sir, right now thousands and lakhs of Rohingya refugees are entering the North Eastern States as illegal immigrants. Thousands of kilometres of border area is insecure. Immediate serious preventive measures should be taken by the Central Government. We do not have a proper security in our State. Thousands of people are suffering right now. Yesterday itself, more than thousands of Bangladeshis have illegally tried to penetrate Meghalaya through the border.

Sir, through you, I would like to apprise the hon. Union Home Minister to take preventive measures immediately.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति जी, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। महोदय, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां जो अपने लोग हैं, उनकी चिंता की जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ट्वीट करके, जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधान मंत्री हैं, उनको बधाई दी, लेकिन यह भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं, उनकी शांति, सुरक्षा, विकास, सब चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने जब ट्वीट किया, जब उनको बधाई दी, तो वहां हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की। … (व्यवधान) न ही उसका उल्लेख किया, न ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। … (व्यवधान) ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये

लोग वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? … (व्यवधान) गाज़ा को लेकर आपने बड़ी-बड़ी बातें की थीं? … (व्यवधान) गाज़ा को लेकर आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहां आकर आप नहीं करते हो। … (व्यवधान) सर, ऐसा कैसे हो सकता है? … (व्यवधान) गाज़ा को लेकर तो … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती जून मालिया जी।

… (व्यवधान)

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): Sir, through you, I would like to raise an important matter related to the Anganwadi workers. *....(Interruptions)*

Sir, the honorarium payable to the Anganwadi workers and helpers under the Anganwadi services was last enhanced almost six years ago by the Union Government vide Ministry of Women and Child Development's Order dated 20th September, 2018 with effect from October 2018. The wages of Anganwadi workers and helpers were hiked from Rs.3000 to Rs.4500 per month and from Rs.1500 to Rs.2250 per month respectively. *....(Interruptions)* Here, the State Government also contributes 40 per cent to the amount payable to the Anganwadi workers and helpers. *....(Interruptions)*

I would urge the hon. Minister to kindly consider an enhancement of the honorarium keeping in view the challenges of ICDS responsibilities. Thank you, Madam.

(1440/CS/SAN)

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे (इटावा) : महोदय, आरक्षण के जो विरोधी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ: 'कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, वह भी तुम्हारा है, तुम जो कहो, वह सच है, हम जो कहें, वह झूठ है।" भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों में जजों की भर्ती आरक्षण व्यवस्था के आधार पर की जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द कर वन नेशन वन एजुकेशन के तहत शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देश में समान एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाकर लागू किया जाए, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाए। देश व प्रदेश के कार्मिकों को भविष्य की सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल की जाए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आपका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

… (व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

List of members who have associated themselves with the Issues raised under matters of urgent public importance

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Varun Chaudhry	Shri Navaskani K.
Shri K. C. Venugopal	Shri Navaskani K. Shri N. K. Premachandran Shri Hibi Eden
Shri S. Supongmeren Jamir	Shri N. K. Premachandran Shri Navaskani K.
Shri Daroga Prasad Saroj	Shri Navaskani K. Shri Jagdambika Pal
Shri Murari Lal Meena	Shri Navaskani K.
Shri D. M. Kathir Anand	Shri Navaskani K.
Shri Richard Vanlalhmangaiha	Shri Navaskani K.
Shri Rahul Singh Lodhi	Shri Navaskani K.
Shri Abu Taher Khan	Shri Navaskani K.
Adv. Adoor Prakash	Shri Navaskani K.
Dr. Mohammad Jawed	Shri Navaskani K.
Adv. Gowaal Kagada Padavi	Shri Navaskani K.
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Navaskani K. Shri N. K. Premachandran Shri K. C. Venugopal
Shri C. N. Annadurai	Shri Navaskani K.
Shri Malaiyarasan D.	Shri Navaskani K.
Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	Shri Navaskani K.
Shri Devesh Shakya	Shri Navaskani K.
Shrimati Lovely Anand	Shri Navaskani K.
Shri Bhaskar Murlidhar Bhagare	Shrimati Supriya Sule

	Shrimati Kanimozhi Karunanidhi
Shrimati Smita Uday Wagh	Shri Naresh Ganpat Mhaske Dr. Hemant Vishnu Savara Shri Anup Sanjay Dhotre
Shri Shafi Parambil	Shri Hibi Eden
Dr. Shrikant Eknath Shinde	Shri B. Manickam Tagore Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane Shri Ravindra Dattaram Waikar Shri Vishaldada Prakashbapu Patil Shri Shrirang Appa Chandu Barne Shri Balashowry Vallabhaneni Adv. Chandra Shekhar Shri Rajesh Ranjan Dr. Hemant Vishnu Savara Shri Naresh Ganpat Mhaske Shrimati Smita Uday Wagh
Shri Jagdambika Pal	Dr. Rajkumar Sangwan
Dr. Shiv Pal Singh Patel	Shri Jagdambika Pal
Shri Dilip Saikia	Shri Jagdambika Pal
Shri N. K. Premachandran	Shri Jagdambika Pal
Shri Chandan Chauhan	Shri Jagdambika Pal
Shri Gurjeet Singh Aujla	Shri Jagdambika Pal
Shri Rajmohan Unnithan	Shri Jagdambika Pal

MOTION RE: REFERENCE OF WAKF (AMENDMENT) BILL TO JOINT COMMITTEE

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Hon. Minister Shri Kiren Rijiju.

1441 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I rise to move:

> "That the Waqf (Amendment) Bill, 2024 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:-
>
> 1. Shri Jagdambika Pal
> 2. Dr. Nishikant Dubey
> 3. Shri Tejasvi Surya
> 4. Smt. Aparajita Sarangi
> 5. Dr. Sanjay Jaiswal
> 6. Shri Dilip Saikia
> 7. Shri Abhijit Gangopadhyay
> 8. Smt. D.K. Aruna
> 9. Shri Gourav Gogoi
> 10. Shri Imran Masood
> 11. Dr. Mohammad Jawed
> 12. Shri Mohibbullah
> 13. Shri Kalyan Banerjee
> 14. Shri A. Raja
> 15. Shri Lavu Srikrishna Devarayalu
> 16. Shri Dileshwar Kamait
> 17. Shri Arvind Sawant
> 18. Shri Mhatre Balya Mama Suresh Gopinath
> 19. Shri Naresh Ganpat Mhaske
> 20. Shri Arun Bharti
> 21. Shri Asaduddin Owaisi
>
> and 10 Members from the Rajya Sabha;
>
> that in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee,

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

HON. CHAIRPERSON: *The question is:

"That the Waqf (Amendment) Bill, 2024 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:-

1. Shri Jagdambika Pal
2. Dr. Nishikant Dubey
3. Shri Tejasvi Surya
4. Smt. Aparajita Sarangi
5. Dr. Sanjay Jaiswal
6. Shri Dilip Saikia
7. Shri Abhijit Gangopadhyay
8. Smt. D.K. Aruna
9. Shri Gourav Gogoi
10. Shri Imran Masood
11. Dr. Mohammad Jawed
12. Shri Mohibbullah
13. Shri Kalyan Banerjee
14. Shri A. Raja
15. Shri Lavu Srikrishna Devarayalu
16. Shri Dileshwar Kamait
17. Shri Arvind Sawant
18. Shri Mhatre Balya Mama Suresh Gopinath
19. Shri Naresh Ganpat Mhaske
20. Shri Arun Bharti
21. Shri Asaduddin Owaisi

* Original in Hindi

and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee,

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session;

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to request the hon. Minister … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Without the permission of the Chair, how can you speak?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Who has given you the authority? No, I have not given you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: How can you talk directly?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You should address me. You have not addressed me. You are a senior Member.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am now getting your permission. … (*Interruptions*)

Sir, the IUML, Indian Union Muslim League, has got three Members in this House. Their representative is not there in this Committee. I would like to request the Government, through you, to include a representative of the IUML party also in this Committee.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

(1445/SNT/IND)

BHARATIYA VAYUYAN VIDHEYAK – Contd.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Hon. Minister Shri Kinjarapu Rammohan Naidu.

1445 hours

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024.

In fact, I would like to thank the Chair, first of all, for what was supposed to be a three-hour debate, yesterday, went on up to five hours and also had 36 speakers speaking on this important Bill. Adoor Prakash ji, Rajiv Pratap Rudy ji, Rajeev Rai ji, Sougata Ray ji, C. N. Annadurai ji, Magunta Sreenivasulu Reddy ji, Dileshwar Kamait ji, Shrirang Appa Chandu Barne ji, Bajrang Manohar Sonwane ji, Kishori Lal ji, Ganesh Singh ji, Abhay Kumar Sinha ji, Rajesh Ranjan ji, Sachithanantham R. ji, Malvinder Singh Kang ji, Vijay Kumar Dubey ji, Dayanidhi Maran ji, M. P. Abdussamad Samadani ji, Rajkumar Sangwan ji, Ramesh Awasthi ji, Selvaraj V. ji, D. Ravi Kumar ji, N. K. Premachandran ji, Adv. Gowaal Kagada Padavi ji, Praveen Khandelwal ji, Hanuman Beniwal ji, Adv. Chandra Shekhar ji, Ravindra Dattaram Waikar ji, Sudha R. ji, Praveen Patel ji, Mohammad Jawed ji, Tapir Gao ji, Zia Ur Rehman ji, Ajay Bhatt ji, Jagdambika Pal ji, and Anand Bhadauria ji. So, almost 36 Members have participated in this debate. Not only have they participated, they have given some valuable suggestions and also passionately been involved in this debate.

I would like to remind the House, 20 years back, if you would have seen any civil aviation topic that has been discussed in the House, the participants were mainly coming from technical background or they were coming from these major metropolitan cities where the presence of airports has been maximum. But yesterday, if you had witnessed the debate for five hours, we have seen hon. Members from the length and breadth of this country, from the remotest areas of this country, from the most backward areas of this country, have passionately spoken on this Bill. That is the change this Government has brought in and the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji has brought in to the civil aviation industry.

The civil aviation industry has witnessed unimaginable growth in the last 10 years since Modiji has taken charge as the Prime Minister of the country. He had a special focus; he had a special vision for the civil aviation industry and because of which he understood the importance of improving the infrastructure

in civil aviation. That is why, what was a total of 74 airports in 2014 has gone up to 157 airports, which has more than doubled in this country today. If you look at the passenger growth in this country, 60 million passengers were there domestically in 2014, which has gone up to 153 million, which has more than doubled in 2024. Also, the international passengers have grown up from 43 million to 66.7 million. As you know, just like any travel industry which took a big hit during the COVID time, aviation also took a big hit. Even though it took a big hit, within three years it stood back on its feet. It not only crossed the pre-COVID numbers, but also we are at an all-time high in the passenger growth in the country, and today we stand as the third largest aviation economy in the whole world. That is the change hon. Prime Minister, Narendra Modi ji has brought in the last 10 years for the Civil Aviation Ministry.

Also, I would like to thank all the previous Ministers who have worked on this, especially my predecessor Jyotiraditya Scindia ji, who had constantly worked for the upliftment of the Civil Aviation Ministry and brought in a lot of policy changes. In fact, I would also like to remember our previous hon. Minister, Ashok Gajapathi Raju ji, who was also handling this and who was from our party also at that time. With this growth, it is very important we look into the future also. This is not just for the 10 years that we are proud of. We are in the third place right now. Under the leadership of the hon. Prime Minister, we want to see India become number one in the domestic economy. If you want to see India in that number one position, there has to be proper legislative backing, there has to be good policy making, there has to be good policy which drives the civil aviation industry in that direction. And that is where this Bharatiya Vayuyan Vidheyak comes into play, and which is why I would like to go into a little bit more detail of the Bill also.

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 से पहले इंडियन एयरक्रॉफ्ट एक्ट,1934 था। This was the pre-Independence era Act. Under the British rule, this Act was formed. The Act was promulgated because of an International Aircraft Convention which was formed in 1919. वर्ष 1919 में जो कन्वेंशन बना था, उसके हिसाब से एयर क्रॉफ्ट बिल, 1934 प्री इंडिपेंडेंस ईरा में लेकर आए। इसके बाद वर्ष 1944 में शिकागो कन्वेंशन भी आया। शिकागो कन्वेंशन आने के बाद आई.सी.ए.ओ. का फार्मेशन हुआ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है।

(1450/RV/AK)

आई.सी.ए.ओ. यूनाइटेड नेशन्स की एक एजेंसी थी। शिकागो कन्वेंशन के बाद जो आई.सी.ए.ओ. बना, उसमें 193 देश शामिल थे। Regularly, all these 193 countries used to sit, discuss, deliberate and formulate the standard and recommended the practices, which are again supposed to be implemented by all the member countries within the ICAO.

India has also been a very strong participant of the ICAO, and we have tried to formulate our own laws by harmonising whatever the Standards and Recommended Protocols (SARPs) are there from the ICAO. This has been happening for a long time. While we have been doing this, the 1934 Act, which was there, was amended 21 times. It was amended in such a way that whenever some SARPs were coming in, we were just attaching it to the old Bill. There was no proper structure. In the end, right now the way it has become is that there is no clarity. There is a lot of ambiguity in the existing Act that is there right now, and there is a lot of confusion. In some places, there is a lot of redundancy also. So many subordinate legislations have been brought in; so many rules have been brought in; so many regulations have been brought in, there was no proper structure for the whole Act which is why a proper structural difference was supposed to be brought in. This was done with the formation of this new विधेयक, which is the भारतीय वायुयान विधेयक.

The first thing that we have tried to address is, structurize the whole Bill. We have structurized by giving the DGCA a separate chapter. We have told what is the DGCA and what are the powers of the DGCA which is the Directorate General of Civil Aviation. We also have the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS). Similarly, we have another separate chapter for it, and the functions and the powers have been properly listed out for it. There is also the AAIB which is the Aircraft Accident Investigation Bureau and powers of the Central Government.

सर, पहले ऐसा होता था कि पावर्स कहीं और लिखे हुए हैं और फंक्शंस कहीं और लिखे हुए हैं, रूल्स कहीं और लिखे हुए हैं। आई.सी.ए.ओ. का ऑब्जर्वेशन था कि सभी एक प्रिंसिपल एक्ट में होने चाहिए, जो कि सिविल एविएशन की एक हार्मोनी क्रिएट करे। इस बिल के तहत सिविल एविएशन में वह हार्मोनी हम लेकर आए हैं। Other than this, we have tried to reduce the redundancies. इसके एक्ट में पहले जो गैप्स थे, उसको भी ठीक करने की कोशिश हम इस भारतीय वायुयान विधेयक में कर रहे हैं।

महोदय, इसके बाद दूसरी चीज यह है कि हमने इसमें डेफिनिशन्स को जोड़ा है। We have brought in definitions for design, maintenance and manufacture into the Bill. पहले का जो इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट था, we did not have design at all, we did not have the word 'maintenance' at all and there was just manufacture as a word, but it was not defined. But today, under the leadership of Prime Minister Modi ji, we see a strong sense of आत्मनिर्भरता being formed in this country, and civil aviation, taking an inspiration from that आत्मनिर्भरता, is trying to achieve a position for India in the future where we are not only operating planes in this country, but we are also designing planes, we are manufacturing planes and we want to export planes to the whole world. So, that is the situation we want to create, and that is going to happen. Exactly, that is going to happen because of the भारतीय वायुयान विधेयक and that is going to come.

We have especially added the word 'design', and adding of the word 'design' is going to create an area where a lot of industry players are going to come, which is going to improve the design area of the manufacturing. Already the HAL is manufacturing Hindustan 228, which is a 19-seater plane; Dhruv is there from HAL, which is a 14-seater helicopter; and NAL is also making another plane. If you bring in these changes in the legislation, then the ICAO will recognise India as a State of design, which will improve our prospects globally also to bring in talent that will attract in creating design here. Further, whatever we design or manufacture is also going to be accepted worldwide.

So, it was very important for us at this stage with the changes that are happening throughout the country, to define design, maintenance and manufacture, which is the major driver in the civil aviation sector today.

(1455/UB/GG)

That is what we have brought into the Bill today. Before bringing this Bill here, a lot of wide consultations have happened both internally and externally. We have received the feedback from the public. There is a feedback from internal departments like DGCA, BCAS, AAI, AERA, and AIB and from external departments like the Ministry of Defence, the Ministry of Home Affairs, the Ministry of External Affairs, the Finance Ministry, the DPIIT, and the Department of Telecom. All these were widely consulted and all their feedback was taken in before we brought in this Bharatiya Vayuyan Vidheyak into the august House.

There is another important feature that this Bill is addressing. This is the feedback that we have received from the pilots, especially, the pilots who are getting trained and trying to obtain their CPL – Commercial Pilot License. Sir, before they obtain this Commercial Pilot License, there is one certificate that is required which is the Radio Telephony Restricted Certificate. This Radio Telephony Restricted Certificate which was supposed to be given on the basis of the previous Act was supposed to be given by the Department of Telecom. Now, before obtaining the CPL, they had to go to the Department of Telecom and get this license. Once they get the license from the Department of Telecom, they come back to DGCA which is under the Ministry of Civil Aviation and they get the Flight Radio Telephony Operator License. Once they get the Flight Telephony Operator License, then they again get the Commercial Pilot License which is the CPL.

Now, regarding this process of going to two departments just for that Certificate for Radio Telephony, there was a lot of feedback from the pilots and especially, the training industry that this is creating a lot of problem for them. Going through two departments, you would know how difficult the system gets over the years when there are different kinds of people and especially, DGCA which has the expertise for the radio telephony in aviation which is why it has the capacity to give the Flight Radio Telephony Operator License. So, the feedback from the industry has been to shift this from the Department of Telecom and put it within the Ministry of Civil Aviation. With this Bill, we have addressed that feedback and we have shown that this is the Government which listens to the public, and which does what the public needs and that is the change that we have brought in this Bill also.

Another important change that we have brought with this is regarding the appeals section. I thought a lot of people would talk about this but not a lot of people have thrown light on this but there have been a lot of inconsistencies in the earlier Act related to the appeals. There was a provision for appeal against financial penalties only. Regarding administrative penalties, there was nothing written in the earlier Act which was addressing the appeals on administrative penalties. Only for financial penalties, there was an appeal and there was only one appeal that was allowed. But now we thought that when we are trying to

change this Act by bringing in a new Bill, we have decided that we are going to implement the principles of natural justice and how the industry treats the appeals, how other departments are treating the appeals, the same way we are going to bring that structure into this. That is what we have done here also. So, anytime any action is taken, the first show-cause notice will be issued to the person against whom the action is being taken. He will be properly heard and he will be given a chance to go for two appeals and there will be a proper tribunal also after the appeals so that he can avail of the principle of natural justice. We have accommodated that here. Just like I said earlier, only for financial penalty, the appeal was there. Now, we have added administrative enforcement also so that there is an opportunity for appeal. Earlier, only the Indian Aircraft Act, which is the principal Act, carried certain provisions regarding the action of suspension of licenses, certificate or approvals.

The other sections which come under restrictions were addressed by some other rules. Now, we have brought everything into the principal Act so that there is a legislative backing, there is a clear flow of instructions on how the licenses or certificates get suspended, how they get restricted or how they get cancelled. All this has been brought into the principal Act which is going to create a lot of clarity on how the appeals and also how the licenses are being done in this country.

These are some of the important points that the Bill covers and I feel that whatever issues the hon. Members have raised regarding the Bill, I was able to cover with this and especially, there has been some discussion on the naming of the Bill also. I do not see the problem. I have calculated how many words are there in the act.

(1500/SRG/MY)

Sir, 11,643 words are there in the entire Act. Out of 11,643 words, only three words are there, that is, *Bhartiya Vayuyan Vidheyak*, and the rest of the text is completely in English. So, there is no way how people feel that we are imposing certain things. In fact, when we are bringing these three words also everyone should feel happy. I was hearing someone saying that you come from Telugu land and you are accepting this. Of course, I will accept it. It is an Indian language and we are all proud of all the Indian languages that are there.

I would also like mention one thing in respect of *Bhartiya Vayuyan Vidheyak.* In Telugu also, Bhartiya is Bhartiya only. In Telugu, Vayu is also Vayu only. So, I treat this as a Telugu name also, and I treat it as a Sanskrit name also; I treat it as any other Indian language. So just by bringing the name of this act, I feel that everyone should feel proud of this and not oppose the naming of the Act. That is one point which I want to mention here.

Other than this, one of the important issues that have also been raised during the speeches was the airfares issue. It has constantly been coming up, let it be during `Zero Hour', let it be during Private Members' Bill or let it be during the Question Hour. Through the Bill also, many Members have raised this issue. In fact, I have already mentioned this after taking charge as the Minister also that one of my top priorities would be to make the airfares affordable and accessible to the common man of this country.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): There should be some mechanism for flexibility.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I will get it done.

The intention of the NDA Government is this. Till 2014, civil aviation was always like it was for certain sections of the civilized society. It was like civilized aviation. But once hon. Prime Minister Narendra Modi Ji has taken charge, civil aviation was considered as civilian aviation, and that is what our commitment is even today also. To make it civilian aviation, this is a very important point which the Ministry is also looking at very seriously. But I would also like to tell the House that we have to understand the dynamics around the airfares also. It is not just the airlines saying that tomorrow they will just put this air price at so and so price. There is a certain mechanism. There are a lot of other factors which are included in the airfares like the ATF, the fuel cost, the airport security fee, user development fee, landing charges, and a lot of other factors like market demand, and especially when some vacations are there or some special events are happening. So, there are a lot of dynamic factors which get included in deciding the fare of this thing.

Yesterday also when a lot of Members were speaking, they were also mentioning how certain carriers have gone out of system also. Some important airlines like Jet Airways and Deccan Airways and some other important airways which were very optimistic in the area of civil aviation, have all exited the aviation market. So, we have to create a balance. Now if you see, if we create so much pressure on the airlines that they totally are not in a situation to run, then we do not have any planes to run. So, we have to create a balance, and that is the balanced approach that the Ministry is also looking at. There is a balanced approach where the airlines also should not misuse or take advantage of the position of the passenger, and at the same time, we are creating a level playing field so that the airlines also operate at a certain stage in the country.

On the directions of the hon. Speaker Sir also - last time when there was a discussion on this - he said, 'why do you not meet the airlines?', we are doing it from the Ministry. We are having meetings with the airlines industry, and we are trying to ensure that there is no misuse or there is no disadvantage for the passengers. I would like to mention this in the House also because a lot of Members have raised this issue across the Benches and even the hon. Speaker has also taken cognizance of this. We are thinking of setting up an online mechanism to take in grievances not just from the MPs, but also from the public. We will put up a team in the Ministry which is going to specifically look about these issues where they feel undue advantage has been taken or unnecessarily some unreasonable hike has happened in airfares. Whenever there is an issue like this, we are going to create an online system which will take care of the grievances. You can put in your grievances and with timely response, we are going to address this one. We are going to make sure that there is no undue advantage that has been taken by anyone. I want to tell this to the hon. Members of this house.

Other than this, one important scheme that has been brought in by the hon. Prime Minister which I would like to mention in the House again, is the RCS Scheme.

(1505/RCP/CP)

The RCS-UDAN Scheme was a total game changer for the civil aviation market in the country. We should all be proud of the great vision that hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji had to create the scheme back in 2016 itself. I take great pride in speaking about the RCS-UDAN Scheme which is a

regional connectivity scheme, *Ude Desh Ka Aam Nagrik*, and some of the success stories this has created. I could see the positivity of most of the Members who have spoken yesterday also. They had been proudly speaking about the airports in their districts, airports in their constituencies and how they have increased, how they want more connectivity happening, and how they want the terminal capacity to increase. I would like to take certain examples. One example is the Darbhanga Airport. Darbhanga city is a very historical city. From the Maithili time, it is a very historic and historical city. It had one airstrip there which was running between 1950 and 1962. After 1962, there was no plane there. It was totally taken away from the civil aviation map of this country. When RCS came into play, when UDAN came into play – this was in 2020 – thereafter the airport was upgraded by spending Rs.120 crore under the UDAN Scheme. The first flight from Darbhanga took off on 9th November, 2020. It was in 2020 when the first flight took off. In the year 2022-23 – this was up to COVID-19 also – the airport handled six lakh passengers in the whole year. That was the kind of change the RCS has brought in for Darbhanga. There was no airport in Western Odisha. There was a huge interest from all the people of Western Odisha that they should have an airport. Before 2014, before the RCS scheme, there was nothing which was addressing this issue. But once the RCS was brought into place, even in the Jharsuguda Airport we have spent up to Rs.202 crore where we have created a new airport. Once that airport was brought in, the first flight took off in 2019. Now that terminal is handling two lakh passengers per year which is a great achievement for the Jharsuguda Airport. Then we have the Pithoragarh Airport, the Kalaburagi Airport, and the Kishangarh Airport. Examples are numerous. These come from all the cities, all the States and all the Union Territories of this country. So, this was the grand vision that Narendra Modi ji had where we are going to take up those remote areas where there is a lot of demand from people to travel through airplanes. That was when the RCS was promulgated and it was brought into effect. More than 500 routes have started under the RCS. More than 1.4 crore people of this country have travelled through the RCS routes. That is something which we all should be proud of.

Other than that, because of the success of the scheme, we are going to improve the scheme in the coming days. With the help of the Central Government, we are going to bring in the RCS again because it was a 10-year plan. Now, we are seeing that there are some issues. The RCS is specifically for three years because the way that scheme was done is that for three years, we are going to help a certain airport or a certain route to take off. It was not for a continuous time that the Government is going to provide the support. We wanted to create the impetus. We wanted to create the push and the spark. So, for three years, we were supporting. But now, a specific situation has arrived where after three years, the airlines sometimes are backing away from that route. That also has been expressed by a lot of people. So, we are going to address that issue. We have a process where after one year we can re-bid that route and we can restart that route through RCS. We need to extend the scheme of RCS because it has been a huge success and it has given a huge push to civil aviation also. So, definitely, we are going to look into expanding RCS also.

Other than that, in the area of civil aviation, just like how the interest is growing for having more airports and airlines, we want to have seaplanes also. That has been also a brainchild of Narendra Modi ji. He wants to see the seaplane industry also grow in this country. There was a certain policy which was made earlier. But we have taken industry feedback also on seaplane policy. They have requested for some changes. We have done those changes and very soon we are going to launch the new policy also. That is going to open up a whole new area of air travel. Wherever you have dams, wherever you have lakes, wherever you have sea connectivity, you can use the seaplane connectivity to connect those places. Again, it is going to create an alternate way of travelling. So, seaplanes are something we are looking at.
(1510/PS/SJN)

Now, I come to helicopters. If you look at the situation in India, you will find that the number of helicopters is very less as compared to the population, or the size of the country, that we have. A Brazilian city, Brasilia itself has more than 500 helicopters, and we are looking at 250-something helicopters in the whole country. So, there is a great opportunity to tap into the helicopter services in this country. What is the Ministry of Civil Aviation doing with regard

to the same? We want to encourage manufacturing of helicopters in the country. We are trying to push it. Like I have said, there is this state-of-the-art design element that is there in the Bharatiya Vayuyan Vidheyak, which is going to improve the setting up of plants, and it will also help in designing these helicopters. And once we have that network within the country, and if the States also support us, I am sure that that will be very fruitful.

I would specifically take the example of the State of Madhya Pradesh. The State is doing a wonderful job by connecting its religious and tourism circuits with helicopters. Now, with regard to medical tourism, Uttarakhand AIIMS has also put in one helicopter so that it can cater to the difficult terrain and unreachable areas in the State. So, there are a lot of services that helicopters can provide us. And we, on behalf of the Ministry of Civil Aviation, are strongly looking into this area. And with the help and support of the States, I am very sure that helicopter services are also going to increase manifold in the coming days.

Sir, I would especially like to thank hon. senior Member of the House, Rudy ji, who has spoken yesterday about the Bill. It is a homecourt advantage for him. Whenever there is a civil aviation matter, it is a homecourt advantage for him. He brings in all the experiences that he has. He has rightfully elevated the discussion that was happening yesterday, and I am very, very thankful to him for bringing in so much of knowledge.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): He is a pilot himself.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Yes, Sir, he is a pilot himself. We recognise it. The House recognises it. He has actually elevated the whole sense of the debate here. He has also enlightened us on how the civil aviation industry has originated in India, and how it has travelled through the years. He has specifically mentioned about the Aero Club of India. We take pride in the Aero Club of India. It provides all the services. In future, we are going to see how we can collectively use the wisdom of the Aero Club of India in the growth of civil aviation in this country, and I am definitely going to look into it personally also.

Sir, there were also some suggestions from the hon. Members with regard to air fares. I have already addressed that issue. We will form a specific team in the Ministry which will look into the issues with regard to air fares. Most

of the Members have talked individually about the airports in their States or the airports within their own constituencies. About 36 Members have spoken on this Bill, and the names of the airports that they have taken are more than 50. I would say that it is very difficult. Each individual airport has a specific -- I would not say a problem -- update, which I want to give to the hon. Members. So, if possible, I would extend an invitation to the hon. Members through this august House that whenever they have time, they can come and see me, so that I can sit with them and explain to them exactly what is the necessary thing that needs to be done regarding the airports. But on behalf of the Ministry, I would like to tell you that we are interested in building more airports. We want the infrastructure around the airports to increase. And the only challenge, a big challenge, that we find today is the availability of land. That is why, Sougata *Da* was speaking about it yesterday, and he was mentioning, क्या आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आपने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए, इतनी एयरलाइंस चल रही हैं? यह शो ऑफ की बात नहीं है। If we would not tackle the infrastructure problem today, it is going to be a huge challenge in the future. अगर आज हम एयरपोर्ट्स के इश्यू को सेटल नहीं करते हैं, आज तो हमें हर जगह लगेगा कि ये तो पिछड़ा इलाका है, यहां पर एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? यहां पर तो कुछ और बन सकता है। हम यहां पर किसी और चीज में पैसा लगा सकते हैं। But very soon, that place is going to need an airport, and when that airport requirement is there, you would not get any land. So, that is something which needs to be addressed today, and it has to be addressed by the States themselves.

An airport has got a great potential to drive a State and there are numerous examples like this. I can take the example of Shamshabad airport. Under the then Chief Minister, who is now also the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, Shamshabad airport was constructed in Hyderabad. He envisioned that. In Shamshabad village, 5000 acres of land were acquired. At that time, people were questioning, 'why do you need 5000 acres of land for the airport'? And today, if you look at it, after twenty-odd years, that 5000 acres of land are not enough right now for the services that that airport is requiring. This is the challenge which many big cities are facing today.

(1515/SMN/SPS)

If you see these places like Chennai, Mumbai, Kolkata, all of them are very tightly situated in small lands. We want to expand those airports but there is no land available. If you want to acquire more land, the price of the land has become so exorbitant that it is totally unviable to do expansion in those areas. So, I am advising all the Members here and also through you to the States that you represent that if you can focus on getting that land parcels today itself, you are going to create an airport infrastructure which is going to be useful for generations to come. It is very difficult tomorrow to address this land issue. Even yesterday when I was hearing the speeches, a lot of people have already mentioned how land acquisition is a problem.

Right now, if you want to take those areas for airport development, there is a lot of land acquisition problem just like anywhere else. So, we have to tackle this problem and from our side, whatever support is needed from the Central Government, we are going to provide just like we have done for the last ten years and we are committed to improve the airport infrastructure in this country under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi Ji and that is our commitment to all the States.

For Patna airport also, hon. Member has spoken about it. Land is with the State right now and whatever land the State provides, we first give the site clearance. We do a thorough inspection. Can an airport come here? Can it be viable? Can we build a proper runway where big flights, narrow body flights, wide body flights land easily? So, we do all these surveys and we give a site clearance. Once that is done, you go into land acquisition. So, wherever you have a request of a new airport, we see if there is a land parcel available or if there is air strip available. There is already a lot of research done from the Ministry of Civil Aviation but in case, if there is no update for you, you can handover to me again a request for that specific place. I will give you a specific update on the status of that site. With the cooperation from the State and Central Government, I can assure you if everything goes perfectly, we can very soon build an airport in that place. So, do not restrict yourself. If you have any place in mind, please let me know so that I can get it inspected and I am going to provide all support from the Ministry so that we can build airports there. That was regarding individual airports.

For connectivity also, there have been a lot of requests that we have an airport now and we want to improve that connectivity. Now, connectivity is a market driven exercise that is being done by the airlines. We do not have a specific rule or we do not have the specific power to say to the airlines that you just have to start this route from today. But through RCS, we have done a bidding process where these unconnected routes or unserved airports or underserved airports are all given certain viability gap funding so that the unconnected airports are connected. In that sense, if there is any airport which comes under the RCS category, then definitely, we are going to provide the support and ensure that proper connectivity is given and all other requests that you have – let it be for domestic flights or international flights – even though that is not the direct responsibility of the Government, we are trying through a favourable way to push the request to the airlines so that they can be considered as and when there is a possibility of considering them.

Sir, these are some of the main issues that were mentioned yesterday and other than this, I think any issue from any other Member that has been raised especially Sougata Da, he is not here, but one thing I take objection to what he has said.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): What about Buddhist circuit?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, your Buddhist circuit is also there. We are definitely going to sit with the State Government and do it.

If hon. Speaker Sir was there, I would have told him that we have given site clearance for Kota airport where he has been very strongly pursuing from his side also. … (*Interruptions*) यह शुरू होगा तो सबका एक-एक आ जाएगा। मैं सबका अलग से दे दूंगा।

HON. CHAIRPERSON: He is ready to invite any hon. Member.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Any grievances that you have regarding airlines or airfares, we are going to create a proper system where we have a team in the Ministry which is going to address all these issues. We are going to create a very efficient system where you can

provide us with all the details. If there is a specific airfare that you feel is very unreasonably hiked, you provide us on which website you have taken it, what was the timing of the plane and in which plane. If you can provide the details, we will do thorough research from our side. If there has been any misuse of the rights of the passengers, then we are going to take strict action also. We have done this earlier also.

(1520/SM/MM)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): What about land acquisition?

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): No, please. You kindly address the Chair.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, as I said, land is a State subject. If you feel that somewhere the cost is very high, it is up to the State to look for alternate land proposals. We are not saying that the airport should be restricted to only one specific area.

You can look at four or five areas and we can provide all the inputs as to where it can be feasible. If the land is very expensive in a certain portion, it is up to the State to look at other alternatives. Now, I would like to take the point of Prof. Sougata Ray.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): What about the Thoothukkudi Airport?

HON. CHAIRPERSON: Kanimozhi ji, this is not fair. Hon. Members have already raised their concerns and the hon. Minister is now responding to them. You can ask your question later on. When I allow you, you can ask a question.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I can say that I am very, very accessible to everyone. I am willing to meet anyone at any time and I will give them proper update.

HON. CHAIRPERSON: You can take cognizance of Kanimozhi ji.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Yes. Regarding Thoothukkudi Airport, I can say that a terminal building is being constructed there. You have also requested many times to speed up the process. Our Ministry is trying to push it up.

In Mumbai, the Navi Mumbai Airport will be a game changer airport for the whole Mumbai city. A lot of people have expressed concerns as to when it is going to open. The construction has been going on for a long time. I personally visited that airport and took a review of it. We have given a strict deadline that by 1st April, 2025 the first flight has to land and take off from there. We are ensuring that they are strictly following it. In many of the airports, we are trying to put a timebound deadline so that they complete their work and people can access all these airports.

Prof. Sougata Ray has mentioned that everything is getting privatised. एयर इंडिया आपने दे दिया है और अब किसी से सीट का अपग्रेड भी नहीं पूछ सकते हैं। वर्ष 2014 से पहले सिफारिश कल्चर होता था। इसी सिफारिश कल्चर के कारण एयर इंडिया का कर्ज 80 हजार करोड़ रुपये तक चला गया था। उसी की वजह से यह नुकसान हुआ और हमें एयर इंडिया को छोड़ना पड़ा।

Now, the Ministry of Civil Aviation does not get request for seat upgradation. We get request for upgradation of airports; we get request for upgradation of airport infrastructure; we get request for upgradation of facilities. So, we have raised the level of Ministry of Civil Aviation from just seat upgradation request to airports upgradation request. This has only happened because of the vision of the hon. Prime Minister Narendra Modi ji. We all are showing this commitment to the country.

There is lot of scope and potential especially in the MRO industry. I have replied in one of the answers about the growth of the MRO industry. From a two-billion-dollar industry, we have made it a four-billion-dollar industry in seven years. It also has great potential in job creation in the country.

So, a lot of different sectors in civil aviation are being looked upon. This Bharatiya Vayuyan Vidheyak encapsulates all of them and gives good direction. It harmonises all the SARPs which have been set by ICAO, a United Nations Agency for civil aviation. We are trying to maintain top standard globally. We do not just operate within ourselves but we set standards for the world itself.

So, we are considering the civil aviation sector a very promising one. I would like to personally thank hon. Prime Minister, Narendra Modi ji who has given the responsibility of handling the Civil Ministry to me at a very young age.

I did not have any expertise in the civil aviation sector. But he had the confidence on a young Member of this House. He has the vision that if it is in the hands of a young Minister, it will definitely touch the height. That is why, I want to thank the hon. Prime Minister.

I want to thank our leader, Shri Chandrababu Naidu also for giving me the opportunity. I also want to thank him on behalf of our Minister of State, Shri Muraleedharan. We both are young Ministers and we want to do a lot good things in civil aviation sector. Yesterday, hon. Members from both sides have spoken. They all have given a lot of support and encouraged us as young Ministers.

On behalf of the Ministry of Civil Aviation, I would like to thank all the Members of both sides. Everyone has supported us. With this kind of support, we are sure that we are going to reach number one position in the domestic aviation market in the whole world.

(1525/RP/YSH)

That is still our commitment. While I say that is our commitment, we are going to ensure that in whatever we do in this Civil Aviation Ministry, it is going to be addressed as ‘civilian aviation Ministry’. The civilian is going to be the topmost priority for us and that we are going to ensure, Sir. This Bill, the Bhartiya Vayuyan Vidheyak, plays a very important role. I request the whole House, just like they have supported through their speeches yesterday, to support in the passing of this important Bill which creates and gives a new direction for the civil aviation industry in the country.

With these words, I thank you, once again, for giving me the time.

(ends)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : प्रश्न यह है:

"कि वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात और निर्यात के नियंत्रण के विनियमन का और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving my Amendment No. 5, that is, DGCA's authority is being entrusted to 'an officer'. My amendment is that the officer should be not below the rank of a Secretary to the Government of India. Please accept it.

I beg to move:

"Page 2, line 39,-

after "an officer"

Insert "not below the rank of Secretary to the Government of India." (5)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Amendment No. 8 is also same, that, it is not below the rank of Additional Secretary to the Government of India in the same Clause. I am moving it.

I beg to move:

"Page 2, line 49,-

after "authority"

insert "not below the rank of Additional Secretary to the Government of India."

(8)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

'कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Amendment No. 9 is also same, that, it is not below the rank of Additional Secretary to the Government of India. I am moving it.

I beg to move:

"Page 3, line 1,-

after "other officer"

insert "not below the rank of Additional Secretary to the Government of India."

(9)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

'कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, Amendment nos. 10 and 11 are more or less of the same character. Since my other amendments are negatived, I am not moving them.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

'कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Amendment No. 12 is very important. This is an amendment to Clause 7. It is regarding the officer's qualification of the Aircraft Accident Investigation Bureau. Since it is a very sensitive post, the qualification should be not below the rank of the Director General of Police. That amendment can very well be accepted by the Government.

I beg to move:

"Page 3, line 47,-

after	"an officer"
Insert	"not below the rank of Director General of Police." (12)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

(1530/RAJ/NKL)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Adv. Dean Kuriakose to move Amendment No. 13 – not present.

Mr. N.K. Premachandran, are you moving Amendment No. 14?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving Amendment No. 14 as my earlier amendment is already negatived. So, there is no meaning in further moving it.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 10

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No. 15?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): No, Sir, I am not moving Amendment No. 15.

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you.

Prof. Sougata Ray to move Amendment Nos. 16 and 17 – not present.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 18

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray – not present.

Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No. 18?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, let me read the Amendment No. 18 to Clause 18. As per the existing provision, if the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for the safety of aircraft operations, direct that no building or structure shall be constructed or erected, or no tree shall be planted on any land within twenty kilometres of the radius. So, my suggestion is, let it be five kilometres.

Sir, I beg to move:

Page 9, line 14,-

for "twenty"

substitute "five". (18)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray to move Amendment No. 19 – not present.

Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No. 20?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): No, Sir, I am not moving Amendment No. 20.

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray to move Amendment No. 21 – not present.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

Clause 22

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray to move Amendment No. 22 – not present.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is time for the Private Members' Business. … (*Interruptions*)

श्री हैबी ईडन (एरनाकुलम) : सर, प्राइवेट मैम्बर बिल … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सर, प्राइवेट मैम्बर बिल्स इस बिल के पास होने के बाद लिए जाएंगे। इस बिल पर खंडवार विचार हो रहा है। श्री हैबी ईडन जी, this is your third term. You should be aware of the rules. We will take it up later on.

प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 23 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

Clause 26

HON. CHAIRPERSON: Shri Kodikunnil Suresh, are you moving Amendment No. 23?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 12, line 24,-

after "aircraft"

insert ", drone, manned or unmanned aerial vehicle, remote controlled or radio controlled airborne vehicles". (23)

माननीय सभापति : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा खंड 26 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : प्रश्न यह है

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 27

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray to move Amendment No. 24 – not present.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray to move Amendment No. 1 – not present.

Shri N.K. Premachandran ji, are you moving Amendment No. 2?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is very important. The hon. Minister had replied to my query yesterday also. I had raised this issue at the time of introduction of the Bill also. Article 348(1)(b) mandates that the text of the Bill shall be in English. So, I am insisting on that, and I am moving the amendment.

I beg to move:

Page 1, line 5,-

for "Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024"

substitute "Indian Aircraft Act, 2024". (2)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

(1535/KN/VR)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Mr. Vishaldada Prakashbapu Patil, are you moving your Amendment No. 3?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, this is similar to the amendment given by Prof. Sougata Ray. So, I am not moving my amendment.

HON. CHAIRPERSON: Shri Dean Kuriakose ji to move Amendment No.4– not present.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1537 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up the Private Members' Business.

Shri Manish Tewari.

INTELLIGENCE SERVICES (POWERS AND REGULATION) BILL

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the manner of the functioning and exercise of powers of Indian Intelligence Agencies within and beyond the territory of India and to provide for the coordination, control and oversight of such agencies.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आसूचना अभिकरणों के भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर और उससे परे कार्यकरण की रीति और शक्तियों के प्रयोग को विनियमित करने तथा ऐसे अभिकरणों के समन्वय, नियंत्रण और अन्वेक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 80, etc.)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of article 324, etc.)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Sir, I introduce the Bill.

विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र के युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, राष्ट्रीय एकता और तैयारी के संवर्धन के लिए विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र के युवाओं में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, राष्ट्रीय एकता और तैयारी के संवर्धन के लिए विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

आयकर संग्रहण दृश्यात्मक निरूपण विधेयक

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के करदाताओं से संग्रहित आयकर के सुगम्य एवं पारदर्शी रीति अनुसार दृश्यात्मक निरूपण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि देश के करदाताओं से संग्रहित आयकर के सुगम्य एवं पारदर्शी रीति अनुसार दृश्यात्मक निरूपण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(1540/VB/SAN)

ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स (विनियमन और मूल्य नियंत्रण) विधेयक

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मधुमेह के प्रबंधन में सुधार करने और सभी लोगों के लिए ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत में ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स के विनिर्माण, वितरण और मूल्य निर्धारण में एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : प्रश्न यह है:

> "कि मधुमेह के प्रबंधन में सुधार करने और सभी लोगों के लिए ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारत में ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स के विनिर्माण, वितरण और मूल्य निर्धारण में एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

....

HON. CHAIRPERSON: DR. D. RAVI KUMAR – not present.
SHRI K. SUDHAKARAN – not present

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of section 3 and Schedule II*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I introduce the Bill.

ASHA WORKERS (REGULARISATION OF SERVICE AND OTHER BENEFITS) BILL

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regularisation of the services of ASHA workers and conferring the status of permanent employee of the Government and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण और उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I introduce the Bill.

ANGANWADI WORKERS (REGULARISATION OF SERVICE AND WELFARE) BILL

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the regularisation of the services of Anganwadi Workers and conferring the status of not less than those of Group 'C' employee of the Central Government on such Anganwadi Workers.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का नियमितीकरण करने और ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सरकार के समूह 'ग' कर्मचारियों से अन्यून दर्जा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I introduce the Bill.

BACKWARD AREAS DEVELOPMENT BOARD BILL

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of a Board for speedy development of backward areas and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

BAN ON ENTRANCE EXAMINATION IN PROFESSIONAL COURSES BILL

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for ban on entrance examinations to all professional courses in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि देश के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

OVERSEAS WORKERS (WELFARE) BILL

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare of Indian Citizens employed outside the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि देश के बाहर नियोजित भारतीय नागरिकों के कल्याण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

QUALITY EDUCATION (ENHANCING THROUGH INTERNSHIP) BILL

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to enhance the quality of education in professional and technical courses by providing mandatory structured internships to the students, providing basic remuneration under the internship and establishing a national-level platform for internship application and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि छात्रों को अनिवार्य संरचित इंटर्नशिप प्रदान करके व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, इंटर्नशिप के तहत मूल पारिश्रमिक प्रदान करने और इंटर्नशिप आवेदन के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच स्थापित करने और उससे जुड़े मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Sir, I introduce the Bill.

(1545/PC/SNT)

SOLID WASTE MANAGEMENT BILL

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the segregation and re-cycling of municipal solid waste, use of re-cyclable waste in waste-energy plants for generation of energy and transportation of non-recyclable waste into landfills and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : प्रश्न यह है:

> "कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रीकरण, अपशिष्ट-ऊर्जा संयंत्रों में पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्ट का ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोग करने तथा गैर-पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्ट का अपशिष्ट भराव-क्षेत्र तक परिवहन एवं उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF TAMIL NADU BILL

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Tamil Nadu for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as housing, drinking water, roads, sanitation, creation of grain and fodder banks, skill development, cloud seeding contour bunding and welfare schemes for the women, children, senior citizens and people living below poverty line in the State and for encouraging traditional water conservation through lakes, ponds, wells, rainwater harvesting and afforestation and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि तमिलनाडु राज्य में आवासन, पेयजल, सड़क, स्वच्छता, अनाज और चारा बैंकों का सृजन, कौशल विकास, क्लाउड सीडिंग, कंटूर बंडिग जैसी विकासोन्मुख अवसंरचना के सतत् और संतुलित विकास और महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तथा झीलों, तालाबों, कुओं, वर्षा जल संचयन और वनीकरण के माध्यम से पारंपरिक जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of article 58)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : आइटम नंबर 38, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत – उपस्थित नहीं।

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new sections 10A and 10B)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I introduce the Bill.

(1550/AK/CS)

FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 3, etc.)

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS IN THE STATE OF TAMIL NADU BILL

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Tamil Nadu to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains situated in the State of Tamil Nadu.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि तमिलनाडु राज्य में स्थित नवीन पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों के उत्खनन सहित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों की मरम्मत, नवीकरण एवं परिरक्षण की लागत को पूरा करने के प्रयोजनार्थ तमिलनाडु राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I introduce the Bill.

ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new section 90A).

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, I introduce the Bill.

विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि युवाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के प्रयोजनार्थ कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन तथा युवा अधिकार रक्षक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से युवा आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि युवाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के प्रयोजनार्थ कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन तथा युवा अधिकार रक्षक के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से युवा आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : महोदय, **:** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

VICTIMS OF NATURAL LIGHTNING DISASTER (COMPENSATION) BILL

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and compensation to the victims of lightning strike disaster and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि आकाशीय बिजली आपदा पीड़ितों का पुनर्वास और प्रतिकर तथा उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I introduce the Bill.

HIGH COURT OF KERALA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT PALAKKAD) BILL

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Permanent Bench of the High Court of Kerala at Palakkad.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि केरल उच्च न्यायालय की पलक्कड़ में एक स्थायी पीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I introduce the Bill.

ALL INDIA INSTITUTES OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new section 3A).

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the All India Institutes of Medical Sciences Act, 1956.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I introduce the Bill.

(1555/IND/UB)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आइटम-48, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल – उपस्थित नहीं।

जैविक कृषि संवर्धन विधेयक

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को उजागर करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को उजागर करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हू।

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL

(Insertion of new section 5A, etc.)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I introduce the Bill.

AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I introduce the Bill.

AIRLINES PASSENGER SERVICES AUTHORITY BILL

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish the Airlines Passenger Services Authority of the protection of passenger rights in airlines and to provide compensation for flight delay, cancellation, denied boarding and baggage lost or damage and to regulate the rights of frequent travellers in India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि एयरलाइनों में यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एयरलाइन यात्री सेवा प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उड़ान में विलंब, रद्दीकरण, बोर्डिंग से मना किए जाने व सामान खो जाने अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा प्रदान करने व भारत में प्राय: यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकारों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I introduce the Bill.

प्ले स्कूल (विनियमन) विधेयक

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्ले स्कूलों के कार्यकरण का विनियमन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि प्ले स्कूलों के कार्यकरण का विनियमन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अनाथ (सरकारी स्थापनों में पदों का आरक्षण और कल्याण) विधेयक

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थापनों में अनाथों के लिए पदों का आरक्षण तथा कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी स्थापनों में अनाथों के लिए पदों का आरक्षण तथा कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविकाओं में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि कृषि तथा अन्य ग्रामीण उपजीविकाओं में नियोजित ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

1559 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

COMMISSION FOR REGULATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY BILL

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 58, श्री सी. एन. अन्नादुरई।

1559 hours

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I beg to move:

> "That the Bill seeking to provide for the setting up of a Commission to regulate and promote the development of Information Technology industry in the country and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

(1600/SRG/RV)

The Commission shall consist of a Chairperson and four other members to be appointed by the Union Government having such qualifications as may be prescribed.

Information technology is the gateway of all future developments, be it education, healthcare, agriculture, sports, bio-diversity, safety and security etc. The Tamil Nadu Government is taking care to enrich capacity building in Information Technology each year and spread awareness in e-governance and mobile-governance. It will open opportunities for employment generation for scientists, techno-experts and other managerial jobs. All socio-economic development growth and civilizational march will depend upon direction of information technology based on Artificial Intelligence.

The Commission shall take appropriate steps to set up information technology parks in cities with population of more than one million and in cities having potential for development of information technology parks. Information technology industry is one the fastest growing industries of the country. There is

tremendous potential for further growth of this industry, Therefore, we require more investment. The Chief Minister of Tamil Nadu is making all-out efforts for attracting and encouraging more investment in the IT industry in Tamil Nadu. This industry can prove to be a major source of revenue for the Government. There is huge scope to tap the growth potential of the information technology industry. It is also proposed that a national policy on information technology be formulated. This Bill will pave the way for socio-economic development of various States of the country, especially the developing States including the State of Tamil Nadu.

I take this opportunity to announce that our hon. Chief Minister of Tamil Nadu aims to make the State a trillion dollar economy and global human capital hub through IT industry. The Tamil Nadu Government is already fostering entrepreneurship related to IT and establishing IT parks in the State.

Thank you.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> “कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास का विनियमन और संवर्धन करने के लिए आयोग की स्थापना करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

1603 बजे

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं, सी.एन. अन्नादुरई साहब द्वारा लाए गए बिल के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सर, यह बिल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बिल में उन्होंने अपनी जो आशंका जाहिर की है, उस आशंका के मूल में वह बात नहीं है। बिल में उन्होंने एक आशंका जाहिर की, जिसके लिए उन्होंने एक रेमेडी दी। वे कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से विकास हो रहा है, उसमें अगर कोई इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो वह आई.टी. इंडस्ट्री है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को और खासकर इस सदन को बताना चाहता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप होती है, वह 50 साल, 100 साल के बारे में सोचती है, जो कि आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी सोचते हैं और उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' का उनका संकल्प पूरा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती थी कि आई.टी. इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली है। इस पार्लियामेंट में बड़ी चर्चा होती है कि 'ब्रेन ड्रेन' हो गया, कितने लोग विदेश चले गए, कितने लोग यहां आ गए, कितने बच्चे पढ़ते हैं। अमेरिका की पूरी सिलिकॉन वैली को भारतीय मूल के लोग कंट्रोल करते थे। वहां भारत का पूरा दबदबा था। हम खुश होते थे कि भारत की आई.आई.टी. से पढ़े हुए लोग, हमारे पैसों से पढ़े हुए लोग, भारत में सुविधा नहीं मिलने के कारण अमेरिका चले गए और वे वहां बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ी कम्पनी बना रहे हैं। लेकिन, उसके बावजूद भी तत्कालीन भारत सरकार ने, अगर ऑपोजीशन पार्टी का नाम लूंगा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन मैं 'तत्कालीन भारत सरकार' कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कभी भी इसके बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया।

(1605/GG/RCP)

अध्यक्ष जी, और तो और आपको जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि वर्ष 1996 में डब्ल्यूटीओ में हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया और उसके कारण जो देश की समस्या है, आज जो बेरोज़गारी नज़र आ रही है, आज कानून में, पीएमएलए से ले कर, वह केवल और केवल चिदंबरम साहब की देन है। वे डब्ल्यूटीओ में गए और उन्होंने साइन कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं, आईटी के सामान हैं, कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनमें ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। उसके कारण हमारे खिलौने का पूरा का पूरा उद्योग खत्म हो गया, आईटी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, मोबाइल की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। साथ

ही, वर्ष 1996 के पहले भारत जो एक्सपोर्ट करता था, वह एक्सपोर्ट पूरा का पूरा बंद हो गया और पूरा का पूरा भारत चाइनीज़ मार्केट बन गया। वर्ष 1996 में उस एग्रीमेंट को साइन करने के कारण आज भी भारत सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी जब से प्रधान मंत्री बने हैं, वर्ष 2014 से हमारी सरकार वर्ष 2024 तक जूझ रही है कि उस एग्रीमेंट को बायपास करते हुए हम अपने यहां की इंडस्ट्री को, अपने यहां के ब्रेन को, हमारे यहां की टैक्नोलॉजी को, हमारे यहां के जो लड़के पढ़े-लिखे हैं, उनको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकें। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सकारात्मक कर सकें।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, सकारात्मक कैसे होगा, जब 'रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए'? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज आप सकारात्मक बोल लो, बाकी फिर कभी और बोल लेना

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज स्टार्ट अप के नाते, स्टैंड अप के नाते, पीएलआई स्कीम के नाते और सबसे बड़ा जो सवाल है, एसटीपीआई के नाते, सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो बना है, वह छोटी-छोटी जगहों पर बना है। क्योंकि जो टैलेंट है, वह वहीं ज्यादा है। चाहे भारत में खेल का टैलेंट हो, अन्य क्षेत्रों में योग्यता, क्षमता का टैलेंट हो, चाहे इस पार्लियामेंट में आने वाले लोगों का टैलेंट हो, आप जानते हैं कि हम और आप भी छोटी जगह से आ कर, आप लोक सभा अध्यक्ष हैं और मैं चौथी बार यहां सांसद हूँ और पार्टी मुझे इतना मौका देती है, तो जो छोटी जगहों के लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा सेटअप किया, जिसका नाम एसटीपीआई है। … (व्यवधान) मैं गोड्डा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ, जो कि एसप्रेशनल जिला है, वहां भी एसटीपीआई की यूनिट है। मेरे यहां बोकारो एक छोटी सी जगह है, वहां भी एसटीपीआई की यूनिट है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब माननीय प्रधान मंत्री जी आ गए हैं तो मैं अगली बार बोलूंगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हम आपको अगले सत्र में बोलने का मौका देंगे।

विदाई संबंधी उल्लेख

1609 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोक सभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। यह सत्र 22 जुलाई, 2024 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में, हमने 15 बैठकें की, जो लगभग 115 घंटे और 21 मिनट तक चलीं।

दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट, 2024-25 पेश किया गया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट, 2024-25 पर सामान्य चर्चा 27 घंटे 19 मिनट तक चली। इस चर्चा में 181 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 30 जुलाई 2024 को चर्चा का उत्तर दिया

सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों, 2024-25 पर 30 जुलाई, 2024 से 5 अगस्त, 2024 तक चर्चा की गई और चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया।

(1610/MY/PS)

दिनांक 5 अगस्त, 2024 को केन्द्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा कुल 4 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुल महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित हैं, वित्त विधेयक, 2024; विनियोग विधेयक, 2024; जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024; और भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 ।

सत्र के दौरान 86 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 400 मामले उठाए। सभा में नियम 377 के अधीन 358 मामले उठाए गए। निदेश 73क के अधीन 25 वक्तव्य, सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 2 वक्तव्य और नियम 372 के अधीन माननीय मंत्रियों द्वारा तीन 'सुओ मोटो स्टेट्मेन्ट' सहित कुल 30 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान कुल 1345 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया।

इस सत्र के दौरान, दिनांक 22 जुलाई, 2024 को ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों के संबंध में नियम 193 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा हुई। दिनांक 31 जुलाई, 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल के नुकसान के विषय पर नियम 197 के अधीन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया गया।

सत्र के दौरान 65 गैर सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की बात करें तो देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए

उचित उपायों के विषय पर श्री शफी परम्बिल द्वारा प्रस्तुत एक संकल्प को सदन द्वारा चर्चा के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2024 को लिया गया। हालाँकि, इस संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

लोक सभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 136 प्रतिशत रही। सत्र के दौरान सभा ने दिनांक 23 जुलाई, 2024 को तंजानिया संयुक्त गणराज्य की स्पीकर एवं IPU की अध्यक्ष श्रीमती तुलिया एक्सन का स्वागत किया गया। दिनांक 1 अगस्त, 2024 को जापान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी हार्दिक स्वागत किया।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ।

इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गयी समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोक सभा सचिवालय के महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सम्बद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, कृपया अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम "वन्दे मातरम्" की धुन बजाएंगे।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

1614 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।